[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part -I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link https://sansad.in/rs/debates/officials]

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at two of the clock,
(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*)

GOVERNMENT BILL

[$]The Banking Laws (Amendment) Bill, 2025

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, further consideration on the motion for consideration of the Banking Laws (Amendment) Bill, 2024 moved by Shri Pankaj Chaudhary on the 9th December, 2024. Shri Shaktisinh Gohil to initiate the discussion.

श्री शक्तिसिंह गोहिल (गुजरात): माननीय उपसभापति महोदय, आज वित्त मंत्री जी The Banking Regulation, Act के 5 कानूनों में amendment करने जा रही हैं। एक जमाना था, जब बैंक में सिर्फ पूंजीपति जा सकते थे और अगर कोई किसान या कोई गरीब बैंक के दरवाजे पर देखा भी जाता था, तो उसे शक की निगाहों से देखा जाता था। वह इंदिरा गांधी जी ही थीं, जिन्होंने बैंकों का nationalisation करने के बाद यह कह दिया कि बैंकों के दरवाजे आम हिंदुस्तानी के लिए खुले हैं और चाहे कोई किसान हो या कोई गरीब हो, वह भी बैंक के अंदर जा सकता है। बैंकों में वह काम अगर शुरू हुआ, तो nationalisation के बाद शुरू हुआ। मैं आपके जरिए वित्त मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि आप कानून बदलने के साथ, अपने Statement of Objects and Reasons में - आपकी मंशा पर मुझे कोई शक नहीं है, परंतु जो लोग आपके साथ बैठते हैं, जो लोग administration चलाते हैं, आप कितना भी कानून बदलें, जब तक उसको implement करने करने वालों की मंशा साफ नहीं होगी, कानून बदलने से कुछ नहीं होगा, इसका implementation करने वालों की नीयत को ठीक करना होगा। कानून संविधान से बनता है और संविधान का आर्टिकल-14 कहता है - 'Equality before Law.' कानून सबके लिए समान होना चाहिए, यह हमारा संविधान कहता है, परन्तु यहां क्या होता है? उपसभापति महोदय, एक कानून वह होता है कि जिसे सामने वालों के लिए इस तरह से politically उपयोग करो कि उसे खत्म करो और जैसे ही अपने पास आ जाए, वह आर्टिकल-14 नहीं रहता है, 'Equality before Law' नहीं रहता है, वह कानून बदल जाता है। अगर वह सामने है, तो कहता है कि वह बहुत बड़ा

[$] Further consideration continued on a motion moved on the 9th December, 2024.

क्रिमिनल है, उसने fraud किया है, अब वह जेल जाएगा - चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग और जैसे ही जगह बदलकर वह इधर आ जाएगा, तो power seeking, power seeking हो जाएगा और उसको सब मिलता रहेगा। तो कानून अलग-अलग नहीं होना चाहिए, कानून सबके लिए समान होना चाहिए।

उपसभापति महोदय, इसी Bill के अंदर एक Amendment आ रहा है। वह amendment क्या आ रहा है? Co-operative banks के अंदर Director का tenure 8 साल का है, जो इसी सरकार ने किया था, कुछ ही वक्त पहले किया था। अपनी political power बचाने के लिए, political equation के साथ, कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आपने कहा कि co-operative bank में Director 8 साल ही रह सकता है। आप अब क्या amendment ला रहे हैं? अब ये इस नए amendment के साथ यह चीज ला रहे हैं कि अब co-operative bank में Director 10 साल तक रहेगा। जब आपने उसके लिए 8 साल का कानून बनाया था, उसी वक्त गुजरात में The Panchsheel Mercantile Co-operative Bank Ltd. में – सर, वहां के जागरूक नागरिकों ने Reserve Bank of India को खत लिखा कि banking law कहता है कि वहाँ Director 8 साल से ज्यादा नहीं रह सकता है। उपसभापति महोदय, उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट के Co-operative Department को खत लिखा। मेरे पास संदीप मांगरोला नाम के एक नागरिक का यह खत है। गुजरात गवर्नर आरबीआई को लिख कर भेजती है कि हमें यह पत्र मिला है, पर इसका implementation तो आरबीआई को करना है। पंचशील मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में डायरेक्टर के 8 साल से ऊपर हो गए हैं, इसलिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इसको कानून के तहत decide करे। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड नहीं किया। उसने बार-बार लिखा कि ऐसे बहुत सारे कोऑपरेटिव्स के, शुगर के सारे डायरेक्टर्स की अवधि 8 साल पार कर गई है, मैं उनका डिटेल दे रहा हूँ, मुझे आप समय दीजिए। जब उसने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर यह मुझे भेजा, तो मैंने आरबीआई को लिख कर भेजा कि आप इससे मिलिए तो सही। कानून के खिलाफ काम हो रहा है और उसके लिए एक नागरिक अपनी बात रख रहा है, लेकिन आप उसको मिलने का टाइम नहीं देते हैं, जवाब नहीं देते हैं। दुख है कि आरबीआई ने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी जवाब नहीं दिया। वित्त मंत्री जी, क्या आप रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर कुछ कहेंगी या नहीं? आज यह पार्टी पावर में है, कल वह होगी, लेकिन डेमोक्रसी में इलेक्टेड मेंबर जनता का प्रतिनिधि होता है, उसके लिए कोई भी ऑफिसर हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में हो..., आज हम लिखते हैं, लेकिन आपके डिपार्टमेंट से कोई जवाब तक नहीं आता है। चाहे हम कुछ भी लिखें। एक वक्त था, जब टाइम के अनुसार जवाब देना होता था। इस संबंध में यहाँ से गवर्नमेंट के द्वारा निकाला गया एक सर्कुलर है, जिसके अनुसार in stipulated time मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जवाब देना चाहिए, preliminary reply इतने दिनों में और आखिरी रिप्लाई interim reply के इतने दिनों के बाद देना चाहिए। लेकिन Finance Department या रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल किसी को गिने ही नहीं। मैं मानता हूँ कि इसके लिए वित्त मंत्री जी अपने डिपार्टमेंट को जरूर ठीक करेंगी। पहले यह किया गया कि किसी भी बैंक में कोई एक डायरेक्टर 8 साल से ज्यादा समय तक नहीं रह सकता है, लेकिन अब यह अमेंडमेंट आ रहा है कि वह 10 साल तक रह सकता है। चूँकि हमारे यहाँ कहा जाता है that charity begins from home. आपने जिसको सहकारिता मंत्री बना कर रखा है, जिनके पास

कोऑपरेटिव विभाग है, माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके जरिए जरूर कहूँगा कि कम-से-कम वे जिस बैंक में चेयरमैन रहे थे, वहाँ तो कानून लागू होना चाहिए। [] उपसभापति महोदय, वह क्यों कोर्ट में पेंडिंग है? वह इसलिए कोर्ट में पेंडिंग हैं, क्योंकि दो डायरेक्टर्स के एक गुट...

श्री उपसभापतिः जो मैटर कोर्ट में पेंडिंग है..., आप बड़े अनुभवी आदमी हैं।...(**व्यवधान**)...

SHRI SHAKTISINH GOHIL: I am not yielding. ...*(Interruptions)*... No, I am not criticizing the court. Whatever matter it is, it is my right to say. And that is why I want to highlight it. The matter is *sub-judice*.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes.

SHRI SHAKTISINH GOHIL: I am not going into the merits of the matter. What I want to say is, it is the duty of the Government to see to it. Otherwise,दो लोग मिल कर कोर्ट चले जाएँगे, तारीख पे तारीख पड़ती रहेगी और क्या सरकार देखती रहेगी? इसीलिए मैं कहता हूँ कि it is the duty of the RBI कि वह party intervener के तौर पर वहाँ जाए, party intervener के तौर पर सरकार उसमें हस्तक्षेप करे। [£] आप उन Directors को हटाइए।...(**व्यवधान**)... यह आपका पावर है, इसलिए आप उसको कीजिए।...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः प्लीज़, प्लीज़।...(**व्यवधान**)...

श्री शक्तिसिंह गोहिलः आप वहाँ administrator को लगा सकते हैं।...(**व्यवधान**)...

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT; AND THE MINISTER OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (DR. MANSUKH MANDAVIYA): Sir, ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।...(**व्यवधान**)...

SHRI SHAKTISINH GOHIL: I am not yielding. ...*(Interruptions)*... I am not yielding. ....*(Interruptions)*...

श्री उपसभापतिः माननीय मंत्री जी, इनके बाद मैं आपको मौका देता हूँ। He is not yielding. ...*(Interruptions)*... इनके बाद मैं आपको बोलने का मौका देता हूँ।...(**व्यवधान**)...

डा. मनसुख मांडविया : सर, इसको कार्यवाही से निकालना चाहिए।

[£] Exupnged as ordered by the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will do. ...*(Interruptions)*...

श्री शक्तिसिंह गोहिल: माननीय उपसभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि चूँकि उसमें इस तरह से चल रहा है, इसलिए वहाँ पर administrator लगाने की जरूरत है और उन डायरेक्टर्स को हटाया जाए, जो आपके कानून के खिलाफ 2006-07 से 2024 तक बैठे हैं। आप उनको हटा कर वहाँ पर administrator लगा दीजिए और नया चुनाव करा लीजिए। उसके बाद फिर शेरहोल्डर्स चुनेंगे। जो लोग आएँ, वे काम करें। I am not against it. डेमोक्रेसी में अगर हम हारते हैं, तो हार स्वीकार करते हैं और अगर जीतते हैं, तो काम करते हैं, पर चुनाव ही न होने दो, यह किस तरह का है? वह भी वहाँ, जहाँ पर सहकारिता मंत्री खुद चेयरमैन रहे हों, आज वे ही यहाँ सरकार में हों और वहाँ पर यह हो रहा है। अगर किसी को बुरा लगे तो लगे, किसी को अच्छा लगे, यह कहने की जरूरत मेरी नहीं है। जो सच बात है, वह कहने की मेरी आदत है, फिर सच किसी को अच्छा भी न लगे, तो उनको मुबारक!

उपसभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि fanindia.net पर पूरी डिटेल के साथ जो हकीकत दी गई है, उसके मुताबिक, इस सरकार ने वर्ष 2024 तक 50 विलफुल डिफॉल्टर्स के 87,000 करोड़ माफ किए। इसमें कौन हैं? मेहुल चोकसी, ऋषि अग्रवाल जैसे लोग भी इसके अंदर हैं। ये हमारे देश को लूटकर बाहर जाने वाले लोग हैं, आप उनका कर्जा माफ करते हो। आप गरीब, किसान, छोटे दुकानदार के यहाँ तो ऑक्शन करने पहुंच जाते हो और यहां पर उनका आपने माफ किया।

सर, मैं आपके जरिए इस गृह में यह कहना चाहता हूँ कि मेहुल चोकसी हमारे देश को लूटकर बाहर भाग गया, उसको रोक सकते थे। मेरे हाथ में यह एक affidavit है। हाई कोर्ट के अंदर एक Criminal Civil Application 4758/2015 दायर की गई। जब वहां यह petition लगी, तब वहां Respondent एक Affidavit file करता है और उसमें वह लिखता है कि मेहुल चोकसी बहुत बड़ा फ्रॉड है। उसका शेयर 650 रुपये से 13 रुपये हो गया है। इसने सिर्फ बैंकों को ही नहीं, गरीब लोगों से 14 प्रतिशत इंटरेस्ट देने के नाम पर, गोल्ड बार के नाम पर पैसे लिए हैं। देश की जनता के ...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापति: धन्यवाद।

श्री शक्तिसिंह गोहिल: सर, एक मिनट और दे दीजिए, मैं खत्म करता हूँ।

श्री उपसभापति: एक मिनट नहीं, आप जल्द खत्म करें।

SHRI SHAKTISINH GOHIL: I will say just last three lines and conclude. In this Affidavit, he had written, 'I would also like to draw kind attention to the fact that the Petitioner has a huge debt of Rs.9,870 crores outstanding which also specified in the website of the Ministry of Corporate Affairs,' and, उसके साथ वह उसकी कॉपी लगाता है।

Petitioner कहता है कि 'Like Vijay Mallya, Mehul Choksi भाग जाएगा। उसकी वाइफ का दुबई में फ्लैट भी है।' साहब, वह कब कहता है? उसने यह 18 महीने पहले कहा था। ...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापति: धन्यवाद। अब आप खत्म कीजिए, मैं अगले स्पीकर को बुलाऊंगा।

श्री शक्तिसिंह गोहिल: अगर मेहुल चोकसी को पकड़ लेते, तो वह बाहर नहीं जा सकता था। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. शक्तिसिंह जी, आप बड़े अनुभवी हैं। आपकी तकरीर में जो भी संसदीय शब्द नहीं होंगे, वे रिकॉर्ड पर नहीं जाएँगे। माननीय मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहते थे। आप कुछ intervene करना चाहते थे।

डा. मनसुख मांडविया: डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर [£] जैसे शब्दों का बिना किसी authentication के प्रयोग करना उचित नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: जो भी असंसदीय शब्द हैं, उनके बारे में मैंने कह दिया है। जो भी असंसदीय शब्द होंगे, उनको हम examine करेंगे और उन पर उचित कार्रवाई करेंगे। I have already told. ...(**व्यवधान**)... कृपया आपस में बातचीत न करें। माननीय अरुण सिंह जी।

श्री अरुण सिंह (उत्तर प्रदेश): डिप्टी चेयरमैन सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र अपनी बात कह रहे थे, तो मैं अपनी बात की शुरुआत इससे करूँगा कि मेरे पास बहुत सारे articles और newspapers की cuttings हैं, जो कहती है 'NPA crisis could be the Congress-led UPA's biggest scam' जैसे दर्जनों articles और editorials से भरे हुए हैं। कांग्रेस ने अपने समय में जो काली करतूतें की हैं, उसको पहले वे देखनी चाहिए। Basically, Sir, the Banking Law (Amendment) Bill, 2024 में पाँच Acts में संशोधन किया गया है, क्योंकि ये सभी Acts एक-दूसरे से interconnected हैं। The RBI Act, 1934, the SBI Act, 1955, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act,1980. सहित विभिन्न अधिनियमों में संशोधन किया गया है। ये संशोधन इस उद्देश्य से किए गए हैं कि हमारे डिपॉजिटर्स को अधिक सुविधा मिले, स्टेकहोल्डर्स को फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में अधिक पारदर्शिता मिले और गवर्नेंस में सुधार हो।

यदि हम बैंकिंग प्रणाली को देखें, तो यह हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और इसके बिना आर्थिक गतिविधियों का संचालन करना अत्यंत कठिन है। कांग्रेस के शासनकाल में

[£] Exupnged as ordered by the Chair.

रोटी, कपड़ा और मकान का नारा दिया जाता था, जिसमें घर-मकान में भी स्कैम होता था, लेकिन जब 2014 में माननीय प्रधान मंत्री जी ने पदभार ग्रहण किया, तो उन्होंने रोटी, कपड़ा और मकान के साथ इसमें बैंकिंग को भी जोड़ा और फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्राथमिकता दी।

बैंकों के कर्मचारी भी वही थे और अधिकारी भी वही थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से आह्वान किया कि देश के हर नागरिक का बैंक खाता होना चाहिए, चाहे वह कितने ही दूर-दराज के क्षेत्र में क्यों न रहता हो। परिणामस्वरूप, आज 54 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। अब देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका बैंक खाता न हो।

इन 54 करोड़ खाताधारकों को दुर्घटना बीमा और रूपे कार्ड जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। इससे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन का उदाहरण और क्या हो सकता है? बैंकिंग व्यवस्था में सुगमता, सरलीकरण और व्यापकता को देखते हुए पिछले 10 वर्षों में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं।

अब जो अमेंडमेंट लाया गया है, उसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को भी सुव्यवस्थित किया गया है। पहले अल्टरनेट फ्राइडे को रिपोर्टिंग की जाती थी, जिससे कभी-कभी किसी महीने के कुछ दिन की रिपोर्टिंग छूट जाती थी। अब प्रावधान किया गया है कि महीने की पहली 15 दिनों की रिपोर्टिंग उस अवधि के अंत में होगी, और बाकी 15 दिनों की रिपोर्टिंग महीने के अंत में होगी। इससे तुलनात्मक अध्ययन बेहतर होगा, अकाउंटेंसी में सुधार आएगा और यह प्रक्रिया स्टैंडर्डाइज्ड हो जाएगी, क्योंकि सभी क्षेत्रों में इसी प्रकार से फाइनेंशियल क्लोज़र किया जाता है, तो यह Reserve Bank of India को भेजी जाने वाली रिपोर्टिंग प्रणाली में बदलाव किया गया है।

महोदय, अभी तक हमारे जो depositors हैं, वे एक नॉमिनी का नाम दे सकते हैं कि अमुक व्यक्ति हमारा नॉमिनी होगा। कभी-कभी यह देखने में आया कि अकाउंट होल्डर और नॉमिनी दोनों का एक साथ निधन हो गया, तो मामला लिटिगेशन में चला जाता था कि कौन इसका असली वारिस है। अब इस बिल के माध्यम से nominee up to four — अब वे उसमें simultaneous or sequential nominee कर सकते हैं, जिससे लिटिगेशन कम होगा और कानूनी उत्तराधिकारी को तुरंत भुगतान मिल सकेगा। पहले कोर्ट में जाना होता था और इस प्रक्रिया में वर्षों लग जाते थे, लेकिन इस संशोधन से करोड़ों डिपॉजिटर्स को सीधा लाभ मिलेगा।

सर, अभी माननीय सदस्य tenure of cooperative bank directors के बारे में बोल रहे थे। सर, देश में 33 State Cooperative Banks और 351 District Cooperative Banks हैं। आमतौर पर, चुनावी प्रक्रिया 5 साल के कार्यकाल के लिए होती है। यदि किसी Director को 8 वर्षों में रिटायर कर दिया जाए, तो 3 वर्षों का गैप आ जाता है। इसे दूर करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है कि Elected Directors और Nominated Directors (other than the full-time Director) के लिए दो टर्म कर दिया जाए, उनका कार्यकाल 10 वर्ष तक का कर दिया जाएगा, तो 8 साल और 10 साल की anomaly दूर हो जाएगी। इससे Cooperative Sector को लाभ मिलेगा और इस क्षेत्र की कार्यप्रणाली अधिक सुव्यवस्थित होगी। अन्यथा समय-समय पर डायरेक्टर बदलने से दोबारा दिक्कत आती थी। सर, 60 साल पहले से "substantial interest" चला आ रहा था, तो उसकी definition में चेंज किया गया। अगर आपकी पांच लाख की इन्वेस्टमेंट होगी या 10 per cent of the paid-up capital whichever is less, यह 60 साल पहले से था, तो अब इसको ध्यान में रखते हुए पांच लाख की जगह दो करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह अच्छा है और इसको समय के

अनुसार बदला गया है। इसकी भी हम तारीफ करते हैं। अभी जो remuneration of the auditors हैं, उसमें "Reserve Bank of India, in consultation with the Central Government, will decide what the remuneration for the auditors would be." अभी देखिए कि बैंक के जो Board of Directors हैं, they are competent enough to decide the fees according to the business of the bank. इसमें सरकार ने और autonomy देते हुए मोदी मंत्र 'Minimum Government, Maximum Governance' को ध्यान में रखते हुए यह कहा है कि "Now, the fees of the auditors will be decided by the Board." यह अधिक autonomy बैंक को देगा, यह बहुत अच्छा कदम है। इसी के साथ-साथ जो 'unclaimed amount' है, वह Investor Education Fund है। अभी तक केवल dividend जाता था, Now, the Government has taken a view. It is a very welcoming view. Now the shares, bonds, debentures, whatever interest जो भी है, the entire thing will be transferred to the Investor Protection Education Fund और जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनका क्लेम बनता है, वे उसको क्लेम कर सकते हैं। इस चेंज के बारे में बताया है।

सर, जहां तक बैंकिंग की बात है कि किस प्रकार से बैंक में क्रांतिकारी बदलाव आया है। बैंक में व्यापकता किस स्तर तक बढ़ी है। जब 2014 का समय था, उसमें सबने देखा कि यूपीए के समय किस प्रकार से फोन बैंकिंग होती थी। बैंकों में इंटरफेरेंस होता था। बड़े रसूख वालों को ही लोन मिलता था, छोटे वालों को लोन नहीं मिलता था, crisis थी, बैंकों के पास लोन देने के लिए कैपिटल नहीं बचा था। उनका capital adequacy ratio बिल्कुल खत्म हो गया था। यह बहुत बड़ा crisis था। जब बैंक कि स्थिति बिगड़ चुकी थी, bad loan से लेकर asset quality इतनी खराब थी कि आप सोच भी नहीं सकते थे। उस समय इतनी खराब स्थिति थी। अगर बैंक की स्थिति खराब होगी, तो देश में बिजनेस कैसे बढ़ेगा। वह बहुत ही crisis का समय था। चूंकि लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं थे। जो आम नागरिक हैं, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो उनके बैंक अकाउंट नहीं थे, तो वे साहूकारों के पास जाकर पैसा लेते थे। वे उनको ब्याज देते-देते थक जाते थे। वे जमीन गिरवी रखते थे। कांग्रेस के समय इस पीड़ा के बारे में किसी ने नहीं सोचा। 67 साल हो गये थे । आम व्यक्ति को लोन मिल सके, कम ब्याज पर लोन मिल सके, बिना collateral के दिए हुए उसको लोन मिल सके। इस बात की पीड़ा अगर किसी ने समझी और उस पीड़ा को दूर करने वाला कोई व्यक्ति है, तो मैं गर्व से कहता हूं कि देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी हैं और उन्होंने यह करके दिखाया है। सर, 2015 में मुद्रा लोन शुरू हुआ। जो छोटा व्यवसाय करना चाहते हैं, उनको अगर लोन की जरूरत थी, तो वे कहां जाएं। उनके पास गिरवी रखने के लिए कोई जमीन भी नहीं होती थी। प्रधान मंत्री जी ने 2015 में मुद्रा लोन स्कीम लेकर आए और उसके माध्यम से उन्होंने कहा कि आप अपना छोटा-मोटा व्यवसाय कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। कोई collateral देने की जरूरत नहीं है। आज देखते-देखते मैं यह कह सकता हूं कि 48 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिल चुका है। इसलिए भी बधाई दूंगा कि पहले 10 लाख रुपये का मुद्रा लोन था, लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में दस लाख को बीस लाख रुपये कर दिया है, इसलिए मैं उनका विशेष अभिनंदन करता हूं। स्टैंड अप योजना विशेष रूप से महिला, एससी और एसटी के लिए है। उनके लिए अलग से बैंकों में कहा गया है कि स्टैंड अप योजना के अंतर्गत यदि एससी, एसटी या महिलाएं हैं, तो उनको लोन देने का काम करो, जिससे वे भी व्यवसाय कर

सकें और लोगों को भी रोजगार दे सकें। महोदय, अभी 53,600 करोड़ रुपये स्टैंड-अप योजना के अंतर्गत डिस्बर्समेंट हो चुके हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इसलिए भी अभिनंदन करना चाहूंगा कि 1 जून, 2020 में, जब कोविड महामारी का समय था, उस समय उन्होंने यह कहा कि बेचारे रेहड़ी वाले, पटरी वाले, ठेले वाले कहाँ जाएंगे? ये बहुत संकट में हैं, इनका संकट कौन दूर करेगा, इन्हें तो कोई लोन देने वाला भी नहीं है। वे उस समय 'पीएम स्वनिधि योजना' लेकर आए। उन्होंने कहा कि जो रेहड़ी वाले, पटरी वाले लोग हैं, हम उन्हें लोन देने का काम करेंगे। आप किसी गारंटी के रूप में कोलेटरल मत दो और यदि समय पर पेमेंट करोगे, तो हम 7 परसेंट के इंटरेस्ट की सब्सिडी भी देंगे। महोदय, देखते ही देखते ऐसे रेहड़ी और पटरी वाले 94 लाख लोगों को 'पीएम स्वनिधि योजना' के अंतर्गत 13,000 करोड़ रुपये देने का काम यदि किसी ने किया है, तो वह देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। महोदय, इसी प्रकार से 'विश्वकर्मा योजना' से लेकर अन्य अनेक योजनाएं हैं।

सर, आप एग्रिकल्चर सेक्टर में देखिए कि जब यूपीए का समय था, तब कृषि क्षेत्र में जो पूरा लोन दिया था, वह 7,30,000 करोड़ रुपये, यानी 7.3 लाख करोड़ रुपये दिया गया था, लेकिन आज वही एग्रिकल्चर लोन 7 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 27 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यह इस बात को बताता है कि लोगों को किस प्रकार से कृषि क्षेत्र में लाभ मिला है।

महोदय, मैंने कहा है कि बैंकों की व्यापकता कैसे बढ़ी है। महोदय, अगर हम देखें, तो आज़ादी के बाद, देश भर में 2014 तक – हम पीएसयू बैंक की बात कर रहे हैं, अगर हम Scheduled Commercial Banks से लेकर प्राइवेट बैंक्स को जोड़ेंगे, तो यह बहुत बड़ी संख्या होगी – पब्लिक सेक्टर बैंक में, देश की आज़ादी के बाद केवल 1,17,990 ब्रांचेस थीं, इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों के पास Bank ब्रांच की सुविधा ही अवेलेबल नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कार्यकाल में इनकी संख्या 36 परसेंट बढ़कर 1,60,501 ब्रांचेस हो गई है। महोदय, जब इतनी अधिक संख्या में ब्रांचेस बढ़ गई हैं, तो लोगों को सुविधा मिल रही है। वे वहाँ जाकर लोन भी ले रहे हैं और अपना पैसा भी जमा कर रहे हैं। महोदय, यह व्यापकता इस तरह से बढ़ी है।

महोदय, इसी तरह से semi-urban क्षेत्र में 65 परसेंट और रूरल क्षेत्र में 32 परसेंट बैंकों का नेटवर्क फैला हुआ है। यह हमारे प्रधान मंत्री जी के समय का योगदान है। महोदय, आज आप RTGS/ NEFT के माध्यम से 24 घंटे, कहीं से भी पैसा ट्रांसफर करा सकते हैं। भीम ऐप और यूपीआई में तो क्रांतिकारी बदलाव आया है। महोदय, यदि डिजीटल टेक्नोलॉजी में पूरे विश्व में देखेंगे, तो पाएंगे कि यदि कहीं पर सबसे अधिक डिजीटल ट्रांजेक्शन्स भीम ऐप और यूपीआई के financial year 2023-24. इस प्रकार से यह क्रांतिकारी बदलाव डिजीटल टेक्नोलॉजी में आया है। सर, पहले बैंकों की स्थिति खराब थी। 2015 में प्रधान मंत्री जी ने सभी बैंकों से कहा था कि लोन तो यूपीए के समय में दिया गया है और यूपीए के समय में जो लोन दिया गया है, वह इस प्रकार से दिया गया है कि आँख बंद करके दिया है, टोपी घुमाई गई है, इसलिए आप ऐसा कीजिए कि सभी बैंक्स को डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो रियल में एसेट है, उसका एक्यूआर, यानी asset quality review करो। जो doubtful debts लगते हैं, जो लोन वापस आ नहीं सकते हैं, उनको छिपाने कि जरूरत नहीं है - क्योंकि इनके समय में तो नये-नये इंस्ट्रूमेंट्स ले जाकर छिपा रहे थे।

उन्होंने कहा कि इसको छिपाने की जरूरत नहीं है, आप इसको रिव्यू कीजिए, उसको डिस्क्लोज़ कीजिए। अगर वह डाउटफुल है, एनपीए है, तो उसको दिखाने का काम शुरू कीजिए। महोदय, सभी बैंक्स ने उस पर काम करना शुरू कर दिया।

महोदय, उसके बाद four 'R's — recognition of NPA, resolution, re-capitalization and reforms के माध्यम से सरकार ने four 'R's पर काम शुरू किया।

महोदय, 2016 में IBC कानून ले आए और NCLT, RP इत्यादि का प्रोविज़न हुआ। आईबीसी के आने के बाद ये लोग, जो यह कहते हैं कि आपने इतना लोन माफ कर दिया, सर इन्हें अक्ल नहीं है, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन यह होता है कि अगर आपका कोई लोन वापस नहीं आ रहा है, तो आप उसे बैड डेट्स प्रोवाइड कराके अपनी बुक्स में write-off अवश्य कर लेंगे, लेकिन उसका तकादा बंद नहीं होता है। वह चालू रहता है और उस पर ब्याज भी चालू रहता है। वह एकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि वह आएगा, नहीं आएगा, इसलिए उसकी एकाउंटिंग नहीं होती है, इसलिए उसके write-off के लिए ये ऐसा कहते हैं कि आपने माफ कर दिया। महोदय, यह ऐसे माफ नहीं होता है। अगर माफ करना हो, आपको निकालना हो, तो borrower के जो एसेट्स हैं, उसके संबंध में आप देखो कि आज की डेट में उनकी realization value कितनी है? उस realization value में सरकार कितनी रिकवरी कर रही है? तब आप कह सकते हो कि इतना माफ किया या नहीं किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार में आईबीसी आने के बाद जो fair value of asset थी, उसका 100 परसेंट नहीं, बल्कि fair value of asset का 122.81 परसेंट, मतलब जितनी फेयर वैल्यू थी, अगर उससे अधिक रिकवरी करने का काम किया है, तो वह प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया है। सर, 3,40,000 करोड़ रुपये की रिकवरी हुई है। बैंकों का फिर उसके बाद consolidation करके, कई बैंकों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, यूबीआई, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में कई बैंक मर्ज किए गए जिससे अगर बैंकों का साइज बड़ा होगा, तो बैंक बड़े लोन भी दे सकेंगे और बैंक में और एफिशिएंसी भी आएगी। यह कठोर निर्णय लेने का काम अगर किया गया है, तो वह हमारे देश के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया है।

सर, जब बजट आता था, तो हम खुद ही बजट में देखते थे और यह होता था कि बैंकों को कैपिटल देनी पड़ेगी, क्योंकि बैंकों में लॉस हो रहा है। सर, जब हमारी सरकार 1996 में आई थी, तब ग्रॉस एनपीए 16 परसेंट था। एनडीए की सरकार उसे कम करते-करते 7.8 परसेंट तक ले आई। फिर इनको गलती से सत्ता मिल गई। 12.3 परसेंट एनपीए हो गया। ग्रॉस एनपीए और 12.3 परसेंट एनपीए था, जो कि इन्होंने छोड़ा था। यह सरकार की नीतियों का, सरकार के द्वारा बनाए गए कानून का नतीजा ही है कि दिसंबर, 2024 का ग्रॉस एनपीए केवल 2.6 परसेंट है और नेट एनपीए केवल 0.6 परसेंट, मतलब नेट एनपीए 1 परसेंट से कम है। सर, पहले बैंकों में लॉस होता था। 2013-14 में किसी तरीके से 37,000 करोड़ रुपये का थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया गया। उसके बाद एनपीए के कारण 2,07,000 करोड़ रुपये का लॉस हुआ। इन्हीं के समय की काली करतूतें थीं। सर, हमने सारे आर्टिकल मीडिया से लेकर, एडिटोरियल आदि सब डॉक्यूमेंट किए हैं। 2023-24 में पब्लिक सेक्टर बैंकों ने 1,41,000 करोड़ रुपये का प्रॉफिट कमाया है, जिसमें इनके समय में लॉस होता था। अगर 9 महीने का देख लें, इसी दिसंबर, 2024 में 1,29,000 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है और यह मान के चलिएगा कि जब 2025 का आएगा, तो वह पिछले साल के

प्रॉफिट के ऊपर जाकर उसे भी पार करेगा। माननीय निर्मला सीतारमण जी समय-समय पर बैंकों को पैसा देती थीं, क्योंकि उनके पास बिजनेस करने की कैपिटल नहीं थी। कुल मिलाकर 3,26,000 करोड़ रुपये हमारी सरकार ने दिए, ताकि बैंक अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इनके काले कारनामों को हम क्यों भुगतें, बैंक क्यों भुगतें? 3,26,000 करोड़ रुपये देने का काम किया गया और आज वही बैंक प्रॉफिट कमा रहे हैं। वही बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत बड़ी मात्रा में डिविडेंड भी देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने 55,000 करोड़ रुपये से अधिक का डिविडेंड देने का काम किया है। सर, उस समय स्थिति बहुत खराब थी। आज बैंक बहुत सुदृढ़ हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो कानून आए हैं, इनके बदलाव के माध्यम से हमारे डिपॉजिटर्स, हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे स्टेकहोल्डर्स और बैंकिंग इंस्टिट्यूशन्स को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। मैं इस बिल के समर्थन में बोलते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और माननीया वित्त मंत्री जी को इसके लिए ढेर सारी बधाई देता हूं। इस प्रकार के रिफॉर्म्स जो समय-समय पर लाए जा रहे हैं, इसके लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करते हुए कांग्रेस के मित्रों से इतना ही निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूं ...(**समय की घंटी**)... जो अच्छी बात है, उसकी तारीफ कर लोगे, तो जनता भी आपको कहीं न कहीं थोड़ा बहुत समर्थन दे देगी।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद।

श्री अरुण सिंह : अदरवाइज़, जो हालत है, धीरे-धीरे ऐसा सूपड़ा साफ हो जाएगा कि जो एक-दो राज्य बचे हैं, वे भी साफ हो जाएंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद।

श्री उपसभापति : धन्यवाद। श्री साकेत गोखले।

SHRI SAKET GOKHALE (West Bengal): Sir, because this Bill pertains to the banking laws, I want to start by talking about the flagship banking scheme of this Government. A few years ago, the Government came up with this idea of providing Jan Dhan Bank Accounts to everybody. The Government's data claims that they opened a total of 54 crore Jan Dhan Accounts. It is fantastic. The idea is great. What the Government does not conveniently say is that out of these 54 crore Jan Dhan Accounts, 11 crore accounts are dormant, which means that they are not being used. These accounts are completely dormant. And, how much money do these dormant Jan Dhan Accounts have? These accounts have about Rs.14,000 crore. It is Rs.14,000 crore of poor people's money because that is what the Jan Dhan Accounts were created for, and this money is lying unused in these accounts. People are not able to access their own money. This number, Rs.14,000 crore, is a very important number *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on the subject. It is not Bengal that we are discussing. As per law, you know that you have to speak on this Banking Laws (Amendment) Bill.

SHRI SAKET GOKHALE (West Bengal): I want your ruling on something, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will read the rule.

SHRI SAKET GOKHALE: The speaker before me was talking about the *yojanas* of the Modi Government. *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; it is for all.

SHRI SAKET GOKHALE: * It is my only question.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is no separate rule.

SHRI SAKET GOKHALE: Before I completed my sentence, you stopped me. My time may be paused.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is already very clear that जिस subject, जिस बिल पर discussion हो रहा है, आप उसी पर बोलेंगे।

श्री साकेत गोखले : सर, मैं उसी पर बोल रहा हूँ।

श्री उपसभापति : आप उस पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री साकेत गोखले : सर, मैं bank accounts की ही बात कर रहा हूँ।

श्री उपसभापति : नहीं, नहीं, you are discussing West Bengal.

श्री साकेत गोखले : * ..(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : आप पश्चिमी बंगाल पर ...(**व्यवधान**)...

* Not recorded.

श्री साकेत गोखले : सर, *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It will not go on record. You are wasting your time.

SHRI SAKET GOKHALE: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You please speak on the subject. Only that will go on record.

SHRI SAKET GOKHALE: I am speaking on the subject. *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am telling you. I will be forced to call the next speaker. ...(*Interruptions*)...

SHRI SAKET GOKHALE: * Let us talk about banking in detail, that is, the deposits and the loans. Today, bank deposits have gone down and the bank loans have gone up. The number of deposits in the banks have grown at 11 per cent. On the other hand, the amount of loans taken by Indians has grown by a shocking 18 per cent. When asked a question in the Parliament in February last year, the Government told that the total amount of unsecured outstanding loans in India was Rs.62 lakh crore. Unsecured loans means credit card and personal loans. So, the amount owed by average Indians on only credit cards and personal loans is Rs.62 lakh crore, that is, 25 per cent of India's GDP. People are forced to take loans because of economic distress.

Let us come to gold. In the first nine months of this fiscal year, the number of gold loans went up by 68 per cent. Distress in the economy is forcing people to pledge their gold and take loans on that. Sure, the value of gold is going up and it has benefited people by getting a higher amount on that. I remember during the Lok Sabha elections, the Prime Minister Modi had said that the opposition would take away your *mangalsutra*. Today, under the Narendra Modi Government, women are having to pledge their *mangalsutra* to take loans to pay their monthly expenses. Who has taken away the *mangalsutra* of women? It is not the opposition; it is under this Finance Minister that the Modi Government has done that. There is a report by Perfios-PwC, which was published in February. These are the statistics of people in the urban areas. I am not talking about poor people. Thirty-three per cent of the

* Not recorded.

monthly salary goes towards paying EMIs on loans. People spend the highest amount on their obligatory loan expenses, which is 39 per cent of their total spending, followed by 32 per cent for basic necessities. Sir, 70 per cent of income EMI भरने में और आटा तथा सब्जी खरीदने में जाता है। I am talking about the urban areas. Imagine what the condition in rural areas is! People with an income of above one lakh are paying approximately 46 per cent of their after-tax salary only on servicing the existing debts. There is a loan crisis. The Government itself had admitted that consumption is down in our economy. Therefore, people are not taking loans to buy new products or to consume something new. They are taking loans to service their existing loans. The other side of this problem is that Indian banks are being crushed under the burden of Non-Performing Assets. In just last five years, Indian banks have a staggering 10 lakh crores as Non-Performing Assets (NPAs). How does this Government solve the NPA crisis? NPAs are not created by ordinary people, it is created by a bunch of 10-15 people who defraud the system and then leave the country. Banks have now been told to write off NPAs. What is a write-off, Sir? A write-off is a beautiful accounting technique where these NPAs are taken off the balance sheets of banks. It does not mean that they are repaid. It just means that they are taken off to make the balance sheet look healthy. So, NPA करो, write-off करो, बैंक्स का पैसा जाएगा but this money is still not being recovered. So, as I said earlier, deposits are going down and loans are going up. When we look closely, we find an interesting trend that the corporates are borrowing less. Corporates are, in fact, sitting on a lot of money since 2019 after corporate tax rate was slashed. They are not investing this money in the market, that is a different thing, but corporates are not borrowing. Sir, it is average people, MSMEs, who are required to borrow money every month. The loan burden of average Indians, farmers, small businesses is going up. That is the reason that our GDP growth has come crashing down to mere 5.4 per cent, which is the lowest in six quarters.

Last year, our Government was celebrating the big growth in the stock market. Fantastic! Before the Exit polls were conducted, Prime Minister Modi and the hon. Home Minister Amit Shah, came on TV and said, आप स्टॉक खरीदो, buy stocks, the market is going to shoot up. Great! People borrowed money, people used their savings and put all that money into the stock market. Now, what has happened? The people said, पीएम मोदी जी ने कहा है, तो उन्होंने कुछ सोच कर ही कहा होगा। PM Modi said, stock market will rocket; Amit Shah ji said, stock market will rocket. In the last three months, after the US elections, stock market has crashed. Who has lost the money? The average people have lost the money, Sir. Because loans are easily available; App के ऊपर आपको लोन मिलता है, people went and took loans. Because

PM Modi ने कहा, they put that money in the stock market. Savings of average Indians have been wiped off because the hon. Prime Minister decided to be a stock market expert on live television.

Sir, why are people not depositing their savings in bank accounts? Today morning, there was a report in the Mint, which said, that with an expected rate cut, banks are now going to cut their deposit rates. Now, when people are not consuming, the Government wants to stimulate consumption through. So, cutting the interest rates is a strategy. Bank's deposit rate will go down. With the food inflation, which is about 10 per cent, what is happening to deposits in banks? If the rate of interest that I am getting on my deposit is less than the rate of inflation, it means that if I am keeping money in the bank, I am actually losing money. That is why, people are not keeping money in banks; they are putting it in places like the stock market, where they feel there will be appreciations, but these are also very risky areas, and, naturally, as the bubble has burst, people have ended up losing their money.So, what is the Government doing to make deposits attractive? It is forcing banks to market deposits. Saying that your ratio is really bad, your credit deposit ratio is bad, the Government is forcing banks to do marketing. Banks are marketing these deposits aggressively to people. But what is happening is that there is a major liquidity crisis in the country. Banks can only offer money when there is liquidity in the system. Today, banks are being encouraged to bring in deposits. Deposits are liabilities for banks while loans are assets. These deposits are coming in with attractive interest rates on it. When there is no liquidity in the market, this is affecting the profit margins of banks. Let us say, if the price of gold, which they are holding right now on behalf of people, comes crashing down tomorrow, then, with respect to the gold loans for which gold is used as collateral, banks will not be going to have the margin that is required to service that money. Sir, in the last five years, our Public Sector Banks (PSBs) have made revenue of Rs. 8,500 crores through a very unique mechanism. What is that mechanism, Sir? Penalties on not maintaining minimum balance! You are a poor person but if you have no money in your account and you do not maintain a minimum balance, bank is going to charge you a penalty. Sir, an amount of Rs. 8,500 crores has been earned by banks by taking money from poor people, who do not have money to even keep a minimum balance in their accounts. This happens with the poor.The other harassment is done to the middle class. Every three months, do your KYC, do a re-KYC, do a re-re-KYC. Sir, when PAN cards are linked to bank accounts, Aadhaar is linked to bank accounts, what is the need for this constant KYC? …(*Interruptions*)… But they make people keep doing that.

श्री उपसभापति : प्लीज़, बैठ कर कमेंट नहीं करें।

SHRI SAKET GOKHALE: People have to do the KYC because otherwise, the bank accounts are frozen. And, once these accounts get frozen, it becomes a major nightmare as people have to go to the branches, while people do not have the time to do that. But every time, 'do your KYC or we will freeze your account'. No questions asked. When the data is there with the Government, the Government is very good at using data for other things. Before elections, we get a WhatsApp message about *Viksit Bharat* during the Code of Conduct. So, they have the data to send WhatsApp messages during elections; they don't have the data to find out where a person is staying using the AadhaAr and PAN. Why do I need to keep doing KYC every two months?

Sir, all I wish to say in conclusion is that piecemeal legislation like this Banking Laws (Amendment) Bill is useless until we address the structural problems faced by our banks. These problems will continue to exist unless we implement drastic economic reforms. Sir, the Finance Minister thinks that the gaping wounds in our economy can be fixed with a band-aid. The first step towards any problem is to first accept it. When you accept is, when you start making amendments and changing. This Government, for eleven years, is not willing to accept that there is a problem. We very clearly saw this in a visionless Union Budget where there was absolutely no sort of reform done. Sir, the Modi Government has dangerously started believing its own *jumlas*. It started this propaganda to mislead the people, but now in a shocking turn of events, the Modi Government itself is actually believing '*sab changa si*'. They have deluded themselves into thinking that everything is fantastic under our Government, everything is great, and things have never been better before. Sir, our economy and our banking system cannot be fixed until the Government removes its blindfolds. I strongly urge the hon. Finance Minister to come back to this House with some real, actual banking reforms instead of bringing pointless Bills like the Banking Laws (Amendment) Bill, which does absolutely nothing to fix our banking system. Thank you, Sir.

श्री उपसभापतिः माननीय सदस्यगण, आप सबको पुनः याद दिलाने के लिए I will read Rule Number 110 of the Rules and Procedures. "The discussion on a motion that the Bill be passed shall be confined to the submission of arguments either in support of the Bill or for the rejection of the Bill. In making his speech, a Member shall not refer to the details of the Bill further than is necessary for the purpose of his arguments which

shall be of a general character." आप बहस में इस Rules and Procedures का ध्यान रखें। Now, Mr. K. R. N. Rajeshkumar.

SHRI K.R.N. RAJESHKUMAR (Tamil Nadu): Hon. Deputy Chairman, Sir, ..(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: One minute, please. Yes, Mr. Derek O'Brien.

SHRI DEREK O' BRIEN (West Bengal): Sir, I am glad you have referred to this Rule from the Chair. With full respect, Sir, my request to you is the timing of this observation is yours to choose from. It is happening more from this side because you chose to read this, which is your prerogative, after somebody from this side finished his speech.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is your perception.

SHRI DEREK O' BRIEN: This is my earnest request, my humble request. ..(Interruptions).. Sir, I request you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please, take your seat.

SHRI DEREK O' BRIEN: One minute, Sir. Let me finish.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have already said. ..(*Interruptions*).. No, no. ..(Interruptions).. You have already said. ..(Interruptions).. आपसे भी आग्रह है कि कृपया आप बैठें।...(**व्यवधान**)... The Chair is on its legs. ऐसे नहीं, कृपया आपस में बात न करें।...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्यगण, आपमें से एक-एक व्यक्ति...(**व्यवधान**)... देरेक जी, आप बड़े सीनियर मेम्बर हैं, आप सदन में नहीं थे, कोई इधर से बोल रहे थे, कोई उधर से बोल रहे थे, मैं हमेशा कहता हूँ कि speak on the subject. It is your perception which you are telling. ..(*Interruptions*).. Nothing is going on record. ..(*Interruptions*).. Shri K.R.N. Rajeshkumar, you please speak. Nothing else is going on record. ..(*Interruptions*)..

SHRI K.R.N. RAJESHKUMAR: Hon. Deputy Chairman, Sir, I am very thankful to the hon. Tamil Nadu Chief Minister, Thalapathy, the hon. Deputy Chief Minister, Annan, and also our floor leader, Shri Tiruchi Siva, for giving me this opportunity to speak on the Banking Laws (Amendment) Bill, 2024. I have a few concerns, Sir. I am coming

to the nomination system, especially the amendment to Section 45 ZA. When a large number of banks currently do not have a single nominee as per the RBI report on customer service published in 2023, expecting to have up to four nominees sounds like saying, "if you do not have bread, eat cake". The concept of appointment of nominee by the account holder under the Banking Regulations Act is to have smooth distribution of assets among the legal heirs after the death of the account holder. The nominee acts as a power of attorney holder. The only difference between a power agent and a nominee is authority given under power of attorney ceases when principal account holder dies, whereas the role of nominee will come into play after the principal account holder dies. Nominee is not a legal heir. If more than one nominee is appointed, and if there is no conscious decision taken among nominees, the deposit amounts cannot be withdrawn smoothly for disbursement to legal heirs. This raises significant concerns and highlights the need for careful consideration and clarification on nomination system. Next issue is regarding auditor remuneration.

[The VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI DHARMSHILA GUPTA), *in the Chair*]

I would like to address the Amendment of Section 17 regarding auditor remuneration. The additional powers given to banks may lead to recruiting its known auditor and with higher remuneration only to manipulate the audit report. That may lead to hide corrupt practices. Therefore, it is best to be fixed by the RBI in consultation with the Union Government which is already an existing practice.

Next issue is regarding PAN card mandates. In villages, primary cooperative bank mandates the rural people to have PAN card even for their minimal deposit. It is complicated for the village people to maintain the deposit account. This affects the saving habits of our rural people. I urge the Government to relax the norms for the deposit account, especially for low-value transactions in primary cooperative banks and in the Nationalised Banks as well.

Next issue is regarding exemption from minimum balance penalty. The bank account holders face issues with automatic deduction as penalty when their balance falls below the minimum requirement. This affects low-income individuals and daily wage earners who struggle to maintain their accounts. I urge the hon. Finance Minister to address this concern as well.

Next issue is regarding inclusion of cooperative banks in Central Government Schemes. It is very important. Our rural cooperative banks have made significant achievements in digitalisation. However, the Central Government has not considered the cooperative banks to deliver the Central Government schemes. Considering its

potential, I urge the Government to include the cooperative banks in Central Government Schemes. Then only the benefits of Central Government schemes can be availed by cooperative bank account holders. There are portals such as Vidya Lakshmi Education Loan, Pradhan Mantri Awas Yojana, Housing Loan, etc. Also, kindly consider the cooperative banks to include in Single Nodal Account (SNA) for Central Government Schemes.

The next issue is regarding exemption of TDS from Cooperative Central Banks. In rural areas, the Primary Agriculture Cooperative Credit Society acts as a key source of credit for farmers by supporting them in financing agriculture activities and allied activities through the District Central Cooperative Bank. It is also a function for the disbursement of the State Government Relief Fund, including subsidies, drought relief, disaster compensation and other forms of financial assistance through the Cooperative Central Bank. These societies have been affected by Section 194N while they transacted the farmers' funds. Hence, it is essential to consider the exemption of tax deduction at source on this account to ensure smooth and efficient delivery of financial aid to beneficiaries.

Next issue is tax exemption for NABARD. This is my request to the hon. Finance Minister. NABARD is the backbone of our rural economy. It plays a vital role in agricultural credit, rural infrastructure development and promoting sustainable income across the country. It is the true mother bird of our rural sector for developing and supporting the very foundation of our national wealth. However, the financial framework under which NABARD operates severely restricts its ability to fulfil its mandate. The imposition of taxes on NABARD's operations drains resources that should directly uplift rural communities through their institutional development and many promotional initiatives such as watershed and tribal development projects. I urge the Government to please remove the tax imposed on NABARD.

For the current financial year, the priority sector lending funds allocated to NABARD have been reduced. As a result, the consensual crop loan to various cooperative banks have been significantly impacted across India. Sir, it is not just for Tamil Nadu, but for the whole country. Now NABARD has decreased crop loan because the priority sector lending fund is not allocated for NABARD. I request hon. Finance Minister to consider it. Then, for the first time in India, all agricultural loans issued by cooperative societies were waived off by the great eminent leader, former Chief Minister Kalaignar, during 2006. It was to the tune of Rs. 7,000 crore. On the same line, good governance is given by our Chief Minister Thalapathi. The ADMK Government had given just a paper waiver; that too, only to crop loans. After assuming the post of Chief Minister of Tamil Nadu, our great leader Thalapathi settled

the entire waiver amount, nearly Rs. 13,000 crore, to cooperative societies. Hence, our Government is a farmer-friendly Government. It has done many welfare activities for farmers. The name of the Department is also changed from 'Department of Agriculture' to 'Agriculture – Farmers Welfare Department' in Tamil Nadu. It is the only State, under the leadership of Thalapathi, which gives a separate Budget for agriculture.

Madam, the hon. Finance Minister is not in the House, but I would make a request. The Ministry of Cooperation has made an initiative of 'One District One Cooperative Bank'. That policy is now initiated by the Ministry of Cooperation. In the circumstances, I humbly request the Ministry of Finance and the Ministry of Cooperation to provide support to newly formed District Central Cooperative Banks by expediting grant of licence and other support such as share capital and infrastructure development. Licence is given to the District Central Cooperative Bank; the Ministry of Cooperation provides support only for share capital and other infrastructure. This policy is implemented by the Ministry of Cooperation. Newly formed District Central Cooperative Banks are growing well and sustaining. There is a need to give share capital subsidy other than infrastructure subsidy; then only, it would be a win-win situation for the Ministry of Finance and the Ministry of Cooperation. Then, I would like to conclude. I urge the hon. Finance Minister to review the Banking Laws (Amendment) Bill, 2024, by addressing these concerns and implementing the necessary changes. Thank you.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता) : माननीय सदस्य श्री राघव चड्ढा जी, आपके पास बोलने के लिए 9 मिनट का समय है।

3.00 **P.M.**

श्री राघव चड्ढा (पंजाब) **:** शुक्रिया, मैडम, कि आपने मुझे बैंकिंग बिल, 2024 पर बात करने का मौका दिया।

मैडम, बैंक ईंट या सीमेंट से बनी किसी इमारत का नाम नहीं है, बैंक सिर्फ किसी स्टील या एल्यूमिनियम से बने एटीएम का नाम नहीं है और बैंक न ही एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर दौड़ रहे ग्राहकों की उस भागदौड़ का नाम है।

बैंक नाम है विश्वास का। बैंक नाम है अधिकार का, न्याय का, समानता का। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह विश्वास, जो ग्राहकों का बैंकिंग व्यवस्था में था, वह कहीं न कहीं कमजोर होता नज़र आ रहा है। इसके कुछ बुनियादी और बेहद basic कारण हैं, जिन्हें मैं आज इस सदन में, आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहला कारण – कमजोर ग्राहक सेवा (Poor Customer Service)

अगर आज किसी ग्राहक को किसी सरकारी बैंक में किसी काम से जाना हो, तो मान लीजिए उसके ग्रह खराब चल रहे हैं और उसकी पूरी दिहाड़ी भी खराब होगी। अगर वह नौकरीपेशा व्यक्ति है, तो उसे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी। अगर वह छात्र है, तो उसे अपना प्रैक्टिकल एग्जाम मिस करना पड़ सकता है। यहां तक कि साधारण सी पासबुक अपडेट करवाने जाना भी एक संघर्षपूर्ण सफर में तब्दील हो जाता है।

मैडम, जब आप किसी सरकारी बैंक में प्रवेश करते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप 80 या 90 के दशक की किसी इमारत में आ गए हैं। जहां दीवारें उखड़ी हुई होती हैं, पंखा अपनी मर्जी से चलता है और लाइनें रेलवे टिकट काउंटर से भी लंबी होती हैं। इसके बाद, जब आप काउंटर नंबर 1 पर पहुंचते हैं, तो आपको बताया जाता है, "यहां काम नहीं होगा, काउंटर नंबर 4 पर जाइए।" जब आप काउंटर नंबर 4 पर पहुंचते हैं, तो कहा जाता है - "यहां भी काम नहीं होगा, फर्स्ट फ्लोर पर जाइए।" और जब आप थके-हारे फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं, तो आपको बताया जाता है, "लंच हो गया है, अब 2 बजे आइए।" फिर जब आप सवा दो बजे पहुंचते हैं, तो जवाब मिलता है, "लंच एक्सटेंड हो गया है, अभी कर्मचारी गुलाब जामुन खा रहे हैं!"मैडम, यह है सरकारी बैंकों में ग्राहक सेवा की स्थिति। आज हम चांद पर पहुंच गए हैं, UPI से गोलगप्पे खरीद रहे हैं, लेकिन हमारी सरकारी बैंकिंग व्यवस्था अभी भी 80-90 के दशक से बाहर नहीं आ पाई है।

हाल ही में RBI गवर्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्तीय वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि 95 शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों में एक साल के भीतर 1 करोड़ से अधिक ग्राहक सेवा से जुड़ी शिकायतें दर्ज हुई हैं। महोदया, ये तो वे शिकायतें हैं, जिन्हें दर्ज करवाने का तरीका ग्राहकों को पता था और उन्होंने दर्ज कराईं। न जाने ऐसी कितनी शिकायतें होंगी, जो सिस्टम में दर्ज ही नहीं हो पाईं। इसी के साथ-साथ Banking Codes and Standards Board of India का एक survey बताता है कि 45 प्रतिशत bank customers बैंकिंग व्यवस्था से dissatisfied हैं, असंतुष्ट हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार के कानों तक यह बात पहुंचे कि सरकारी बैंकों की digital services का एक customer satisfaction audit कराना चाहिए कि क्या हमारी सरकारी बैंकों की वेबसाइट का interface या mobile applications सरल हैं, अच्छी हैं या कस्टमर्स उससे त्रस्त हैं। दूसरा, बड़ी समस्या यह है कि रूरल इंडिया के अंदर limited access to banking infrastructure के बारे में है। मैडम, आइए गांव की और चलते हैं। क्या हमारी बैंकिंग व्यवस्था ग्रामीण इलाकों तक पहुंच चुकी है। नाबार्ड की एक रिपोर्ट बताती है कि 50 per cent of rural India is still suffering from lack of adequate access to banking. Financial Inclusion Index की आरबीआई की 2020 की रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण भारत में हर 100 में से मात्र 54 लोगों तक ही हमारी बैंकिंग व्यवस्था जैसे-तैसे पहुंच पाई है और 30 प्रतिशत से ज्यादा rural households आज भी ऐसे हैं, जो पूरे तरीके से unbanked हैं। मैडम, अगर ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग की बात करें, तो बैंकिंग व्यवस्था ने ग्रामीण इलाकों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। पहले तो बैंक की ब्रांच गांव के पास नहीं है। जब बूढ़ा आदमी भूला-भटका पांच-दस किलोमीटर दूर बैंक की ब्रांच तक पहुंचता है, तो पता लगता है कि बिजली गुल है। बिजली आ जाती है, तो पता लगता है कि server down हो गया है। सर्वर भी चल जाता है, तो पता लगता है कि Aadhar seeding में दिक्कत है। Fingerprint mismatch हो रहा है या bank account की mapping ही नहीं हो पा रही है। Documentation से लेकर, complicated form से लेकर,

language के challenges तक ग्रामीण इलाकों में लोगों को झेलने पड़ते हैं और सबसे ज्यादा banking fraud भी गांव के भोले-भाले आदमी के साथ होता है। इसी के चलते हमारे गांव का आदमी private, निजी साहूकार के पास जाकर loan लेना बेहतर समझता है, न कि किसी bank के पास जाकर। जब वह साहूकार के पास जाता है, तो न वहां paper work होता है, एक easier access होता है। Fear of bank or illiteracy नहीं होती, बहुत बार तो mortgage पर कुछ नहीं रखना पड़ता है, इसलिए वह साहूकार से ब्याज पर पैसा उठाता है, लेकिन साहूकार उसे मनमाने दाम पर ब्याज पर पैसा देता है। वह 60 से 80 प्रतिशत सालाना का interest rate चार्ज करता है। जिंदगी भर के लिए उसकी गुलामी लिखवा लेता है और वह बेचारा गांव का भोला-भाला आदमी debt trap में फंसकर रह जाता है। मेरी तीसरी सबसे बड़ी समस्या, जो मैं आज आपके समाने रखना चाहूंगा, जो cyber fraud, digital frauds in banking sector. 2023 में cyber frauds की 75,800 घटनाएं सामने आईं, जिनकी complaints दर्ज हुई। वर्ष 2024 आते-आते 75,000 से बढ़कर यह आंकड़ा 2,92,000 हो गया, यानी कि 285 प्रतिशत के banking frauds की घटनाओं में इजाफा देखा गया और इस banking fraud के चलते लोगों के 2,100 करोड़ रुपये zero हो गए, शून्य हो गए, उनका नुकसान हो गया। इसमें सबसे ज्यादा complaints UP-related banking frauds की आई हैं। मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि money theft के साथ-साथ data theft भी उतना ही जरूरी है। जब आप bank को पूरे विश्वास के साथ अपना data देते हैं, अपना PAN देते है, अपना नाम, address, date of birth तमाम चीजें देते हैं, तो क्या bank आपके data को सुरक्षित रख पाता है। क्या bank जाने-अनजाने में या data चोरी के माध्यम से वह हमारा सारा data marketing कंपनीज़ के पास, credit card कंपनीज़ के पास, loan देने वाले, flat बेचने वाले लोगों तक नहीं पहुंचाता! एक report के मुताबिक 2019 में SBI के 3 million customer account data leak हो गया और तमाम banking history leak हो गई। 2021 में MobiKwik का 8.2 TB KYC data leak हो गया। 2021 में payment gateway Juspay का 100 million credit cards की payment details और records leak हो गए। अब यह लीक है या जाने-अनजाने में data sharing है, यह फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन आपको इस data leak का भुगतान करना पड़ता है, उसको भुगतना पड़ता है और उसका सबसे छोटा-सा उदाहरण है कि आए दिन आपके बीवी, आपके माता-पिता, आपके घरवाले आपका हाल पूछे न पूछे, लेकिन marketing calls वाले आपको रोज फोन करके कहेंगे कि आपका credit card approve हो गया, आपका loan approve हो गया, हमसे flat ले लीजिए, हमसे फलानी चीज़ ले लीजिए। इनके पास हमारा data कहां से आता है। यह एक बड़ा सवाल है। चौथी समस्या hidden charges और fees के बारे में है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि नाना प्रकार के charges हैं, जो आज मैं सदन में लाया हूं, ये माननीय वित्त मंत्री जी तक पहुंचें, ताकि देश के आम आदमी की जेब banking system काट रहा है, तो उसके बारे में ग्राहक को भी पता लगे और माननीय वित्त मंत्री जी को भी पता लगे। पहला, minimum balance penalty- यदि आप न्यूनतम balance नहीं रखते हैं, तो bank आपका 100 से 600 रुपये प्रति माह काट लेता है। इस charge को लगाने के बाद बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3,500 crore रुपये minimum balance penalty के नाम से लोगों से वसूले। दूसरा charge extra ATM usage के ऊपर है। आपको बैंकों द्वारा ATM transaction के लिए दो से तीन की इजाजत मिलती है। अगर आप

चौथा, पांचवां transaction कर लें, तो हर transaction पर आपको 20 रुपये ATM charge देना पड़ता है। Inactivity fee 100 से 200 रुपये सालाना है, यानी कि अगर बैंक का बहुत ज्यादा account use नहीं करते हैं, तो बैंक inactivity के नाम पर भी charge लगा देता है। यदि आप बैंक स्टेटमेंट मंगवाते हैं, तो बैंक स्टेटमेंट इश्यूएंस चार्जेस के नाम पर आपसे 50-100 रुपये लेता है। फिर आप कहते हैं कि एसएमएस अलर्ट्स के माध्यम से मेरे बैंक के खाते में क्या आ रहा है, उसकी जानकारी मिलनी चाहिए, तो एसएमएस अलर्ट चार्जेस के नाम पर आपसे प्रति क्वार्टर 20-25 रुपये लिये जाते हैं। यदि आप online payment करेंगे, आपने NEFT की, तो उसकी भी transaction fee ली जाती है। ये लोग पहले आपको जबर्दस्ती लोन बेचते हैं और फिर उसके बाद loan processing fee के नाम पर 1 से 3 प्रतिशत राशि loan amount की काट लेते हैं। महोदय, जब आपकी किस्मत ठीक चल रही हो और आप समय से पहले अपने लोन के बकाये का भुगतान करने के लिए बैंक पहुँच जाएं, तो loan pre-closure charges, early payment penalty के नाम पर भी बैंक आपसे पैसा वसूलता है, साधारण-सा signature बदलवाना हो, nominee की details बदलवानी हो, तो बैंक आपसे उस change पर भी 200 रुपये प्रति transaction के नाम पर पैसा वसूलता है। यदि demand draft और pay order बनवाने जाएं, तो बैंक आपसे 100-200 रुपये प्रति डिमांड ड्राफ्ट वसूलता ही वसूलता है, यानी की कस्टमर्स की जेब काटी जा रही है और कस्टमर्स को पता भी नहीं लगता कि बैंक कितना पैसा इन नाना प्रकार के charges के चलते आम आदमी से वसूल रहा है।

मैडम, मेरा पाँचवाँ और आखिरी प्वाइंट insurance and investment product misselling है। अपने क्वार्टर्ली या मंथली टारगेट्स पूरा करने के लिए bank के Executive misselling करते हैं, लोगों को गलत प्रॉडक्ट्स बेचते हैं। यह भी एक प्रकार का honey trap है। मीठी-मीठी बातें करके, भोले-भाले मासूम लोगों को ऐसे प्रॉडक्ट्स बेच दिए जाते हैं, जिनकी जरूरत उन्हें है ही नहीं। Insurance Regulatory Development Authority of India (IRDAI)की एक रिपोर्ट बताती है कि 3.5 लाख सालाना complaints में से 20 प्रतिशत complaints सिर्फ और सिर्फ मिस्सेलिंग, यानी गलत प्रॉडक्ट्स बेचने की दर्ज की गई हैं। SEBI की एक Report बताती है कि 30 प्रतिशत इन्वेस्टर्स misleading information के शिकार हैं और म्युचुअल फंड्स की mother body, जिसे Association of Mutual Funds in India कहते हैं, वह बताती है .. (**व्यवधान**)..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI DHARMSHILA GUPTA): Hon. Member, please conclude.

श्री राघव चड्ढा : मैडम, मैं खत्म कर रहा हूं। 23 प्रतिशत इन्वेस्टर्स ऐसे हैं, जिनके पास वे प्रॉडक्ट्स हैं, जो उनके risk profile और financial goal से मेल ही नहीं खाते हैं। मैडम, मैंने जो सारी समस्याएं बताई हैं, उनके माध्यम से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये बहुत बुनियादी समस्याएं हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI DHARMSHILA GUPTA): Please conclude.

श्री राघव चड्ढा : मैडम, आज इस देश का एक आम एकाउंटधारक, एक आम आदमी सफर कर रहा है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता): आपका समय समाप्त हो गया है। Please conclude.

श्री राघव चड्ढा : वह सफर कर रहा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इन बुनियादी समस्याओं का समाधान करें।

उपसभाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता): श्री मेदा रघुनाधा रेड्डी, आपके पास 6 मिनट हैं, आप अपना भाषण आरंभ कीजिए।

SHRI MEDA RAGHUNADHA REDDY (Andhra Pradesh): Madam Vice-Chairman, the banking sector in India has been growing at a stellar rate over the years and I welcome this Bill for its willingness to adapt to the evolving needs for our times. However, I have certain specific comments to make.

I wish to raise about the banking sector in the context of Andhra Pradesh. Now, about Financial Scams: Banking fraud cases in India surged 27 per cent to 18,461 in the first half of the Financial Year 2024-25 compared to its previous level of 14,480 cases in the same period in the previous year. The data also shows that the total amount involved increased nearly eightfold to Rs. 21,367 crore in the first half of the financial year 2024-25, compared to Rs. 2,623 crore in the same period last year. Now, the remedy: I remind the House of the Agrigold Scam, where my party leader, Shri Jagan Mohan Reddy Garu, took the unprecedented step of ensuring direct State intervention to support victims. Rs. 667 crore were released to over 10.4 lakh victims. It was the first time that the State Government actively assisted those affected by the financial fraud, setting a strong precedent for the accountability and justice. I request the Central Government and all State Governments to follow the pro-public example set by Shri Jagan Mohan Reddy Garu and compensate victims through the State Exchequer whenever possible.

Now, about credit for farmers and rural areas: Madam, during his tenure as Chief Minister, in 2022-23, Shri Jagan Mohan Reddy Garu authorized and announced a total outlay of Rs. 3,19,480 crores as credit at the 219th State Level Bankers' Committee (SLBC) meeting. Of this, 54 per cent of the loans were earmarked specifically for the agriculture sector. Throughout his tenure, bankers were instructed to redouble their efforts to lend more credit to support the downtrodden to withstand

the pressure of inflation. Farm mechanisation, poultry and tenant farming were also given special focus. Such a vision is lacking in the Union Budget's banking focus. The PM-Kisan Samman Nidhi Yojana had a utilization of Rs.63,500 crores, exceeding the initial allocation of Rs.60,000 crores in 2024-25, yet, the allocation has stagnated at Rs.63,500 crores again. The Deen Dayal Antyodaya Yojana, which intends to give credit assistance and interest subvention to rural women self-help groups, has an unimpressive increase from Rs.15,047 crores to Rs.19,005 crores. Of the 40.6 crore women in rural parts of India, we have only been able to cover around eight crores so far. What is needed is a multiplication of these schemes' financial allocation and not just marginal increase; following Jagan*ji*'s example. Madam, through you, I request the hon. Finance Minister for five-day work week and social security for banking employees. Banks operate six days a week as per standard practice. The employees of the Central Government, Reserve Bank of India, Life Insurance Corporation (LIC), etc., enjoy a five-day week. With the approval for Eighth Pay Commission's constitution, going by the previous Pay Commission, a fitment factor of over 2.57 per cent is expected for Central Government employees. However, as per the December, 2023 tripartite agreement between the Indian Banks' Association and Banking Employee Unions, a mere 17 per cent salary hike was agreed upon. This means that bankers get lower salaries as well as they have more working days compared to their equivalent Central Government employees. Likewise, in the Employee Association meeting of Retired SBI staff at Andhra Pradesh from Tirupati, Kakinada, Vijayawada, Guntur and Rajahmundry, the hardships of retired banking employees with insufficient pension were highlighted. I request the hon. Minister to look into this urgently along with reduction of the number of working days for banking employees. With these suggestions, I support the Bill. Thank you, Madam.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता) : धन्यवाद, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, श्री निरंजन बिशी। आपका समय 6 मिनट है।

SHRI NIRANJAN BISHI (Odisha): Madam, I am thankful to you for giving me an opportunity to speak on the Banking Laws (Amendment) Bill, 2024, which seeks to amend the critical legislation governing the banking sector, including the Reserve Bank of India Act, the Banking Regulation Act, 1949, SBI Act and the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Acts of 1970 and 1980. While the Bill aims to modernize and streamline banking regulations, it has to ensure safeguards for the interest of poor customers, women customers, farmer customers, SC/ST customers. First of all, I would say that this Bill has limited focus on public

sector banks which form the backbone of our financial ecosystem, particularly, in villages and semi-urban areas. The Bill does not address the problems like high non-performing assets, lack of digitization and declining market share. By amending the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Acts, 1970 and 1980, the Bill strengthens the way for further privatization of public sector banks which goes against the people of our nation and against the employees of banks and SC/ST communities because if the nationalized banks would be privatized, then the private banks, the micro finance companies, the private financing institutions will exploit the customers by levying 36 per cent interest on them.If the nationalized bank would be privatized, then private bank, micro-finance company and private finance institution will exploit the customer by levying 36 per cent interest upon the customer. Secondly, a growing concern is the alarming rise in digital frauds, which are causing significant financial loss to individuals across the country. With the rapid adoption of digital banking, cybercriminals are exploiting gaps in cyber security, targeting unsuspecting customers through phishing, identity theft, and online scams. Reports indicate a surge in cases where hard-earned savings are wiped out due to inadequate protection and customer awareness. The Bill, however, has substantial robust provision to address this pressing issue. Strengthening cyber-security frameworks, mandating advanced fraud detection system and ensuring timely customer redressal are critical steps that must be incorporated. Public awareness campaign on digital safety should also be emphasized to protect consumers from cyber robbery. मैडम, 2021 से 2024 तक **cyber crimes** की 30 लाख 5 हजार **complaints** हुई हैं और उनमें **consumers** का, **customers** का, **stakeholders** का 27,914 करोड़ रुपए का **loss** हुआ है। पहले **treasury** की, घर के आलमीरा की जो चोरी-डकैती होती थी, उसमें उसे तोड़-फोड़ कर चोरी की जाती थी, लेकिन अभी **cyber crimes** में, **cyber frauds** में **poor to rich**, **officer to labour**, सबकी **online** चोरी-डकैती होती है। इसमें गरीब अपनी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए जो पैसा इकट्ठा करता है, **saving** करता है, वह 27,914 करोड़, जो हमारी **Ministry of Social Justice and Empowerment** का एक साल का बजट है, जो एक डिपार्टमेंट का, एक मिनिस्ट्री का एक साल का बजट है, देश के इतने पैसे, 27,914 करोड़ की **bank robbery** हुई है, **cyber robbery** हुई है! इसलिए हमें **Artificial Intelligence** को **strengthen** करना है और जो **citizens' data** है, उसको **secure** करना है। हमारे देश में अभी तक 1,65,501 **Scheduled Commercial Bank Branches** हैं और 2,55,536 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें से 90,035 ग्राम पंचायतों में अभी भी **bank facility** नहीं है। हमारे ओडिशा में 6,794 ग्राम पंचायतें हैं, जबकि केवल 2,012 **bank branches** हैं। इस तरह से 4,782 ग्राम पंचायतों में अभी भी **bank** की **branch** नहीं है। गाँव के गरीब, गाँव के किसान, गाँव की महिला, गाँव के युवा, उनको यह **bank facility** नहीं मिलती है। अगर गाँव के लोगों को, गाँव के गरीब, किसान, महिला को **bank** की **service** नहीं मिलती है, तो वे कैसे **saving** करेंगे, कैसे **loan** लेंगे? अगर केवल **urban**

area में **bank** की **branch** होगी, केवल **urban area** के **customers loan** लेंगे, तो ये जो गरीब हैं, महिला हैं, किसान हैं, उनको कैसे **bank** से **loan** की सुविधा मिलेगी? इस तरह से कैसे देश आगे बढ़ेगा! इसलिए हर ग्राम पंचायत में एक-एक **bank** की **branch** होनी चाहिए।

मैं ओडिशा के बारे में बोलता हूँ। In Odisha, farmers, entrepreneurs and MSMEs struggle to access timely credit and insufficient infrastructure, such as branch closures and limited ATMs which escalate financial exclusion. To address these concerns, the Bill should prioritize strengthening public sector banks through recapitalization and operational improvements, mandate expanded banking services to deprived areas and include robust cybersecurity frameworks.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI DHARMSHILA GUPTA): Now, Dr. M. Thambidurai, you have four minutes to speak.

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Hon. Vice-Chairman, Madam, on behalf of my party, AIADMK, party leader, Edappadi K. Palaniswami, I rise to speak on the Banking Laws (Amendment) Bill which seeks to amend five laws. Madam, just now, DMK Members accused our AIADMK party. I want to answer first for that. Madam, during the DMK regime only, there are a lot of scams that have taken place in the cooperative banks. Many criminal cases are pending against the DMK Members. But he is accusing us. Secondly, Madam, regarding the banking laws, they gave wrong promises to the public in the election manifesto.Now, coming to the students' welfare and farmers' welfare, I would like to draw the attention of the House to the false promises made by the DMK in the election manifesto during the 2021 Assembly election and also during the 2024 Lok Sabha election. ..*(Interruptions)*.. They promised that agricultural loans and jewel loans taken by marginal farmers from cooperative banks will be waived off. They have not waived it off. ..*(Interruptions)*.. They promised that farmers will be given interest free loans. They have not given. ..*(Interruptions)*.. They promised to give free loans to farmers, but they have not given...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता): माननीय सदस्य, कृपया आप विधेयक पर ही बोलें। ...(**व्यवधान**)...

DR. M. THAMBIDURAI: That is what I am speaking, Madam.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता): कृपया आप विधेयक पर ही बोलें। ...(**व्यवधान**)... ..*(Interruptions)*..

SHRI R. GIRIRAJAN (Tamil Nadu): Speak on the subject.... ..*(Interruptions)*..

SHRI K.R.N. RAJESHKUMAR: Speak on the Bill. ...*(Interruptions)*..

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता): आप लोग कृपया बैठ जाएँ। ...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्य, आप विधेयक पर ही बोलें। ...(**व्यवधान**)...

DR. M. THAMBIDURAI: Then, Madam, they promised students of Tamil Nadu ..*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता): माननीय सदस्य बोल रहे हैं, आप अपनी सीट पर बैठ जाएँ। ...(**व्यवधान**)...

DR. M. THAMBIDURAI: They gave all false promises. Because they accused us, that is why, I am telling you this. ..*(Interruptions)*..

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता): माननीय सदस्य, आप कृपया बैठ जाएँ। ...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्य, आप बिल पर ही बोलिए। ...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्य, आप बिल पर ही बोलें। ..*(Interruptions)*.. आप बैठ जाएँ। ...(**व्यवधान**)... वह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। ...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाएँ। ...(**व्यवधान**)... Please sit down. ..*(Interruptions)*.. माननीय सदस्य, आप बोलें। ...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्य, आप बोलें।

DR. M. THAMBIDURAI: Madam, he spoke about the AIADMK Party. That is why, I am replying for that. Let them answer. They promised that they will abolish the NEET. But they have not abolished it. ..*(Interruptions)*.. In the same way, they misled the students saying that they will waive off their study loans. ..*(Interruptions)*.. But it has not been done. ..*(Interruptions)*.. In the same way, they asked the farmers to borrow loans putting their jewels in the bank. The poor people believing that the DMK people will fulfil their promise, borrowed loans. ..*(Interruptions)*.. They have not done that. ..*(Interruptions)*.. As a result, poor people and farmers are suffering. ..*(Interruptions)*..

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता): आप बैठ जाएँ। ...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्य, इस संदर्भ की नियमों के अन्तर्गत जाँच की जाएगी। ...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्य, आप बैठ जाएँ। ...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्य, आप कृपया बिल पर ही बोलें। नियमों के अन्तर्गत ही इसका आकलन किया जाएगा। यदि कोई असंगति होगी, तो वह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

DR. M. THAMBIDURAI: I am not misleading. ...*(Interruptions)*.. Why was he talking about the AIADMK party? ....*(Interruptions)*..

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता): माननीय सदस्य, आप बैठ जाएँ।

DR. M. THAMBIDURAI: The DMK Members accused the AIADMK.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता): इस संदर्भ का नियमों के अन्तर्गत ही आकलन किया जाएगा। यदि कोई असंगति होगी, तो वह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। ...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्य, आप कृपया बैठ जाएँ। ...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्य, आप बोलें। ...(**व्यवधान**)... Please sit.

DR. M. THAMBIDURAI: So, I have every right to speak here. ..*(Interruptions)*. Their loans have not been waived off. That is what I am saying. ..(Interruptions)... This is the subject. Bank loan is the subject. ..*(Interruptions)*.. The DMK Government failed to fulfil the promise made to farmers and students. ..*(Interruptions)*.. That is what I am saying. He talked about cooperative banks. The cooperative bank scandals took place more during the..*(Interruptions)*.. That is a fact. Many criminal cases are pending against them. Thank you, Madam.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता): धन्यवाद। माननीय सदस्य, श्री मिलिंद मुरली देवरा। आपके पास 8 मिनट का समय है।

श्री मिलिंद मुरली देवरा (महाराष्ट्र): मैडम, मैं सबसे पहले माननीया वित्त मंत्री जी को, सरकार को और हमारे राज्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण the Banking Laws (Amendment) Bill, 2024, लाया है। These amendments are very timely because in many cases they are modernizing provisions that are almost 75 years old. मैं आज बहुत ही confidence, विश्वास और गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इस सरकार की उपलब्धियों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम उपलब्धि यह है कि पिछले 10 वर्षों में हमारे public sector banks का पूरी तरह से clean-up हो चुका है। यह बहुत बड़ी बात है। 2018 में पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एनपीएज़ का परसेंटेज almost 15 percent हुआ करता था। सितम्बर, 2024 में Non Performing Assets are only 3 per cent. इसके साथ-साथ, last year सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मिला कर, उन्होंने 1.41 लाख करोड़ रुपए का unprecedented record profit कमाया है and, by the end of this year, the public sector banks will earn almost one-and-a-half lakh crore rupees of net profits. This is unprecedented and I

congratulate the Government. I congratulate the Prime Minister and the Finance Minister for very, very bold reforms to achieve this objective.

इसके साथ-साथ, 2014 में पीएम जन-धन अकाउंट की average balance 1,065 रुपए हुआ करती थी, लेकिन 2024 में उसकी average balance 4,400 रुपए है। यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ।

बिल में ऐसे बहुत सारे प्रोविजन्स हैं, जिनके बारे में मैंने कहा है कि 75 साल से इस सेक्टर को एक प्रकार से नजरअंदाज किया गया, ignore किया गया। One good initiative is to increase the tenure of Directors of Cooperative Banks from eight years to ten years. The MoS of this Ministry is sitting here. I would suggest that there are many kinds of banks in this country. There are Cooperative Banks, there are Scheduled Commercial Banks and there are SFBs, which are Small Finance Banks which RBI is giving licenses to. It will be a good suggestion to have uniformity across banks in terms of the tenure of the Directors. This will bring governance standards in alignment with the Companies Act.

An outdated provision of the 1949 Act limited MDs and EDs — 'EDs' means 'Executive Directors', not the other ED -- of banks to own only 5 lakh rupees worth of shares in other companies. This has been increased to Rs. 2 crores. I commend the Finance Ministry for addressing what was a very long overdue issue which successive Governments should have considered in the last 75 years. ...(*Interruptions*)... I am coming to you, Jairamji.

Another very progressive reform, which is a very important reform, जब लोग बैंक अकाउंट खोलते हैं, they are allowed to nominate only one nominee. This Bill provides for a depositor to nominate four people, which gives a lot of flexibility to the depositors, and I congratulate them.

There are a few suggestions that I have more than a speech. मैंने Small Finance Banks को highlight किया। In the last few years, the Small Finance Banks have done very well for this country. They are mandated to open 25 per cent of their branches in rural, unbanked areas. In the last few years, from 2016 to 2021, the Small Finance Bank branches have increased from 415 to 5,107 branches. Their deposits have increased by 32 per cent in the last three years from 2020 to 2023. But there are some discrepancies between Small Finance Banks and Scheduled Commercial Banks. For Small Finance Banks, the priority sector lending — it is 40 per cent of adjusted net credit banks for Scheduled Commercial Banks -- is 75 per cent. Similarly, CRAR for SFBs is 15 per cent, whereas, for other banks, it is 11.5 per cent. I think it is time to align the CRAR and Priority Sector Lending between Small Finance Banks and Scheduled Commercial Banks. आज हमारे देश में एक बहुत ही significant change underway है। 2014 के पहले भारत के लिए कहा जाता था, "It is a nation of

Savers. Today, under the reforms of this Government, India has become a nation of investors. One startling statistics, very important statistics; in 2014, assets under management of mutual funds were less than ten per cent of bank deposits. Today, they are 31 per cent and are steadily growing. While this is a good trend -- I come from Mumbai; this is a good trend -- it is deepening our capital markets and it is reducing our dependence on short-term foreign inflows, it is also creating one concern and one challenge for all banks, whether it is PSUs or private sector banks. As more capital is moving towards equity markets, banks are finding it increasingly challenging to retain depositors and to attract new depositors.

I have a few suggestions to ensure that we can retain the depositors that banks have and attract depositors. There is no question that banks cannot make current and savings accounts as competitive as other products and other asset classes that are out there. But, for instance, आज यदि एक आम investor एक debt mutual fund में invest करता है, then, the debt mutual fund attracts a tax only upon redemption of that debt mutual fund, not on accrual of interest. But, if a depositor invests in a fixed deposit, that tax is accrued and charged upon accrual of interest, which is very different. If the Government brings these in alignment -- maybe you can do this for a tenure of only five year fixed deposits — it will make fixed deposits as competitive as debt funds and will allow banks to retain depositors and to attract new depositors, who are otherwise moving towards other asset classes, to invest their money. Now, why is this important? That is because today, if banks are flushed with funds, they can lend to MSMEs, which account for 45 per cent of India's manufacturing. The more banks have money, the more they can lend at cheaper rates and fuel India's economy.Another very, very serious challenge before banks, public sector and private sector, मैंने इस सदन में कई बार अपने भाषण में कहा कि UPI केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए एक बहुत बड़ी achievement है। कुछ महीने पहले, I think it was December or January, in one month, India recorded a historic 17 billion transactions under UPI. But, today, the two main companies that are running on UPI platforms are *GPay* and *PhonePay*. ...*(Time-bell rings)*....

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता): माननीय सदस्य, अब आप conclude करें।

श्री मिलिंद मुरली देवरा: मैडम, मेरे पास अभी टाइम है। मुरुगन जी ने मुझे समय दिया है।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. L. MURUGAN): He is speaking very well on an important topic. Let him continue.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता) : ठीक है, पांच मिनट।

SHRI MILIND MURLI DEORA: Madam, I have one suggestion on UPI. Companies that are running on UPI's platform today, who have 90 per cent market share, are *PhonePay* and *GPay*. *PhonePay* is owned by Walmart and *GPay* is owned by *Google*. While we are proud of UPI's success, 90 per cent of UPI is run by American companies. One thing is very clear. While UPI has done very well, it also shows that our banks, public sector and private sector, are not innovating enough. I would like to give a suggestion to the Finance Ministry; we have to encourage innovation in our banking system. हमें banking system को disruptor बनाना है। If we do not innovate efficiently, the banking sector can be disrupted by new technologies. आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर *DeFi*, decentralized finance,पर चर्चा हो रही है। There is embedded finance. These are future technologies which are circumventing banks and allowing people to borrow and lend directly without banking intermediaries. अभी यूएस सरकार डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद decentralized finance, खासकर block chain technology को एक प्रकार से बहुत encourage कर रही है। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूँगा कि हमारे भारतीय बैंक्स को भी, चाहे वे public sector banks हों या private sector banks हों, we must encourage innovation and be open-minded. Embedded finance भी हमारे देश में एक नया trend है। Embedded finance market is about six billion dollars today. It is expected to be 30 billion dollars by 2029. जैसे, ओला और अमेजॉन जैसी जो कंपनियां हैं, वे अपने platforms पर ही insurance products को बेचती हैं, distribute करती हैं। इससे यह होता है कि banks की जो visibility है, वह customer के दिमाग में कम होती है। So, we have to encourage innovation in the banking sector, especially when it comes to DeFi or embedded finance, if we want to be disruptors and not be disrupted.Since my dear friend, Shri Jairam Ramesh, raised one point, I would like to tell about one more achievement. मैंने कहा कि one very big achievement of the Government is to clean up the banking sector. The second very big achievement of the Government, especially when it comes to banking, is that there is a convergence between what the Finance Ministry is doing and what the Environment Ministry is doing. I would like to quote someone. He said, "Corruption and delayed planning permits, or land and environmental clearances under the UPA Government, contributed to the build-up of Non-Performing Assets post the global financial crisis on Indian banks." These are not my words; these are the words of Raghuram Rajan. ...(*Interruptions*)... Raghuram Rajan said that the Environment Ministry and the Finance Ministry used to work in different directions. Today, Mr. Jairam Ramesh and Mr. Chidambaram sit

close to each other. One was the former Finance Minister; one was the former Environment Minister...

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): You were also a Minister.

SHRI MILIND MURLI DEORA: But still, you have a lot to answer for that. The derailing of the banking sector, which led to NPAs, was a direct result of this divergence and, today, I congratulate the Government and the hon. Prime Minister for converging. What the hon. Prime Minister says is a national priority, every Ministry takes part and plays towards that agenda. That is very, very critical for us to grow. I would only say, in conclusion, that these Amendments are very timely. In many cases, they are reversing 75 years of successive Governments that they have overlooked. It is a very positive thing. I think that these will make our banking sector, our financial sector, public sector banks and private sector banks far more competitive, not just in India, but globally. I thank the Government and congratulate the Government for this.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता) : माननीय सदस्य, श्री संजय सेठ। आपके पास बोलने के लिए 15 मिनट का समय है।

श्री संजय सेठ (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बैंकिंग के इस कानून संशोधन विधेयक में सात कानूनों में बदलाव किया गया है, जिससे बैंकिंग प्रणाली को आधुनिक, transparent और reformed बनाने में मदद मिलेगी। इससे बैंक अपनी दिशा बदलने में भी कामयाब होंगे।हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने जब 2014 में सरकार बनाई थी, तब हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व में 11वें स्थान पर थी। आज हमारी अर्थव्यवस्था पाँचवें स्थान पर है और प्रधान मंत्री जी की यह सोच है कि अगले पाँच वर्षों में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेंगे। बैंकिंग क्षेत्र में किए गए ये संशोधन इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेंगे। हमारे प्रधान मंत्री जी ने बैंकिंग सेक्टर को और अधिक मजबूत बनाने के लिए जो प्रतिबद्धता व्यक्त की है, उसे पूरा करने के उद्देश्य से ये संशोधन लाए गए हैं। इस विधेयक के माध्यम से Reserve Bank of India Act 1934, Banking Regulation Act 1949, State Bank of India Act 1955, Banking Companies Acquisition Transfer of Undertaking Act 1970 and 1980 में संशोधन किया गया है।

उपसभाध्यक्ष महोदया, जो पहला संशोधन किया गया है, वह बैंकों की डेटा रिपोर्टिंग से संबंधित है। पहले यह रिपोर्टिंग हर महीने के अंतिम शुक्रवार को होती थी, लेकिन अब इसे प्रत्येक माह की 1 से 15 तारीख के बीच आने वाले अंतिम शुक्रवार और 15 से 30 तारीख के बीच आने वाले अंतिम शुक्रवार को करने का प्रावधान किया गया है। इससे हमारा डेटा अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से प्रस्तुत किया जा सकेगा। दूसरा संशोधन Banking Regulation Act, 1949 की धारा 5(nc) में 'substantial interest' की परिभाषा को संशोधित करता है। इसमें वर्तमान में 5

लाख की सीमा को 2 करोड़ रुपये की सीमा चुकता भूमि पूंजी का 10 परसेंट बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिससे पारदर्शिता, सुरक्षा सुनिश्चित होगी और हितों के टकराव को कंट्रोल किया जा सकेगा। तीसरा अमेंडमेंट धारा 10ए के तहत co-operative banks में Directors के कार्यकाल को आठ साल से बढ़ाकर दस साल किया गया है, जिससे सारी व्यावहारिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। जो हमारे यहां unclaimed deposits हैं, उनमें 28 परसेंट की बढ़ोतरी हुई थी। मार्च, 2023 में बैंकों में इस तरह का unclaimed पैसा करीबन 42,272 करोड़ रुपये था। इसका मेन कारण यह था कि जो उत्तराधिकारी होते थे, वे ठीक से नहीं हो पाते थे, उनको रुपये नहीं मिल पाते थे। इस संशोधन के द्वारा हम लोगों ने चार लोगों को नामित करने की एक सुविधा दी है, जिससे वे unclaimed deposits को ले सकेंगे। चाहे वह लॉकर के अंदर पैसा हो, चाहे वह अकाउंट के अंदर पैसा हो, तो उनको इसके थ्रू एक बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। चौथा संशोधन धारा 16 में Central co-operative banks के Directors को State co-operative banks के बोर्ड में कार्य करने की अनुमति दी जा रही है। यह सहकारी बैंकों के संघीय ढांचे की प्रभावशीलता सुनिश्चित करेगा। एक संशोधन बैंक्स को statutory auditors को remuneration के निर्धारण के अधिकार प्रदान करता है। इससे बैंक को गुणवत्तायुक्त audit services मिल सकेंगी, जो बैंक्स चाहेंगे, तो अच्छे ऑडिटर्स को ले सकेंगे और उनको उस तरीके से पैसा दिया जा सकेगा। ये सभी प्रावधान बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाएंगे। 2014 में जब प्रधान मंत्री जी ने यह सरकार बनाई थी, तो उनको एक सबसे बड़ी समस्या बैंकिंग सेक्टर की मिली थी। सबको मालूम है कि 2014 से पहले राजनीतिक दबाव के अंदर आयोग व्यवसायों और अपने चहेते पूंजीपतियों को बैंकों पर फोन करके लोन दिए जाते थे, जिसका न कोई risk assessment होता था, न due diligence होती थी और इसके उदाहरण विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और ऐसे कई सैकड़ों लोग हैं, जिन्होंने बैंकों का रुपया हड़प रखा है। इसका यह परिणाम हुआ कि बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह से चरमरा गया। सच्चे व्यापारियों को ऋण नहीं मिल पा रहा था और बैंकिंग सेवाएं केवल 53 परसेंट लोगों तक ही सीमित रह गई थीं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग निजी साहूकारों से बड़े ऊंचे ब्याज पर रुपये लेते थे। इसके लिए पूर्व आरबीआई गर्वनर ने भी यह माना है कि यूपीए के भ्रष्टाचार ने ही एनपीए की समस्या को जन्म दिया था, लेकिन मोदी जी की सरकार ने सिर्फ नारे नहीं दिए, बल्कि एक्शन लिया और 3,20,000 करोड़ रुपये बैंकों में डालकर इसको दोबारा जिंदा किया। हमारी सरकार ने 4 Rs - 'recognition, resolution, recapitalisation and reform' की नीति अपनाई है। Asset Quality Review के जरिए छिपे एनपीए को उजागर किया गया है और उन्हें छुपाने की जो चालें थीं, उनको खत्म किया गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि आज बैंकिंग सेक्टर स्वस्थ, प्रोफेशलनी मैनेज्ड और आर्थिक रूप से सक्षम है। आज बैंक्स रिकॉर्ड प्रॉफिट कमा रहे हैं। पिछले 10 सालों में, 10 लाख तक के लोन्स में 238 परसेंट व 50 लाख तक के लोन्स में 300 परसेंट की वृद्धि हुई है। इससे छोटे व्यापारी और एमएसएमई सेक्टर को सशक्त किया गया है। हमारी सरकार ने बैंकों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें से एक आईबीसी कोड है। इसमें इसका प्रावधान है कि खराब ऋणों की तेजी से वसूली की जा सके। उपसभाध्यक्ष महोदया, 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018' के तहत 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति बैंकों को वापस मिली है। यह बात सभी को ज्ञात है कि बड़े और डेवलप्ड देशों में बैंक्स किस तरीके से डूबे और लाखों लोगों का धन उनमें फँस गया, खत्म हो

गया, परंतु हमारे देश के बैंक्स मजबूती के साथ इकोन्मी को बढ़ा रहे हैं और लगभग तीन लाख करोड़ रुपए का मुनाफा भी कमा रहे हैं। मैं इसके लिए आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री को बहुत-बहुत धन्यवाद भी देना चाहूंगा।

उपसभाध्यक्ष महोदया, जब कोरोना का वक्त था, तब सारे विश्व की अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से चरमरा गई थी, परंतु हमारे देश में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी अर्थव्यवस्था को न केवल संभाला, बल्कि उसको आगे भी बढ़ाया। उसके लिए बैंकों से, जो बिजनेस कर रहे थे, उन सबको एडिशनल लोन दिला कर, उनके बिजनेस को चलाया, ताकि उन्हें जब भी पूंजी की जरूरत हो, वे उसमें से निकाल कर अपने व्यवसाय को चला सकें और यही वजह है कि आज हमारा देश बैंकिंग में, इंडस्ट्री में और बिजनेस में बहुत आगे चल रहा है। उपसभाध्यक्ष महोदया, आज इन सुधारों के परिणामस्वरूप भारतीय बैंकिंग क्षेत्र मजबूत और स्थिर है। 2014 से 2024 के बीच बैंकों की जो शाखाएँ थीं, उनमें वृद्धि हुई है। अभी विपक्ष के एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि बैंकों के अंदर बड़ा मिस्मैनेजमेंट है, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि पहले उनकी शाखाएँ 1,17,900 थीं, जो अब बढ़कर 1,65,000 हो गई हैं और ग्रामीण शाखाओं की संख्या 41,855 से बढ़कर 55, 372 हो गई हैं। महोदया, इसी तरह सेमी अरबन शाखाएँ, 32,504 से बढ़कर 45,314 और अरबन शाखाएँ, 21,007 से बढ़कर 29,276 हो गई हैं। यह विस्तार ग्रामीण और शहरी भारत के वित्तीय समावेशन को मजबूत करता है। महोदया, 'प्रधानमंत्री जनधन योजना' के तहत आज रिकॉर्ड 53 करोड़ अकाउंट्स खुले हुए हैं, जिनमें कुल 2,37,000 करोड़ रुपये जमा हैं। इसमें पहले, 2015 में जो औसत बैलेंस 1,065 रुपये का था, वह अब 4,397 रुपये का एवरेज बैलेंस हो चुका है। महोदया, महिलाओं और छोटे व्यापारियों को 'पीएम मुद्रा' और 'पीएम स्वनिधि' योजनाओं के लाभ मिल रहे हैं, जिससे छोटे ठेलेवाले और खोमचेवाले लोगों को लाभ मिल रहा है। महोदया, उसमें से 68 परसेंट मुद्रा लोन महिलाओं को दिया जा रहा है। महोदया, आज हमारे डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हमारे देश के अंदर ही नहीं, बल्कि विश्व में भी सबसे ज्यादा हो रहे हैं। एक छोटे से ठेलेवाला व्यक्ति भी स्कैन कराकर अपना सामान बेच सकता है। यह हमारे देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे 'रुपे' का जो कार्ड है, प्रधानमंत्री जी ने उसको यूएई के अंदर भी चलवाया है और यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं यूपी से आता हूं, वहां डबल इंजन की सरकार के तहत रिकॉर्ड विकास हो रहा है। आज यूपी की अर्थव्यवस्था 27.5 लाख करोड़ रुपये की हो चुकी है। यूपी की बैंकिंग की जो व्यवस्था है, उसमें शानदार प्रगति हुई है। 2017 में बैंकों का कारोबार 12.3 लाख करोड़ रुपया था, जो आज 29.66 लाख करोड़ रुपया हो चुका है। हमारे प्रदेश का सीडी रेश्यो 46 परसेंट से बढ़कर 61 परसेंट हो गया है। आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार यूपी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में देश का नंबर एक राज्य बन गया है और जिसकी हिस्सेदारी 16.2 परसेंट है। आज यूपी में 3 लाख करोड़ रुपये से ऊपर के लोन दिए जा चुके हैं। एमएसएमई के क्षेत्र के लिए पहली बार सरकार ने collateral free loans की सुविधा दी है, जिसमें प्लांट और मशीनरी खरीदने में बहुत मदद मिल रही है। इसके साथ-साथ एजुकेशन लोन्स भी 2017-18 में 71,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024 में 1.3 लाख करोड़ रुपया हो गया है। एजुकेशन लोन में भी 7.5 लाख रुपये तक का लोन बिना किसी collateral और मार्जिन मनी के दिया जा रहा है। यह शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, ताकि हमारा पूरा देश शिक्षित हो और अपने हाथों से खुद काम कर सके। किसान

का जो क्रेडिट कार्ड है, उसकी संख्या 2013 में 6,46,000 करोड़ थी, वह अब बढ़कर 7,75,000 करोड़ हो गई है। इन खातों में आज जो ऋण का अमाउंट है, वह 3,63,000 करोड़ रुपये से बढ़कर अब 9,81,000 करोड़ रुपया हो गया है। अटल पेंशन योजना में भी 7 करोड़ ग्राहक हैं, जिनमें 47 परसेंट महिलाएं हैं। आज बैंकिंग सेवाएं देश के हर कोने में पहुंच रही हैं और ये उपलब्धियां इस बात का प्रमाण हैं कि मोदी सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र को सही दिशा में आगे बढ़ाया है। ...(**समय की घंटी**)... इसी के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (**श्रीमती धर्मशीला गुप्ता**)**:** धन्यवाद। माननीय सदस्य, श्री प्रमोद तिवारी जी। आपके पास 11 मिनट हैं।

श्री प्रमोद तिवारी (राजस्थान)**:** मैडम, मेरा 12 मिनट का समय है।

उपसभाध्यक्ष (**श्रीमती धर्मशीला गुप्ता**) **:** आपके पास 11 मिनट का समय है।

श्री प्रमोद तिवारी: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं इस संशोधन विधेयक को बहुत देर से देख रहा था। इसमें मेरी समझ में एक ही बात आई कि इस सरकार की न तो नीति दुरुस्त है और नीयत तो आदतन खराब है। ...(**व्यवधान**)... इसके पीछे इनका इरादा किसी तरीके से 51 परसेंट, जो सार्वजनिक उद्योग में होना चाहिए, उसको कम करना है। बैंकों की शुरुआत इंदिरा गांधी जी के जमाने में हुई थी। ...(**व्यवधान**)... यह समझ में नहीं आएगा। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। मैं फिगर दे रहा हूं, अगर किसी में हिम्मत है, तो वह अपने जवाब में काट देगा। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1959 में एसबीआई के सात सहायक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वर्तमान में ये 12 रह गए हैं। अगर यह फिगर गलत हो, तो बता दें। मैं कहना चाहता हूं कि 2021 तक कुल 27 छोटे आकार के सहकारी बैंकों का लिक्विडेशन किया गया, जबकि 42 सहकारी बैंक विलय के कारण बंद हो गए। 2018 से दिसंबर, 2022 तक लिक्विडेशन के अधीन बहुराज्य सहकारी बैंकों की संख्या पांच थी। पिछले 10 वर्षों में 2021 तक कुल 91 बैंक, मुख्य रूप से सहकारी बैंकों का liquidation, एकीकरण और पुनर्गठन किया गया। एक बात, जो किसी को भी तकलीफ देगी, वह यह है कि 26 सार्वजनिक बैंकों की 3,400, थोड़ी-बहुत नहीं, 3,400 branches बंद कर दी गई हैं, तो मैं इसमें नीयत पर शक नहीं करूँ, तो क्या करूँ! यह जनता को सुविधा देने के लिए है कि जनता की सुविधा छीन लेने के लिए है! इनमें से 75 प्रतिशत प्रभावित शाखाएँ, जो बंद हुई हैं, वे स्टेट बैंक की हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारतीय महिला बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर & जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर का 1 अप्रैल को विलय कर दिया गया। 2019 में विजया बैंक और देना बैंक का भी विलय कर दिया गया। फिर एक और चीज के ऊपर आ जाइए। कर्ज माफी के दो वर्ग हैं। एक वर्ग में बड़े-बड़े पूँजीपति हैं, जिनके सहारे सरकार चल रही है, जो सरकार को चला रहे हैं और एक वर्ग में किसान हैं। मैं दोनों को compare किए देता हूँ। 2014 में आपने किसानों की कर्ज माफी की बात की और कुल 1,59,590

करोड़ रुपए राज्यों ने माफ किए और कहा 2,25,000. जब वित्त मंत्री जी जवाब दें, तो मेरे आँकड़े सही हैं कि उनके आँकड़े सही हैं, बता दें। अब मेरा एक सवाल है, जिसको मैं बहुत चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ, 16 लाख करोड़, थोड़ा-बहुत नहीं, यह माफ हुआ है! ...(**व्यवधान**)... अच्छा है, हम सदन में बैठे हैं, किसी गली में नहीं बैठे हैं। मैडम, 16 लाख करोड़ बट्टे खाते के नाम पर माफ किया गया! मेरा सिर्फ इतना कहना है कि किसान का नाम ले लें, किसका माफ़ किया और अगर हिम्मत है, तो आज इस एक्ट को पास कराने के पहले 16 लाख करोड़, जो बट्टे खाते में डाला गया, किसका डाला गया, उसका नाम बता दें, यह मेरी चुनौती है। नहीं बता सकते, क्योंकि मालिक लोगों का है। मालिक लोगों के सामने इनकी ज़ुबान नहीं खुल सकती। मैं फिर चुनौती दोहराता हूँ, 16 लाख करोड़ किसका माफ हुआ है, बता दें। हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने अपनी सरकार में किसानों की 70 हजार करोड़ की कर्ज माफी की थी और आपने एक पैसा नहीं किया। £ फर्क सिर्फ इतना है, कर्ज माफी के दो सेक्शंस हैं। मैं कहना चाहता हूँ, इतना ही बता दें, अभी हाल में किसी को नहीं बख्शने वाली सरकार ने 200 करोड़ रुपए किसका माफ किया है? यह बता दें, वरना हम बता देंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यह जुर्माना पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने के लिए हुआ था, यानी पर्यावरण के गुनहगार का भी आप माफ कर देंगे! मैं फिर एक बार आपके माध्यम से चुनौती देता हूँ कि 16 लाख करोड़ जिनके बट्टे खाते में डाले गए, आप उनका नाम बता दीजिए। देश में जो बदनामी थी, वह तो थी ही, अब तो विदेशों में भी इस बात की बदनामी है। £

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता): माननीय सदस्य, आप बिल पर ही बोलें। कटाक्ष न करें, बिल पर बोलें।

श्री प्रमोद तिवारी: मैडम, मैं बिल पर तभी बोलूँगा, जब बैंकिंग की कार्यपद्धति पर बोलूँगा और बैंकों की कार्यपद्धति पर नहीं बोलूँगा, तो बैंकिंग पर क्या बोलूँगा, प्लीज़। मैं आपसे एक बात कहना

4.00 P.M.

चाहता हूँ कि अब तो बदनामी अमेरिका तक पहुँच गई है, यह सारी दुनिया ने देखा। अब एफबीआई के छापे - सबको मालूम है कि एफबीआई किसकी एजेंसी है; न्याय विभाग की जांच - सब कुछ मालूम है, लेकिन बोल नहीं सकते। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि एक तरफ यह हालत है और दूसरी तरफ जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसके लिए शर्म आनी चाहिए। जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनमें से 80 प्रतिशत वैसे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जिन्होंने इनका कर्ज नहीं चुकाया है। 80 प्रतिशत आत्महत्या करने वाले किसान वैसे हैं। मेरी एक फिगर है, जो मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ। ये मुझे बता दें कि क्या यह गलत है? 58 फीसदी किसान कर्ज के बोझ से दबे हैं और 47,000 का कर्ज प्रत्येक किसान पर है। ...(**व्यवधान**)...मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आज की बैंकिंग प्रणाली इस समाज के वंचित लोगों के लिए काम नहीं

£Expunged as ordered by the Chair. £ Expunged as ordered by the Chair.

कर रही है। बैंकों की शाखाएं बंद हो रही है, बैंकों में KYC का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है। ये सारी चीजें हैं। कॉरपोरेट में टैक्स की जो छूट दी जा रही है, 2019 में सार्वजनिक निगमों ने 3.4 लाख करोड़ बचत की है, जबकि कटौती के माध्यम से 8.22 लाख करोड़ अर्जित हो गए हैं। इन्होंने टैक्स छूट को बढ़ावा तो दिया, परन्तु इसका एकमात्र परिणाम बड़े व्यवसायियों की जेब भरनी थी, उसकी यह फिगर है। ऋण माफी – जान-बूझकर चूकने वाले लोग, चाहे वे मेहुल चौकसी हों, वे मेहुल भाई, ये वही मेहुल भाई हैं, जो ...(**व्यवधान**)... मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। 5 साल में बैंकों ने 9 करोड़, 90 लाख की बड़ी धनराशि - 9 लाख करोड़ को ऋण माफी में डाल दिया है। 20 परसेंट जनधन खाते बंद हो गए, फिर भी शर्म नहीं आती। बड़ा अच्छा है, ठीक है! 10 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने अभी तक किसानों की कोई कर्ज माफी नहीं की। सरकार फसल खराब होने पर, सूखा पड़ने पर किसानों के साथ आज क्या कर रही है? ये आम जनता से भारी जुर्माना वसूल रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में न्यूनतम बैलेंस न बनाए रखने के लिए आम जनता से 8,495 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया और बड़े लोगों को उपकृत किया गया। केंद्रीय सहकारी बैंकों के निदेशकों को राजकीय सहकारी बैंकों के बोर्ड में सेवा देने की अनुमति - केंद्रीयकरण और सरकारी संघवाद को कमजोर करने के लिए उनका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। ऐसा क्यों, वह मेरे दोस्त अभी बोल कर गए हैं।

अब KYC की बात है। बार-बार KYC update का समाधान नहीं किया जाता है। मैं अगर कहूँ कि देश की तीसरे व्यक्ति - मैं अभी भी उनका नाम लेने से बच रहा हूँ, लेकिन अगर आप बोलेंगे, तो मैं ले लूंगा। परन्तु घरेलू बैंक और NBFC का कर्ज बढ़ गया है। ग्रुप के कुल कर्ज में उनका हिस्सा आपके कार्यकाल में 36 परसेंट तक पहुंच गया है। 31 मार्च, 2024 तक इस ग्रुप पर 2,41,394 करोड़ रुपए का कर्ज था। वह आंकड़ा जो बढ़कर 31 मार्च तक 36 परसेंट तक पहुंच चुका था, वह अब घटकर 31 पर आ गया है। इसमें कहीं तो एक हद होगी। अगर गरीब किसान पैसा नहीं चुका सके, तो उसे जेल और जब इनके दो-तीन लोग, जिनके सहारे इनकी सरकार चल रही है – देखिए, मैंने जब कहा कि मैं नाम ले लूंगा, तो सब चुप हो गए, इनकी हिम्मत ही नहीं है। ...(**व्यवधान**)... इनकी हिम्मत ही नहीं है कि उनका नाम आने दें। ...(**व्यवधान**)... महोदया, मैं सिर्फ इतना ही कह कर आपसे विदा लूंगा [£]

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता): माननीय सदस्य, कृपया कन्क्लूड करें।

श्री प्रमोद तिवारी : यह किसान विरोधी सरकार है। यह किसानों के खिलाफ है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI DHARMSHILA GUPTA): Hon. Member, please conclude. आपका समय समाप्त हुआ।

[£]Expunged as ordered by the Chair.

श्री प्रमोद तिवारी: वहीं इधर, जो इंदिरा गांधी जी ने सपना देखा था, वह किसानों का था, आम आदमी का था। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने इतनी देर तक बर्दाश्त किया।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता): धन्यवाद। श्री हारिस बीरान। माननीय सदस्य, आपके पास 3 मिनट का समय है।

SHRI HARIS BEERAN (Kerala): Madam, there are five Acts which have been amended in a single stroke. Now, whether it is a fair legislative practice to amend five separate Acts in a single stroke, I think, this House has to ponder over it. Now, Madam, I have got certain issues and concerns with regard to this particular Bill. First is, Section 16 of the Banking Regulation Bill that proposes amendment to allow directors of the Central cooperative banks to also serve on the State cooperative boards. This raises severe concerns with regard to governance. This also raises potential conflict of interest because this is a double role for a director. He can be a director in the Central board as well as the State board. This also has an increased risk of mismanagement and this may also compromise the autonomy of the State cooperative banks. There is no clear justification as to why this has been introduced in this new Bill. It is against the spirit of the cooperative movement and I urge the Finance Minister to delete this provision relating to Section 16. Secondly, on the cyber security and banking fraud, this is a household name now. Banking fraud is a household name. Every second person is affected by banking frauds. But this Bill does not make any mention about the cyber security and banking frauds which is implemented in the public sector bank. There are specific challenges in safeguarding the financial data against the cyber threats. I would just share two or three statistics. From 1.4.2001 to 31.10.2023, Rs.8,586 crore have been lost through banking frauds. Now, only Rs.4.15 crores out of this money could be returned to the victims. So that means Rs.8.60 crore per day on an average is being lost or looted from hapless victims.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*.)

Now, Sir, recovery of money to hapless victims is a very lengthy process. The investigating agencies would have actually caught the accused. They would have got the money also. But to retrieve the money and give it back to the victims, hapless victims, is a very, very lengthy process. There is nothing mentioned in this particular statute so that the hapless victims get back their money which they have lost. There should have been some provision in this particular statute on that. Another problem, which is encountered, is about this CIBIL. We all know that there is this CIBIL rating

on the basis of which the loans are being sanctioned to individuals. But nobody knows what CIBIL is, who CIBIL is and what the legal sanctity of this CIBIL is. There is no transparency. ...(*Time-bell rings*)... Just 30 seconds, Sir. The Government should have incorporated this as a part of the legislation. I am just concluding. One another issue which I have to encapsulate is that the bank deposit growth is lagging behind the loan growth. Therefore, there is no money now in the banks because everybody is going to invest in other investments. ...(*Time-bell rings*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Please conclude.

SHRI HARIS BEERAN: In conclusion, certain provisions therefore actually warrant deeper scrutiny and require reconsideration or revision. I, therefore, urge the Government to adopt cautious and consultative approach.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Shri Haris Beeran. ...*(Interruptions)*... Nothing is going on record now. Shri P. P. Suneer, three minutes.

SHRI P. P. SUNEER (Kerala): Thank you, hon. Deputy Chairman, Sir, for this opportunity. Due to paucity of time, I would only briefly touch on the issues facing our banking ecosystem. Under the BJP's rule, India's banking system has been repeatedly mismanaged to favour large corporate interests while bank employees, students, youth and ordinary citizens suffer. Over the past ten years, Rs.16.35 lakh crore in bad loans have been written off benefiting corporate defaulters while common borrowers face rising penalties and long recovery pressures. This Government, that hesitates to waive off farmers and students loans, has shown no such reluctance in protecting corporate who default on thousands of crores. This is a financial system where the rich walk free while the common man bears the burden. Cooperative banks, which serve small farmers, traders and rural communities, have been systematically sidelined. While corporate banks receive Government bailouts, cooperative banks are left struggling. If we truly want financial inclusion, we must provide cooperative banks with the same level of policy support and capital access. Strengthening these institutions will empower millions of small borrowers who are often ignored by larger financial institutions. At the same time, the rise of shadow lenders and cyber fraud has created new dangers in our financial system.

Non-banking financial companies, operating without stringent oversight, pose serious risk to economic stability. Meanwhile, digital banking frauds are on the rise, leaving citizens vulnerable to financial scams. The Government must introduce stronger

regulations to rein in unregulated lenders and invest in robust cyber security frameworks to protect people's hard-earned money. The time for vague promises is over. We demand immediate action. The Government must recover public money from big defaulters instead of writing off their loans. It must fill all vacant posts in public sector banks to provide employment and improve services. The five-day banking week must be implemented to support employees and enhance productivity. Cooperative banks must receive the backing they deserve to serve the people. Strict regulations on shadow lending and better cyber security must be enforced to protect citizens from financial fraud. These are not just demands. These are necessary corrections to our banking system. The Government must act now. Thank you, Sir.

सुश्री कविता पाटीदार (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण बिल पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। महोदय, हम जानते हैं कि बैंकिंग प्रणाली किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है। बैंकिंग प्रणाली जितनी सशक्त होगी, वह उतनी ही उस देश के आर्थिक विकास में सहयोगी सिद्ध होगी। सरकार ने इस बिल के माध्यम से भारतीय बैंकिंग प्रणाली को एक नई दिशा और मजबूती देने का काम किया है, इसलिए मैं सर्वप्रथम देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, माननीय मोदी जी और वित्त मंत्री, माननीया निर्मला सीतारमण जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ।

महोदय, मैं 1893 का वह समय याद दिलाना चाहूँगी, जब भारत के एक युगपुरुष, नरेन्द्र ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व है कि 2025 में भारत के दूसरे नरेन्द्र ने उस बात को सत्यता की धरातल पर लाकर खड़ा किया है। आज हम दुनिया की अर्थव्यवस्था के पांचवें पायदान पर खड़े हैं और मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही जल्द हम तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। अगर हम 2014 के पहले का समय देखें, तो बैंकिंग प्रणाली इतनी सशक्त नहीं थी। पहले, भारत की आबादी के सिर्फ 53% लोगों के पास ही बैंक की सुविधा थी, उनके खाते थे, बैंकिंग प्रणाली बहुत ध्वस्त थी। पहले, जब ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बैंक से लोन लेना पड़ता था, तो उनके पास खाते नहीं हुआ करते थे, वे खातों से वंचित थे और इसलिए निजी क्षेत्र में जो साहूकार होते थे, जो ऋणदाता होते थे, उनसे उनको लोन लेना पड़ता था। लेकिन, पूर्ववर्ती सरकार, जो कांग्रेस के नेतृत्व की यूपीए सरकार थी, उसने कभी भी यह प्रयास नहीं किया कि प्रत्येक व्यक्ति तक हम बैंकिंग की सुविधा पहुंचाएँ, बैंकिंग प्रणाली को हम साफ-सुथरा करें, जबकि उनके राज में बैंकिंग क्षेत्र में घोर भ्रष्टाचार था, लापरवाही थी, कुप्रबंधन था, फोन बैंकिंग के आधार पर लोन दिए जाते थे। जब किसी को लोन लेना होता था, तो शक्तिशाली संबंधों के आधार पर उनको लोन दिया जाता था, मनमाने तरीके से लोन दिया जाता था, इसलिए बैंक संकट में आ गए थे और जितनी भी बैंकिंग प्रणाली थी, वह पूरी वेंटिलेटर पर आ गई थी। मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि 2014 के बाद जब भारत का नेतृत्व माननीय मोदी जी को मिला, तो उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को, हर क्षेत्र के व्यक्ति को बैंक तक पहुंचाने का काम किया। प्रत्येक व्यक्ति को बैंक की सुविधा मिले, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया और उनके ही प्रयासों का यह प्रतिफल है कि "प्रधानमंत्री जनधन योजना" के

माध्यम से आज 54 करोड़ लोगों को जनधन के खाते मिले हैं। ये वो वंचित लोग हैं, जिनका कभी भी बैंक में खाता नहीं खुला था, जिनको बैंकिंग सुविधा नहीं मिली थी। इतना ही नहीं, आज 18 लाख बैंकिंग टचपॉइंट्स हैं, जिनके द्वारा आज भारत में प्रत्येक 5 किलोमीटर पर हर व्यक्ति को ऐसी सुविधा मिली है कि वह बैंकिंग बुनियादी ढांचे का उपयोग कर सके। महोदय, हम जानते हैं कि पहले सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब भाई-बहन आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, उनकी चिंता कभी किसी ने नहीं की। उनकी चिंता पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं की, लेकिन माननीय मोदी जी ने उनकी चिंता की और उनके आंसू पोंछने का काम किया। आज "प्रधानमंत्री मुद्रा लोन" के द्वारा 30 लाख करोड़ से अधिक का वितरण माननीय प्रधान मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हुआ है। इतना ही नहीं, "स्टैंड अप इंडिया" योजना के तहत भी 30,000 करोड़ का वितरण माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया है। मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व है कि उसमें ऐसी 76% महिलाएं हैं, जिनको इस "स्टैंड अप इंडिया" योजना का लाभ मिल रहा है। माननीय महोदय, पीएम स्वनिधि के तहत 94 लाख स्ट्रीट वेंडर्स, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनकी भी चिंता की गई और उनको भी लोन देने का काम माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया है। वहीं, जन सुरक्षा योजनाओं, जैसे - प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना ने गरीबों को अनिश्चितताओं से बचाने के लिए बहुत कम प्रीमियम पर किफायती बीमा सुनिश्चित करने का काम किया है।माननीय महोदय, यदि बैंकिंग की बात हो और मैं टेक्नोलॉजी की चर्चा न करूं, तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी। टेक्नोलॉजी के प्रयोग से जीवन को कैसे बदला जा सकता है, यह देश और दुनिया को दिखाने का कार्य माननीय प्रधान मंत्री, आदरणीय मोदी जी ने किया है। मोदी जी की दूरदृष्टि का ही यह परिणाम था कि उन्होंने बहुत पहले ही डिजिटल इंडिया का संदेश पूरी दुनिया को दिया।ग्राहकों को त्वरित और पारदर्शी सेवाएं प्राप्त हों, इसलिए बैंकों में टेक्नोलॉजी के समावेशन पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष जोर दिया। उनके सशक्त प्रयासों का ही यह परिणाम है कि आज सब्जी विक्रेता, ठेले वाले और रेहड़ी वाले भी डिजिटल इंडिया से जुड़े हुए हैं। आज जब हम सब्जी खरीदने जाते हैं, तो खुले पैसे की समस्या के कारण विक्रेता को कोई आर्थिक नुकसान नहीं होता। डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से उसे पूरा भुगतान मिलता है।

आज हर व्यक्ति पैसों का लेन-देन डिजिटल माध्यम से कर रहा है। इतना ही नहीं, माननीय महोदय, आज जितनी भी जन-कल्याणकारी योजनाएं हैं, वे भी डिजिटल माध्यम से शत-प्रतिशत लाभार्थियों तक पहुंच रही हैं। चाहे वह 'प्रधानमंत्री आवास योजना' हो या 'किसान सम्मान निधि' हो, प्रत्येक हितग्राही के खाते में शत-प्रतिशत पैसा पारदर्शिता के साथ पहुंच रहा है।

कांग्रेस सरकार का वह बयान, जिसमें कहा गया था कि ऊपर से एक रुपया भेजने पर नीचे केवल 15 पैसा पहुंचता है, उसे खत्म करने का कार्य किया गया। भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम था और पारदर्शिता का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता।

माननीय महोदय, टेक्नोलॉजी के समावेशन पर माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया। बैंक, मोबाइल और आधार - इन तीनों को आपस में जोड़ा गया, इस त्रिशक्ति के कारण प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) बहुत प्रभावी हुआ और लीकेज कम हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि माननीय प्रधान मंत्री जी के कारण लगभग साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये गलत हाथों में जाने से बच गए।

इसके साथ ही, संकटग्रस्त खातों की पहचान एवं समाधान, आर्थिक अपराधियों पर कार्रवाई, बैंकों के पुनर्पूंजीकरण और सुधार की नीति के कारण 2014 के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति अधिक मजबूत हुई है और उनमें सुधार हुआ है। माननीय महोदय, इन सुधारों के कारण इतिहास रचा गया है। कहा भी गया है:

हे समय! नदी की बाढ़ जिसमें सब बह जाया करते हैं,
हे समय! बड़ा तूफान, प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं,
अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं,
लेकिन कुछ विरले होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं।

और यह इतिहास माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि बैंकिंग क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2023-24 में अपना अब तक का सर्वाधिक शुद्ध लाभ, 3 लाख करोड़ रुपये पार कर लिया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक साधुवाद देती हूं।

साथ ही, बैंक ऋण वृद्धि 16 परसेंट के दशकीय उच्च स्तर पर है और यह सब हमारी प्रभावशाली leadership के कारण संभव हो सका है। यही नहीं, सुधारों के साथ रिकवरी भी हुई है। यदि हम बैड लोन की बात करें, तो 2014 से 2023 के बीच लगभग 10 लाख करोड़ रुपये की वसूली की गई है। इसके लिए भी मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं।महोदय, इस सदन में कई बार ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की चर्चा होती है। मैं इस पर भी प्रकाश डालना चाहूंगी कि ईडी द्वारा 1,100 फ्रॉड पकड़े गए हैं, जिनके माध्यम से 65,000 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं, और लगभग 15,000 करोड़ रुपये की संपत्ति सार्वजनिक बैंकों को वापस की गई है। इन अथक प्रयासों से बैंकों का कायाकल्प हुआ है।अब, जो अधिनियम लाए गए हैं, उनके सुधारों के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगी।महोदय, अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के तहत जमाकर्ताओं के पैसे, सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुएं और लॉकर के भुगतान की प्रक्रियाओं को अधिक सुरक्षित बनाया गया है। पहले केवल एक व्यक्ति को नॉमिनी बनाने की अनुमति थी, लेकिन मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस विधेयक के माध्यम से अब एक, दो या तीन नहीं, बल्कि चार नॉमिनी रखने का प्रावधान इस विधेयक के माध्यम से किया गया है।यह बदलाव unclaimed account को सही उत्तराधिकारी तक पहुंचाने के लिए भी मदद करेगा। इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि पहले यदि किसी खाते में जमा राशि सात वर्षों तक unclaimed रह जाती थी, तो उसे IEPF (Investor Education and Protection Fund) में स्थानांतरित कर दिया जाता था। यह विधेयक IEPF में स्थानांतरित की जाने वाली नीतियों के दायरे को विस्तृत करता है। अब दावा न किए गए शेयर, बॉन्ड और ब्याज राशि भी IEPF में स्थानांतरित की जा सकेगी।इसके अलावा, सहकारी बैंकों में निर्देशकों का कार्यकाल पहले आठ वर्ष था, इस विधेयक के माध्यम से उसको 10 वर्ष तक बढ़ाने का काम माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया है।इस नए कानून के तहत एक और महत्वपूर्ण सुधार किया गया है। आरबीआई को रिपोर्ट देने की समय-सीमा बदलने की अनुमति अब बैंकों को दी गई है। वर्तमान रिपोर्टिंग Friday to Friday प्रणाली थी। इसमें कई सीमाएं थीं, जो data reporting की सटीकता और प्रभावशीलता को प्रभावित करती थीं। अब यह रिपोर्ट 15 दिन, महीने और तिमाही के अंत में की जा सकेगी। यह प्रस्तावित संशोधन न केवल बैंकों की कार्य

प्रणाली में सुधार लाएंगे, बल्कि निवेशकों और खाताधारकों के हितों को भी सुरक्षित करने का काम करेंगे।

सर, यह विधेयक भारतीय बैंकिंग प्रणाली को अधिक सशक्त, पारदर्शी, उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। यह केवल बैंकिंग क्षेत्र की कार्य प्रणाली को आधुनिक नहीं बनाएगा, बल्कि निवेशकों और ग्राहकों के हितों की रक्षा को भी सुनिश्चित करेगा। इस अधिनियम के द्वारा जितने भी सुधार किए गए हैं, मुझे लगता है कि UPA की जो कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार थी, उनके पापों का प्रायश्चित करने का काम इस विधेयक के द्वारा किया गया है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को बारम्बार धन्यवाद देना चाहूंगी कि माननीय प्रधान मंत्री जी का 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प है, उसकी तरफ एक मजबूत कदम है और यह मजबूत कदम बढ़ते कदम माननीय अटल जी के उन पंक्तियों को भी रेखांकित करते हैं:

जब तक ध्येय न पूरा होगा,
तब तक पग की गति न रुकेगी।
आज कहे चाहे कुछ दुनिया,
कल को बिना झुके न रहेगी।

सर, बैंकिंग के क्षेत्र में जितने भी fraud हुए थे, उन सारे फ्रॉड्स को उजागर करना, banking प्रणाली को सुदृढ़ करना, बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता लाना, उसमें मजबूती लाने का काम माननीय प्रधान मंत्री जी के द्वारा किया गया है और इस बैंकिंग का जो अधिनियम आया है, उसमें जितने भी सुधार किए गए हैं, उससे निश्चित ही बैंकिंग प्रणाली मजबूत होगी, उसके द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और हम जल्द ही तीसरी ताकत बनकर भारत को विश्वगुरु बनाने का जो हमारा सपना है, उसको हम पूरा कर सकेंगे और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पुनः वह दिन आएगा कि भारत विश्व गुरु बनेगा। दुनिया के मस्तक पर भारत रोली जैसा चमकेगा, वह दिन हम देखेंगे। पुनः मैं माननीय प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी जी को, देश की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी को इस बिल के लिए, इस संशोधन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं और इस धन्यवाद के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिन्द, जय भारत।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Dr. Fauzia Khan.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I understand that the Bill seeks to improve governance standards in the banking sector. While welcoming the intent, I would like to make a couple of quick suggestions. The rupees two crore threshold for substantial interest could be indexed to inflation or made dynamic based on economic conditions. Additionally, raising the threshold to rupees two crores may reduce scrutiny of smaller but influential stakeholders. Sir, the Amendments do little to address challenges faced by rural and cooperative banks such as high NPAs and

lack of technological infrastructure. While prioritizing depositor protection, the Bill overlooks systemic reforms needed to improve rural banking access and streamline credit delivery. Also, the question is whether the speed of our efforts is matching the speed at which the financial world is changing with emerging technologies. Challenges such as crypto currency, online scams, digital arrests are growing at a bewildering pace. Every new day emerges with a new challenge. Are our legislations matching the pace? Sir, Chris Skinner had said, 'Ignoring technological change in a financial system based upon technology, is like a mouse starving to death because someone moved their cheese.' The growing use of AI in this sector is creating new challenges and systemic risks due to the reliance on a small number of dominant technology providers which could lead to widespread disruptions in case of failures. Additionally, the opacity of the AI makes it difficult to audit and interpret decision-making algorithms raising concerns about unpredictable market outcomes, increased vulnerability to cyber attacks, and potential data breaches.

These emerging risks underscore the need for robust risk mitigation practices in the banking industry. Sir, Earl Wilson had said, "Money in the bank is like toothpaste in the tube, easy to take out, hard to put back." The Bill fails to address newly emerging challenges like digital arrests, cooperative bank scams, etc. About 4,016 cooperative banks have reported financial frauds during the last five years. The years of delays faced by depositors in such cases have been ignored. Sir, aadhar linking and KYC requirements in India have led to millions of accounts being frozen. Coming to counterfeit currency and its impact, particularly, five hundred rupee notes, there had been a 317 per cent rise in fake 500 rupee notes and 166 per cent in fake 2000 rupee notes, from 2018 to 2022.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

DR. FAUZIA KHAN: Sir, just give me half a minute, I am concluding. Strengthening the legal frameworks is essential. I will only say, forewarned is forearmed. I leave it to the Government to take cognizance of our suggestions. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Shrimati Sunetra Ajit Pawar; not present. Now, Dr. Sikander Kumar. You have 15 minutes.

DR. SIKANDER KUMAR (Himachal Pradesh): Thank you, Sir, for giving me the opportunity to speak on an important Bill, the Banking Laws (Amendment) Bill 2024. Sir, in 1926, the then Government of India appointed a Commission, which is known

as the Hilton Young Commission, to express their views regarding the functioning of Central Bank of our country. On the recommendations of the Hilton Young Commission, the RBI Act was passed in 1934, and the RBI started its functioning from 1st April, 1935. Earlier, the Central banking functioning were performed by the Imperial Bank of India and after the nationalization of it on 1st July 1955, it came to be known as the State Bank of India. Since then, the RBI has been acting as the central bank of our country. Sir, in the RBI Act 1934, the Banking Regulation Act 1949, the State Bank of India Act 1955, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, and the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1980, there are so many loopholes and in order to overcome these loopholes, the Finance Minister has brought this Bill, that is, the Banking Laws (Amendment) Bill 2024. I congratulate the Hon. Finance Minister for bringing this important Bill.

Sir, the Banking Laws (Amendment) Bill 2024, seeks to amend the key banking regulation with the objective to improve governance standards to provide consistency in reporting by banks to the Reserve Bank of India to ensure better protection for depositors and investors and to improve audit quality in public sector banks. The proposed amendments are a comprehensive legislative effort aimed at modernizing and enhancing the regulatory framework governing India's banking sector. Drawing lessons from past mistakes, the Modi Government is committed to rectifying previous wrongs and ensuring good governance in the banking sector. The proposed amendments are not merely regulatory changes, they represent a bold step towards enhancing transparency and accountability, safeguarding the interest of investors and rebuilding public confidence in our financial institutions. This initiative underscores a vision for a banking system that prioritizes integrity and trust, paving the way for a brighter economic future for all citizens. Sir, previously, the cooperative banking sector faced a crisis of confidence, largely due to the multi-crore loan scams involving Punjab and Maharashtra Cooperative Bank, Maharashtra State Cooperative Bank and Karuvannur Service Cooperative Bank.The scandals in the cooperative sector have created a significant trust-deficit, leaving millions of ordinary depositors vulnerable and anxious about the financial future due to a legacy of misgovernance. The NDA Government in response to the PMC scam, introduced the Banking Regulation (Amendment) Act, 2020 to enhance the management and governance of multi-state cooperative banks. The Act aimed at improving cooperative banks' management and regulation so as to protect the interests of the depositors by bringing these banks under the supervision of the RBI. To ensure good governance, increase transparency and improve access to capital while protecting investors'

interests, the Bill proposes the extension of the tenure of Cooperative Bank Directors and permits Directors of Central Cooperative Banks to serve on the Boards of State Cooperative Banks with the goal of promoting professional management and enhancing governance within cooperative institutions.

Sir, the shallow and failed attempts towards furthering financial inclusion under the UPA regime were marred by inefficiencies and a lack of genuine commitment. However, the Modi Government's *Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana* has been a game-changer by opening over 53 crore bank accounts in the past decade. The scheme is the largest financial inclusion initiative aiming at universal and affordable access to formal banking services, integrating marginalised sections int the economic mainstream. The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana's success is a reflection of the Modi Government's larger vision of banking for all, correcting the failures of the past Government that left millions unbanked and vulnerable. The Amendments proposed under the Bill collectively aim to strengthen the banking framework, making governance more transparent and financial services more accessible for marginalised groups, representing a significant step towards the Modi Government's commitment to good governance and financial inclusion for all. The previous UPA Government has failed to address the needs of the ordinary citizens and include the marginalised in the journey of success and inclusion. While the UPA-era was characterized by inefficiency and a lack of commitment to empowering the marginalized, the Modi Government has harnessed the power of the Jan Dhan-Aadhaar and Mobile Trinity to facilitate a Direct Benefit Transfer system that ensures subsidies and social benefits reach the under-privileged directly into their bank accounts, free from the clutches of middlemen. This approach guarantees that supports not only reaches the marginalized sections but also provides timely-financial assistance for essential schemes such as pensions, scholarships and subsidies for basic goods. For the first time, constitutional recognition has been granted to the National Commission for Backward Classes safeguarding OBC rights within the governance framework. The regime of neglect and exclusivity is long gone, and under the leadership of Modi Government, we are witnessing a new dawn in financial inclusion that is reshaping the future of our nation.

Sir, gone are the days when the Indian banking sector was plagued by a cesspool of bad loans, vested interests, corruption and mismanagement. Under the previous UPA Government, the banking landscape was marred by a Gross NPA ratio that soared to 12.3 per cent by September, 2013 largely due to political interference in lending decisions and the concealment of bad loans. This negligence not only eroded public trust but also inflicted significant losses on banks, jeopardizing the savings of countless depositors. But to recover and revive the banks, the Modi Government's

consistent reforms, targeted towards improving the health of the financial sector, led to a remarkable turnaround with Gross Non-Performing Assets ratio declining to a multi-year low of only 0.6 per cent.

Sir, the UPA Government neglected action towards the financial health of the banking sector led to the banking sector reaching a critical low, with banks being reluctant to lend especially to small and medium-sized enterprises that drive employment.The urgent need for its revitalization was realized by the Modi Government that made concerted efforts towards transforming the banking sector into a vital asset for economic growth and restoring public trust in financial institutions through a comprehensive four 'R' strategy of recognition, resolution, recapitalization and reforms, focused on enhancing transparency in non-performing assets, effectively resolving stressed accounts, recapitalizing public sector banks and instituting necessary reforms. The proactive approach has resulted in recoveries exceeding Rs. 10 lakh crore from bad loans between 2014 and 2023, significantly strengthening the banking ecosystem and fostering a responsible and clean financial system.

Hon. Deputy Chairman, Sir, as proposed under the present Bill, the expansion of the scope for transferring unclaimed amounts to the Investor Education and Protection Fund, IEPF, signifies the commitment of Modi Government to protect investors' interests and promote financial literacy across India. The bureaucratic inefficiencies and lack of transparency prevalent under the UPA Government led to the languishing of unclaimed funds with investors being unaware of their rights to claim them. In contrast, the Modi Government is committed to actively managing and regulating these unclaimed funds, thereby empowering investors and fostering a more transparent banking environment. This proactive approach of the Government protects investors' rights and fosters financial literacy, helping individuals make informed decisions about their investment.

Sir, under the visionary leadership of the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, the push for digitisation in the banking sector has marked a transformative shift compared to the previous UPA Government. The establishment of 75 digital banking units across various districts represents a significant step towards enhancing financial inclusion, particularly in rural and semi-urban areas. Gone are the days when digitization was merely a dream reserved for the affluent, unlike the UPA era, which struggled with inefficiencies and limited access. The Modi Government has prioritized initiatives like the Digidhan Mission and platforms such as UPI and BHIM, leading to a remarkable increase in digital transaction. Furthermore, programs like *Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana* have opened millions of bank accounts for previously

unbanked population, empowering citizens and ensuring that banking services are accessible to all, aligning with the vision of a self-reliant India. The amendments proposed under the Bill are designed to further enhance the regulation and governance of banks aiming to create a robust and reliable framework that supports the ongoing digitization of banking services and ensures equitable access for all. The drive on digitization is not just about convenience; it is about creating opportunities, driving innovation and building a more equal society. Sir, making a fundamental shift towards a better, accountable and transparent banking system, unregulated practices are over and we are witnessing a new dawn for the banking sector while the UPA Government's mismanagement left the banks vulnerable and struggling, resulting in a significant trust deficit. The Modi Government has undertaken significant reforms to rejuvenate the banking landscape, focusing on restoring confidence and enhancing service delivery for all citizens. With the proposed amendment increasing the number of nominees, allowing the appointment of up to four nominees per account, enabling simultaneous nominees, the Government aims at easing and bettering banking services for the general public. The transformation has emphasized on the critical role of a robust banking sector as a cornerstone of economic growth and development, transitioning from a period of scarcity to achieving strong banks for a strong economy with the broader vision of a self-reliant India.

Sir, in conclusion, I would like to say that the Banking Laws Amendment Bill, 2024, seeks to amend the Reserve Bank of India Act 1934, the Banking Regulations Act, 1949, the State Bank of India, Act 1955, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings Act, 1980.

The proposed Bill aims to improve the audit quality in the public sector banks, ensure consistent reporting to the RBI and extend the tenure of Directors in co-operative banks, streamlining the banking operation and aligning them with contemporary financial practices. I support the proposed Amendment. I thank all the hon. Members of this House for their support to the proposed Amendment. Thank you very much.

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Respected Chair, the public sector banks in India are protecting the economic stability of our nation. So, each and every Bill should be properly examined by this House. Over the last decade, Indian banks have written off approximately Rs.16.35 lakh crore. After 2014, every year, this Government has written off a huge amount. A huge number of people, including the poor, are depending upon banks for keeping their money. Now, the richest of the rich are

getting a lot of facilities from banks. But the facilities for ordinary people have deteriorated. Earlier, public sector banks used to give gold loans to a large number of people for agricultural activities. The interest rate was also comparatively low for this loan. It helped thousands of farmers in our country. But, now, the number of such loans has come down. So the people are compelled to go to private money lenders who are collecting exorbitant interest. That is why such companies are making huge profits. The usurers have taken a big amount from public sector banks and they are lending money to people at an exorbitant rate. The public sector banks are used as providers of money to money lenders, like the big corporates. In rural-urban divide, unavailability of credit has also increased. The leading banks have given only a marginal number of loans to villagers. The rural India is still trapped by the private money lenders. The major share of loans has been taken by the richest of the rich, a small section of the society in cities which is very close to the Union Government or part of the ruling class.

In the banking sector, a huge number of employees are working as contract labourers. They have no labour rights. The ground reality is that they have no fixed working time. Lakhs of women workers are there, but they do not have maternity leave; they have no pension scheme and they have no treatment facility. There is no reservation in the contract jobs. Increasing contractualisation is a threat to the equality of the nation and it will also ruin the credibility of the banking sector. We should oppose the contractualisation in our banks. Employees in these banks are struggling for their basic rights. The number of employees in public sector banks has declined. In 2014, the total number of employees stood at 8,42,813. However, the figure has now dropped to 7,64,679. The workload of employees has increased. Even with fixed working hours, workers are often forced to work late night, especially during the financial year and during the audit time. In banks, there should be proper criteria for transfer and posting. Frequent transfers disrupt the lives of the workers and their families. Bank employees are forced to mobilise audience for the propaganda programme of the Union Government. They are also compelled to work as agents of insurance schemes and Government money collection schemes, which provide only a pittance in return to the people.

Employees have more than 15 targets to meet due to the Government directives, most of which involve promotional work of the Union Government. In our banks, the number of transactions has increased, which is natural, but the number of complaints has also risen, which is not natural. This is due to the systemic failure. Daily Transaction Monitoring is an essential part of the banks. Loan documentation and loan recovery are also the responsibilities of the bank employees. In 2014, the

employees-to-accounts ratio was 1:1,251. By March 2024, this ratio has worsened to 1:2,686. Bank employees urgently need the right to disconnect. The right to disconnect is a labour law principle that allows employees to disengage from work-related communications outside their official working hours. Work-life balance and job satisfaction are essential parts of well-being.

The Government is trying to dislodge smaller banks by merging them. After merging, they are being privatised. International experience shows that a network of small banks is healthier for the economy. The banks' privatisation is a serious threat to the public banking system. The network of co-operative banks in Kerala is an example of robust and popular banking network, which is accessible to the common people, but the Union Government is trying to centralise the co-operative banking system. Through this co-operative banking system, we are providing a lot of facilities to the poorest of the poor in our villages. The public banking system should be protected. Privatisation and contractisation should be resisted. For that, we are requesting the Government for recruitment drive in the banking sector. That is very important. The Government should conduct the recruitment drive, and we all know that thousands of posts are lying vacant in our public sector banks. The posts, which are lying vacant, should be filled and the recruitment should be conducted in our banks. I request the Government to protect the co-operative sector and public sector banks in our nation. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shrimati Priyanka Chaturvedi.

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी (महाराष्ट्र): डिप्टी चेयरमैन सर, आपने मुझे इस important मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। सर, defaulters, loan write-off वगैरह के बारे में बहुत सारी बातें कही गईं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ बातें रखूँगी। यह जो बिल आया है, वह अमेंडमेंट के माध्यम से आया है। इस भाव से आया है कि आम आदमी को बैंकिंग सिस्टम में किस तरीके से और सुरक्षा मिल सके। पर, बनते-बनते on ground ये सब खास आदमियों के बन जाते हैं। ये सारे जो चैलेंजेज़ हैं, I am sure कि वित्त मंत्री जी खुद जानती हैं, इसलिए उस पर मैं बोलना नहीं चाहूँगी। पर, आज हमारे बैंकिंग सिस्टम में जो हो रहा है, मैं आपको उसका पूरा सार बताना चाहती हूँ। सर, एक तरफ हैं हमारे wilful defaulters और वे wilful defaulters, wilful defaulters हैं, यानी उनके पास पैसा है, वे पे कर सकते हैं, लेकिन वे पहली टिकट लेकर विदेशों में चले जाते हैं। वहाँ से अपनी अच्छी-अच्छी फोटोज़ भेजते हैं। कुछ wilful defaulters हैं, जो कहते हैं कि हमने तो इंडियन सिटिजनशिप भी त्याग दी है। वे नई कंट्री के सिटिजन बन जाते हैं, फिर हमारा देश जागता है, हमारी सरकार जागती है और उनकी सिटिजनशिप रद्द कराती है। दूसरी तरफ आम आदमी है। अगर वह एक लोन repayment में थोड़ी देर कर दे, तो कलेक्शन

एजेंट्स उसके घर पहुँच जाते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, तोड़-फोड़ करते हैं और उनको प्रेशर डालते हैं कि वे पेमेंट करें। यह हमारी खास आदमी और आम आदमी की स्टोरी चल रही है।

सर, दूसरी तरफ लोन्स राइट-ऑफ हो रहे हैं। कितने लोन्स राइट-ऑफ हो रहे हैं, उसका आँकड़ा, I am sure, वित्त मंत्री जी अच्छे से जानती हैं, मैं उसमें पड़ना नहीं चाहूँगी, क्योंकि वे नाराज हो जाती हैं, जब हम बार-बार बोलते हैं, पर हैं, राइट-ऑफ हुए हैं। उन राइट-ऑफ लोन्स के संबंध में मैं यह बताना चाहती हूँ कि जो ये लोन्स लेते हैं और उनके लोन्स राइट-ऑफ होते हैं, वे एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, उन पर जो केसेज़ हैं, वे चल रहे हैं, पर उनसे उनका कुछ खींचा नहीं जाता है।

दूसरी तरफ, हमारा जो आम आदमी है, वह गारंटी पर गारंटी दे देकर, डॉक्यूमेंट्स पर डॉक्यूमेंट्स दे देकर एक लोन पाने की कोशिश करता है। आप स्टूडेंट लोन देख लीजिए, आप एजुकेशन लोन की तरफ देख लीजिए या आप फार्म लोन की तरफ देख लीजिए। मैं उन पर नहीं जाना चाहूंगी, क्योंकि आंकड़े मैडम के पास होंगे।

सर, मैं महाराष्ट्र से आती हूँ। जो Cooperative Banks हैं - महाराष्ट्र में भी हमने देखा है कि जो regional satraps होते हैं, वे जनता का पैसा लेकर उसको किस तरीके से misuse करते हैं, उसके इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। वह गंदगी है और उसकी सफाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ, वह किसान है, जो उम्मीद करता है कि हमें कुछ रिलीफ मिलेगी, हमें कोई लोन मिलेगा, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड लोन बनाने का एक माध्यम बनेगा, लेकिन उसको उससे वंचित रखा जाता है। महाराष्ट्र में पिछले साल करीब 2,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएँ की हैं।

सर, अभी कुछ ही दिन पहले बजट पेश किया गया था। प्रधान मंत्री जी खुद Creator Economy की बात करते हैं, Content Economy की बात करते हैं और Concert Economy की बात करते हैं। Ministry of Information and Broadcasting की तरफ से WAVES नामक एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जो मुंबई में ही होगा। एक तरफ हम इस Economy की बात कर रहे हैं और हम funds allocate करते हैं और दूसरी तरफ एक Stand-up Comedian अगर कोई joke कह दे, तो वह हमारे पावरफुल लोगों को पसंद नहीं है। ...(**समय की घंटी**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on the subject. ...(*Interruptions*)...

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदीः सर, अब मैं खत्म कर रही हूँ। सर, यह विषय पर ही है, इसमें fund allocate हुआ, पर वहीं economic activity को तोड़-फोड़ कर उस पर बुलडोजर चला दिया जाता है, तो यही आज आम आदमी और खास आदमी का फर्क है। चाहे amendment हो, banking laws हों, banks हों, उनका अंतर मैंने इसी तीन मिनट में बताने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि वित्त मंत्री जी इस पर जवाब देंगी। Thank you.

श्री उपसभापतिः श्री महेंद्र भट्ट, 15 मिनट।

श्री महेंद्र भट्ट (उत्तराखंड)**:** माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया है।महोदय, जब बैंक के बारे में चर्चा होती

है, तो आज मैं कह सकता हूँ कि विश्व के अंदर अगर अर्थव्यवस्थाओं को ठीक दिशा की ओर बढ़ाने का काम किसी सेक्टर ने किया है, तो वह बैंकिंग सेक्टर ने किया है। अगर मैं भारत की दृष्टि से बात करूँ, तो 16 मार्च, 1949 को बैंकिंग कंपनी अधिनियम के नाम से इसको लागू किया गया था। 1 मार्च, 1966 को इसका नाम बैंकिंग विनियमन अधिनियम बना। इसमें अनेक बार संशोधन हुए। संशोधनों का प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि समय, काल और प्रस्तुति के अनुसार उसमें क्या जोड़ना चाहिए, जिससे हम ग्राहकों को अच्छी सुविधा दे सकते हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इन्हीं भावों के साथ ये संशोधन बार-बार किए गए। सन् 1965 में इस अधिनियम में धारा 56 को जोड़ा गया तथा देश के सभी सहकारी बैंकों पर इस अधिनियम को लागू किया गया। यह महत्वपूर्ण विषय है कि सहकारी बैंकों का आज बहुत बड़ा महत्व हो गया है। देश के अंदर उनकी गतिविधियां, उनके द्वारा किए गए कार्य आज जनता के सामने एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। 1983 में फिर संशोधन कर भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक शक्तियां प्रदान की गईं। रिजर्व बैंक के अंदर जो शक्तियां जिस रूप में दी जानी चाहिए थीं, मुझे लगता है कि तत्कालीन सदन को लगा होगा कि कुछ और अधिकार, कुछ और शक्तियां इसको दी जाएँ, उसके लिए इसमें प्रावधान किया गया। 1993 में बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही के ऊपर बल दिया गया। निश्चित रूप से, बैंक की अपनी कुछ मान्यताएँ होती हैं, बैंक के अंदर काम करने की कुछ गतिविधियाँ होती हैं, लेकिन ग्राहक को उसकी सुविधा मिले, पारदर्शिता दिखाई दे, इस भाव के साथ भी उस कालखंड में संशोधन किए गए। वर्ष 2004 में बैंकिंग क्षेत्र में स्थिरता को संशोधन से बल दिया गया। स्थिरता बैंक की बनी रहे, इसकी सबको आवश्यकता थी, क्योंकि तब देश के अंदर इस प्रकार का माहौल था कि अनेक बैंक खुलते थे और अचानक बंद हो जाते थे। आम पब्लिक का बैंक पर जिस रूप में विश्वास स्थापित होना चाहिए था, उसमें कुछ कमी दिखाई दी और विधेयक में उसकी चर्चा की गई। 2017 में बैंकों के दिवालियापन की अनेक घटनाएँ हुईं। तब यह लगता था कि जो जमाकर्ता है, उसका विश्वास कैसे अर्जित किया जाए, तो 2017 में इस विधेयक में दिवालिया और दिवालियापन से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई। सन् 2020 का संशोधन काफी महत्वपूर्ण रहा। इस संशोधन से देश के सभी सहकारी बैंकों को आरबीआई से जोड़ा गया। पहले सहकारी बैंक आरबीआई की गाइडलाइन के तहत नहीं चलते थे, इसलिए यह व्यवस्था की गई। उसी दिन 1,482 शहरी और 58 बहु राज्य सहकारी बैंकों को इससे जोड़ा गया। मैं आज के आंकड़े न कहूँ, लेकिन 2022 की जो जानकारी मेरे सम्मुख है, उसको मैं यहाँ रखना चाहूंगा। सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक, जिनकी शाखाएं आज बहुत हो गई हैं, उनकी चर्चा पूर्ववर्ती वक्ताओं ने की है, इसलिए मैं उस चर्चा की ओर नहीं जाऊंगा। इस समय निजी क्षेत्र के 22 बैंक, 44 विदेशी बैंक, 1,485 सहकारी बैंक और लगभग 96,000 ग्रामीण सहकारी बैंकों को इसके तहत जोड़ने का काम किया गया है।

महोदय, आज बैंक की जो व्यवस्थाएँ हैं और जो संशोधन की अवस्था – जो लोकसभा में 3 दिसंबर, 2024 को पारित किया गया, उसकी कुछ वैधानिक आवश्यकताएँ थीं। इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई, इस पर मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात रखना चाहूँगा।

धारा 18, 25, 27, 56 और 18 में संशोधन की क्या आवश्यकता पड़ी, इसे मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। महोदय, बैंकों द्वारा आरबीआई को नियमित रूप से रिपोर्ट देने की चर्चा बार-बार उठती

रही। पहले यह रिपोर्ट प्रत्येक शुक्रवार को दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में बैंकिंग गतिविधियाँ ऑनलाइन हो जाने के कारण सटीक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया था।आज के समय में Google Pay, Paytm, भीम ऐप जैसे कई डिजिटल माध्यम उपलब्ध हैं। इन सभी माध्यमों से प्राप्त आँकड़ों को प्रत्येक शुक्रवार को संकलित करके सही ढंग से रिपोर्ट करना आरबीआई के लिए संभव नहीं था। बैंकिंग गतिविधियों में मौसमी उतार-चढ़ाव भी होते हैं, जिनकी रिपोर्टिंग के लिए यह आवश्यक समझा गया कि प्रत्येक माह की 15 तारीख की रिपोर्ट उसी महीने की 20 तारीख तक तथा माह के अंतिम दिन की रिपोर्ट अगले महीने की 5 तारीख तक आरबीआई को दी जाए। इससे प्रामाणिकता के आधार पर आरबीआई को बैंकों की सही रिपोर्टिंग मिल सकेगी।महोदय, अब मैं दूसरे संशोधन की बात करना चाहता हूं।धारा 15 (NC) के तहत अधिनियम में व्यापक रूप से पर्याप्त हितों का उल्लेख किया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत "पर्याप्त ब्याज" को परिभाषित करते हुए जहाँ पहले उल्लेखित 5 लाख रुपये अथवा चुकता पूँजी का 10 प्रतिशत निर्धारित था, उसे बढ़ाकर अब 2 करोड़ रुपये अथवा चुकता पूँजी का 10 प्रतिशत कर दिया गया है। यह संशोधन इसलिए आवश्यक हो गया था, क्योंकि लंबे समय से हितों के टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। बैंकिंग संचालन की अखंडता बनाए रखने के लिए इस प्रकार की कानूनी व्यवस्था की गई।

अधिनियम की धारा 20 में उल्लेख है कि बैंकिंग कंपनियाँ ऐसी कंपनियों या संस्थाओं को ऋण या अग्रिम प्रदान करने से रोकती हैं, जिनमें निदेशक का पर्याप्त हित हो। इसी तरह धारा 10 यह अनिवार्य करती है कि बोर्ड के कम से कम 51 प्रतिशत सदस्य कर्मचारी, प्रबंधक, या प्रबंध एजेंट के रूप में बैंक से साथ पर्याप्त हित या संबंधों में उनको स्वतंत्रा मिलनी चाहिए।

महोदय, मैं अब तीसरे महत्वपूर्ण संशोधन पर आता हूं। यह संशोधन सहकारी बैंकों के लिए बहुत अपेक्षित हो गया था, खास तौर पर सहकारी बैंकों की दृष्टि से इस संशोधन को लाने की आवश्यकता महसूस हुई। बैंकिंग अधिनियम की धारा 10A (2A-1) के तहत अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर अन्य सभी का कार्यकाल 8 वर्ष निर्धारित था, जबकि अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक 10 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते थे। अब इस कार्यकाल को 10 वर्ष कर दिया गया है। इसका कारण यह है कि सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों और पदाधिकारियों का कार्यकाल चुनाव की तिथि से 5 वर्ष होता है। इससे व्यावहारिक कठिनाइयां आ रही थीं। इस अधिनियम के तहत सेवा करने वाले निवेशकों को इस अधिनियम का पालन करने के लिए दूसरे कार्यकाल कार्यकाल के लिए बीच में ही अपने पद को छोड़ना पड़ता था।

महोदय, चौथा संशोधन भी सहकारिता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अधिनियम की धारा 16 व्यक्तियों को एक से अधिक बैंकिंग कंपनियों के बोर्ड में नाम कटने से रोकती है। अब इस संशोधन के तहत केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक को राज्य सहकारी बैंक बोर्ड में भी कार्य करने की अनुमति दी गई है।

पूर्व में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, केंद्रीय सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों के बीच पदाधिकारियों के स्तर पर असमानता थी। प्राथमिक कृषि ऋण समिति के पदाधिकारी केंद्रीय सहकारी बैंक बोर्ड में शामिल हो सकते थे, लेकिन केंद्रीय सहकारी बैंक के सदस्य राज्य सहकारी

बैंक बोर्ड में शामिल नहीं हो सकते थे। इस असमानता को दूर करने के लिए यह संशोधन लाया गया।

महोदय, अब मैं पाँचवें संशोधन की बात करता हूं। धारा 45ZA, 45ZC, 45ZE और नई धारा 45ZG के तहत नामांकन से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया।

धारा 45ZA: जमाकर्ता के धन के भुगतान के लिए नामांकन।

धारा 45ZC: सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं की वापसी के लिए नामांकन (विशेष रूप से गिरवी रखी वस्तुएँ)।

धारा 45ZE: सुरक्षा लॉकरों में रखी वस्तुओं की सुरक्षा के लिए नामांकन।

धारा 45ZG: क्रमिक नामांकन की प्राथमिकता सुनिश्चित करने के लिए।

महोदय, कोरोना काल के दौरान ये आवश्यकताएँ सामने आईं। जब नॉमिनी (नामांकित व्यक्ति) की अकाल मृत्यु हो गई, तब बैंक खातों में जमा पूँजी लैप्स हो गई। उस पूंजी को निकालने में परिवारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब नए संशोधन में चार नामांकित व्यक्ति (नॉमिनी) दर्ज करने की अनुमति दी गई है, जिससे परिवारों को उनका धन प्राप्त करने में आसानी होगी और कानूनी प्रक्रिया भी सरल हो जाएगी।

5.00 P.M.

महोदय, छठा संशोधन काफी छोटा है। यह बड़ा संशोधन नहीं है। इसके तहत जमा बीमा निगम, डीआईसीजीसी की परिभाषा, प्रबंध निदेशक की परिभाषा और प्रायोजक बैंक की परिभाषा उल्लिखित है। इसमें केवल बैंकिंग अधिनियम संशोधन, 2020 में पेश किया गया था, उसके तहत जमा बीमा निगम की और प्रबंधन निदेशक की परिभाषा छोड़ दी गई थी। उस समय 2020 में उसका उल्लेख नहीं हो पाया था, जो सहकारी बैंक के लिए अप्रासांगिक और अव्यावहारिक बनी हुई थी। अत: उसे बहाल करने के लिए प्रायोजक बैठक की परिभाषा को इसके तहत हटा दिया गया है।

सर, धारा 35ए - दावा न किए गए लाभांश का हस्तांतरण, अवैतनिक लाभांश खाते में हस्तांतरण से जुड़ा है। इसमें यह सुनिश्चित होगा कि बिना दावे वाले शेयर, ब्याज या बॉन्ड, redemption राशि भी IEPF, निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतिरत की जा सकती है। पहले इसका प्रावधान नहीं था, अब इसको जोड़ा गया है और इसको लागू किया गया है। इसमें निवेशकों की सुरक्षा को बढ़ाया गया है।

उपसभापति महोदय, धारा 41- लेखा प्रशिक्षण अधिनियम, 1955 है। महोदय, इसकी धारा 10 में संशोधन का प्रस्ताव है। अभी तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति आरबीआई द्वारा अनुमोदित होती थी। जो लेखा परीक्षक नियुक्त होते थे,

क्योंकि सब प्रकार के रिकॉर्ड रखने का काम होता था। ह बिना आरबीआई के अनुमोदन के संभव नहीं था तथा इसका पारिश्रमिक आरबीआई द्वारा केन्द्र सरकार के परामर्श से ही दिया जाता था। अब इस संशोधन के बाद लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्वयं करेंगे, तभी बैंकों में प्रतिस्पर्धा, पारिश्रमिक प्रदान करने की सुविधा मिलेगी।

महोदय, बैंक सही प्रकार से ऑडिट करेंगे, इसका प्रावधान इसमें किया गया है। यह संशोधन यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि लेखा परीक्षकों को पर्याप्त रूप में पारिश्रमिक मिले, जिससे लेखा परीक्षकों के, मानकों और समग्र वित्तीय निगरानी में सुधार हो सके।

सर, हमारे विरोधी दल के अनेक वक्ताओं ने बहुत से विषयों पर चर्चा की है। कहा गया कि आखिरकार बैंक बिल में संशोधन की आवश्यकता क्यों है? मैं प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि देश के अंदर आज लोगों के जितने खाते खोले गए, जैसे कि चर्चा में बताया गया कि 54 करोड़ से अधिक जन-धन खाते खोले गए और 14 हजार करोड़ रुपये की धनराशि उन खातों में जमा हुई है। यह अपने आप में इस बात को सिद्ध करता है कि जब तक गुल्लक नहीं होगी, तब तक बचत नहीं होगी। कांग्रेस के शासनकाल में जनता को गुल्लक के अधिकार से वंचित किया गया था। मैं प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आज एक-एक बहन का खाता बैंकों के अंदर है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहनें उस खाते में जमा भी करती हैं और उसकी सुविधाएं भी उन्हें मिल रही हैं। बैंकों से लोन लेकर लोगों के भागने की चर्चा भी यहां हुई। यह भी बताया गया कि कितनी बड़ी संख्या में लोग भागकर गए हैं, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि जब से देश के अंदर प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, इस प्रकार से जो अपराधी हैं, वे किसी भी तरह से बच नहीं सकते हैं और इसका एक व्यवस्थित रूप है। अब केवाईसी के माध्यम से और अन्य तरीकों से व्यक्ति की पहचान होती है, तो स्वाभाविक रूप से यह होता है कि वह व्यक्ति कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा है, जिससे देश के अंदर उसके द्वारा बैंकों को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है।

महोदय, अब मैं मुद्रा लोन की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि यह एक बहुत बड़ी चीज़ है। बैंकों को आज किस गति के साथ जोड़ा गया है, इसको समझना पड़ेगा। मैं अभी अपने मित्रों के साथ बैठकर चर्चा कर रहा था कि एक स्थिति ऐसी आएगी कि शायद पैसा छपना ही बंद हो जाए और सारा लेन-देन बैंकों के माध्यम से हो। ऐसी स्थिति दिख रही है। हमारे कांग्रेस के एक मित्र कह रहे थे कि बैंकों में लाइन लग रही है। महोदय, आज तो बिजली का बिल ऑनलाइन जमा हो रहा है, मोबाइल कनेक्टिविटी का बिल ऑनलाइन जमा हो रहा है। एक-एक चीज़, जहां-जहां लाइन लगी होती थी, वहां लाइन लगना बंद हो गई है। इसमें बैंकों का बहुत बड़ा योगदान है। आज बैंकों के जितने भी सरकारी आयाम हैं, उन सारे आयामों को बैंकों से जोड़ा गया है और बैंक ने हर ग्राहक को हर जगह सुविधा दी है कि किसी भी प्रकार से उसको किसी भी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। यूपीआई की बार-बार चर्चा हुई है। महोदय, हम अपनी अर्थव्यवस्था को तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में लाने का प्रयास कर रहे हैं, इस दिशा में हमें इसका बड़ा लाभ प्राप्त होगा। आज की तारीख में हम सब लोग बैंकों की परिस्थितियों का अवलोकन कर रहे हैं। यह ठीक है कि विपक्ष का उद्देश्य सुझाव देना होता है और मैं इस बात को भी मानता हूं कि जितने सुझाव विपक्ष की ओर से आते हैं, तो हमारे देश के प्रधान मंत्री जी, हमारे देश की वित्त मंत्री जी द्वारा उन

सुझावों को देश हित में कैसे लागू किया जा सकता है, उसका उल्लेख हर बार बजट के अंदर किया है।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हर बार के बजट में बैंक के सुधार के कोई न कोई सुझाव निश्चित रूप से रहते हैं और उस दिशा में लोगों की आय भी बढ़ती है। महोदय, जब यह आय हर वर्ष बढ़ती है, तो उसका पैसा बैंक में जमा भी होता है। आज देश के अंदर इस प्रकार की परिस्थिति बन गई है कि दो नंबर का काम भी होता है। महोदय, मैं तो कई बार इसकी चर्चा करता हूं, बहुत लोगों ने नोटबंदी की चर्चा की है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि नोटबंदी का एक असर तो जरूर हुआ है। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग, जिनके पास अथाह लक्ष्मी माया होगी, उनके यहां आग लगी हुई है, क्योंकि वे पकड़े जा रहे हैं। महोदय, प्रधानमंत्री जी की आंखों में आज ऐसा चश्मा आ गया है कि उन्हें पता लगता जा रहा है कि किस घर में, कहां, कितना पैसा है। जब वे पकड़े जाने पर जेल के अंदर जाते हैं, तो बड़े-बड़े लोग अपने चेहरे छुपाते फिरते हैं। महोदय, आज देश के अंदर यह परिस्थिति बनी है। जो सरकारी पैसा है, सख्ती के साथ बैंक का वह पैसा बैंक के अंदर जाए। मैं मानता हूं कि नोटबंदी के समय बहुत से लोगों ने पैसा जमा नहीं किया होगा, पर अधिकतर लोगों ने एक-एक पैसा बैंक के अंदर जमा किया था और उसी का परिणाम रहा कि इतने खाते खुले और बैंकों के अंदर पैसे की धनराशि जिस गति के साथ जमा हुई, वह भी हमारे सामने एक उदाहरण है।

महोदय, बहुत से लोगों ने इस व्यवस्था पर अनेक प्रश्न खड़े किए होंगे। मैं जानता हूं कि विपक्ष का काम कुछ विषयों पर सुझाव देना होता है, इसलिए प्रश्न भी खड़े होते हैं, लेकिन उन प्रश्नों का आधार और समाधान केवल और केवल वित्त मंत्री जी कर सकती हैं।

महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी दिनों के अंदर हमने अपने प्रदेश और देश के अंदर जो बैंकिंग व्यवस्थाएं स्थापित की हैं, उनमें और गति के साथ सुधार करने होंगे। महोदय, बैंक के प्रति लोगों का विश्वास खड़ा हो, उस विश्वास के साथ हम सबको खड़ा होना है।

उपसभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं और अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं।

श्री उपसभापति: माननीय सदस्य, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री रामजी, आप अपना भाषण आरंभ कीजिए।

श्री रामजी (उत्तर प्रदेश)**:** उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे 'बैंकिंग लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2024' पर बोलने का अवसर दिया है। मैं इसके साथ ही अपनी पार्टी की मुखिया, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी आभार व्यक्त करता हूं।

मान्यवर, मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जैसे-जैसे हम टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे-वैसे हमारे सामने चैलेंजेस भी बढ़ते जा रहे हैं। मान्यवर, उसी क्रम में लगभग 30,000 करोड़ रुपये बैंकिंग फ्रॉड के रूप में भी देखने को मिले हैं। इसमें डिजिटल अरेस्ट, फेक एप्लीकेशन्स या ओटीपी के ज़रिए लोगों की गाढ़ी कमाई, खून-पसीने की कमाई फेक अकाउंट्स में जाती है और वहां से मल्टीपल ट्रांसफर होकर कहां गई, उसके बारे में मालूम नहीं होता है। महोदय, जब बैंकों में जाते हैं, तो वे बोलते हैं कि जिस अकाउंट

में गया, वह फेक अकाउंट है। महोदय, 3 से 4 करोड़ रुपये का टर्नओवर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में हो रहा है, लेकिन बैंक कहते हैं कि यह फेक अकाउंट है। महोदय, यह फेक अकाउंट आखिर करंट अकाउंट के रूप में कैसे खुला, इसकी भी जांच होनी चाहिए। करंट अकाउंट खोलने के लिए जब फिजिकल वैरिफिकेशन होता है, फार्म भरे जाते हैं, वहां चैक करने जाते हैं, तो ये एकाउंट्स कैसे खुल रहे हैं, यह एक गंभीर विषय है। मान्यवर, सरकार को इसका भी संज्ञान लेना चाहिए।

महोदय, इसके साथ ही जो साइबर क्राइम थाने बनाए गए हैं, उनमें जिन लोगों को बिठाया गया है, उन्हें आईटी के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। वे एप्लीकेशन लिख लेते हैं, एफआईआर लिख लेते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई हुई या नही हुई, उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होती है।

मान्यवर, अभी हमारे यहाँ पर एक केस हुआ है। हमारे गोरखपुर में श्री नवल किशन नथानी, जो हमारे जानने वाले हैं, उनका 40 लाख रुपया मल्टीपल ट्रांसफर हो गया। वे बैंक में गए, उन्होंने एप्लीकेशन दी कि फलां- फलां बैंक में आरटीजीएस से पैसा गया हुआ है, लेकिन बैंक ने कहा यह फेक अकाउंट है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकता। महोदय, आखिर यह फेक अकाउंट कैसे खुला था? जब उसमें, एक महीने में, दो महीने में 3.5 करोड़ रुपये का टर्नओवर हुआ, तब यह देखने वाला विषय है। मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी इस पर भी संज्ञान लें।

महोदय, मैं इसके साथ ही किसानों की बात करना चाहता हूं कि जिन किसानों की फसल बरबाद होती है, वह सूखे से बरबाद हुई, आग लग गई या हैवी बारिश हो गई, जिससे फसल बरबाद हो गई और किसान उसका लोन नहीं दे पा रहा, तब उस केस में बैंकों को कम से कम वहां पर वैरिफिकेशन करके उनका लोन माफ करने की भी जरूरत है।

मान्यवर, इसके साथ ही मैं सरकार से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वैसे मैं यह रिक्वेस्ट कई बार कर चुका हूं कि आप 'कृषि मजदूर सम्मान निधि' देने का भी काम करें। आपने 'किसान सम्मान निधि' दी है, यह एक सराहनीय कदम है, लेकिन जो रियल में इसके हकदार हैं, जो लोग पेस्टिसाइड डालते हैं, खेत में जाकर खून-पसीना बहाते हैं, गुड़ाई करते हैं, धूप में हर्बिसाइड डाल रहे हैं, इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं और बीमार भी हो रहे हैं, उन्हें 200-250 मिलते हैं, इसलिए आप उनके लिए 'कृषि मजदूर सम्मान निधि' लाने का भी काम करें।

माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि कई बार यह भी देखने को मिला है कि एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग के बच्चे, जो गरीब होते हैं, उनके एडमिशन्स नहीं हो पा रहे हैं। वे स्कूल्स, कॉलेजिज, आईआईटीज़ तक में एडमिशन्स लेने में असमर्थ हैं, इसलिए उनके लिए बैंक में यह प्रावधान करें कि उन्हें कम से कम जीरो फीस पर कंपल्सरी लोन मिलना चाहिए, ताकि वे ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद, अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद उस लोन को पूरा चुका सकें।

महोदय, मैं इसके साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि एससी/एसटी वर्ग के बच्चों को कई महीनों से स्कॉलरशिप्स नहीं मिली हैं, उन्हें कई सालों से एम.फिल. में पैसा नहीं मिला, इसलिए आप उस पैसे को भी देने का काम करें।

महोदय, मैं ओपीएस को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि इसको पूरे देश में कर्मचारी बार-बार मांग रखते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब सरकार 16 लाख करोड़ के आसपास का पैसा छोड़ देती है, कई साथियों ने बोला भी है कि जब बड़े-बड़े धन्ना सेठों का

पैसा राइट ऑफ किया गया, जब उनके इतने बड़े बजट का पैसा राइट ऑफ कर सकते हैं, तो इस देश में ओपीएस भी लागू कर सकते हैं। ...(**समय की घंटी**)...मान्यवर, मैं इसको लेकर भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। उपसभापति जी, मैं इन्हीं बातों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं, 'जय भीम, जय भारत'।

श्री उपसभापति: श्री मस्तान राव यादव बीडा, आप अपना भाषण आरंभ कीजिए। I am calling your name.

SHRI MASTHAN RAO YADAV BEEDHA (Andhra Pradesh): Sir, on behalf of my Party, Telugu Desam Party, and our hon. Chief Minister, Shri Nara Chandrababu Naidu, I stand here to speak on the reforms suggested under the Banking Laws (Amendment) Bill, 2024. The proposed Bill introduces three key Amendments aimed at enhancing the operational efficiency of the banking sector. The first Amendment addresses the issue of rising unclaimed deposits, which have surged by 26 per cent to Rs.78,000 crores, as highlighted by a recent RBI report. To tackle this challenge, the Amendment allows depositors to nominate up to four individuals, enabling both simultaneous and successive nominations. This simplifies the nomination process, reduces bureaucratic hurdles, and ensures that depositors' funds do not remain unclaimed or inaccessible. By prioritizing depositor convenience and protection, the Government has demonstrated its commitment to addressing evolving financial challenges.

The second Amendment focuses on enhancing investor protection by mandating the transfer of unclaimed dividends and shares. Although the IEPF reserve fund grew from Rs.83 crores in 2018-19 to Rs.86 crores in 2023-24, spending on investor education has declined. The third Amendment extends the tenure of directors in cooperative banks from eight years to ten years. This measure aligns with efforts in Andhra Pradesh to enhance the functioning of cooperative societies. The Andhra Pradesh Cooperative Societies (Amendment) Bill 2024, introduced by the State Legislative Assembly, seeks to improve the transparency, efficiency and overall management of cooperative institutions. By extending the tenure, the Amendment aims to ensure continuity and better governance, contributing to the long-term stability of cooperative banks. This Amendment reflects the unified functioning of the 'double engine sarkar.' Under the able leadership of hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, visionary Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman and visionary hon. Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Chandrababu Naidu, we are steadily building a prosperous and progressive India. The synchronized governance of this 'double engine sarkar' ensures that the vision of Swarna Andhra 2047 — a State

where people are happy, healthy and wealthy — contributes meaningfully to the larger goal of a *Viksit Bharat*. This Bill is yet another step towards robust governance, stronger financial systems and empowered citizens. I stand in full support of these reforms that pave the way for a brighter and more secure future for all. Jai Bharat, Jai Andhra Pradesh.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Praful Patel, not present. Shri Ravi Chandra Vaddiraju, in Telugu.

SHRI RAVI CHANDRA VADDIRAJU (Telangana): &Hon'ble Deputy Chairman Sir, I thank you for allowing me to speak on The Banking Laws (Amendment) Bill, 2024. I congratulate the Government on the introduction of this Bill, which is an important step towards modernizing our banking system and further strengthening the regulatory framework. It will help make the banking system strong, inclusive and efficient. The principal amendments contained in the Bill relate to the Reserve Bank of India Act, 1934, the Banking Regulation Act, 1949, the State Bank of India Act, 1955 and the Banking Companies (Acquisition and Transfer) Acts, 1970 and 1980. Substantial Interest Limit Increase: In section 5 of the Banking Regulation Act, the limit of Substantial Interest has been increased from 25 lakh to 22 crore. This change reflects the current economic realities and inflationary trends, as the previous threshold set in 1968 has become outdated. By updating this definition, the Bill ensures that the regulatory framework remains relevant and effective in today's context.Governance Reforms in Co-operative Banks: Extending the tenure of directors from eight to ten years under Section 10A of the Banking Regulation Act, 1949, and allowing directors of Central Cooperative Banks to serve on the boards of State Cooperative Banks under Section 16 are measures that acknowledge the complexities of cooperative banking. These changes will further strengthen the Co-operative Banking System.

Enhancement of Nomination Clauses: It will help in resolution of the nominee issues by providing an opportunity for depositors, bankers and depositors to file nominations under Sections 45ZA, 45ZC and 45ZE of the Banking Regulation Act, to allow depositors to appoint up to four nominees for bank accounts and lockers.

Investor Education and Protection Fund (IEPF): Under Section 38A of the State Bank of India Act, 1955, and similar provisions in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Acts of 1970 and 1980, the unclaimed

& English translation of the original speech delivered in Telugu.

funds are transferable to the Investor Education and Protection Fund (IEPF). I agree that this is a financially viable move.Sir, while there are many positive changes in this Bill, there are also challenges to address. Issues of Cyber Security: With the proliferation of digital banking, cyber attacks have become rampant. Between 2020 and 2024, 5,82,000 cyber fraud cases were reported, involving a loss of 23,207 crore. In 2024, there were 2.92 lakh cases and a loss of 22,054 crores. Maharashtra and Tamil Nadu have registered the highest number of cases. Telangana is leading the country in preventing the cybercrimes. During Shri KCR's tenure, a 1930 call centre was set up in the State, the first in the country to address cybercrime complaints, and has now been fully automated with an Interactive Voice Response (IVR) system to prioritize cases of financial fraud. This system ensures that urgent cases are attended to promptly, while non-financial complaints are directed to the national cybercrime portal.As of 2021, 78% of Indians have bank accounts, but 19 crore people are still unbanked. Cooperative banks and Regional Rural Banks (RRBs) should be strengthened in rural and backward areas. Telangana has 33 districts, 14,200 villages and 607 mandals. To achieve financial inclusion, expansion of digital banking, financial literacy training programmes and incentives for cooperative banks are needed.Credit facility for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs): MSMEs are the backbone of our economy, yet they often face difficulties in accessing affordable credit. The government and banks must work together to improve credit accessibility for MSMEs through government-backed credit guarantee schemes, lower interest rates, and simplified loan application processes.Sir, I would like to make the following recommendations to address these concerns. Government support to co-operative banks in Telangana and other States and expansion of banking services in rural areas: Banks should adopt modern cyber security systems and build systems based on AI and machine learning. MSMEs need to further simplify lending, lower lending rates and faster lending processes in public sector banks. There should be more focus on digital literacy and people in rural areas should be educated about banking.Regarding banking services for farmers in Telangana, the sector is functioning well. The likelihood of cyber fraud in the banking system here is minimal. Under the leadership of Shri KCR, we have established a robust system that ensures banking services are accessible to farmers, significantly supporting their financial growth. Initiatives such as Rythu Bandu and Rythu Bharosa have strengthened the banking sector in our State.Since the formation of Telangana, over the past ten years, seventy lakh individuals have received loans from banks. Each farmer has benefitted from a loan waiver of one lakh rupees. In contrast, the current Congress Government has only waived loans for fifty percent of those farmers in the

state who availed loan. Additionally, "Rythu Bhima" has been a groundbreaking scheme in the history of this country, implemented by Shri KCR. Under this scheme, if a farmer passes away for any reason, their family will receive a cheque of five lakh rupees within ten days, providing essential support during a difficult time. Shri KCR has continued to assist the families of deceased farmers through the Rythu Bheema Scheme even after their loss. Sir, once again, I would like to sincerely thank you for this opportunity.

श्री उपसभापति: धन्यवाद। श्री संजय कुमार झा जी।

श्री संजय कुमार झा (बिहार): आदरणीय उपसभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया है। मैं जानता हूँ कि इससे पहले जो सरकार थी, उस समय जिस हिसाब से लोन दिए जाते थे, उसके बारे में लोग बोलते थे कि फोन बैंकिंग चलती थी, फोन से ही लोन मिल जाता था, यह बड़े लोगों को मिलता था। मैं पिछला रिकॉर्ड देख रहा था कि जब बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया गया, तो बैंकों को 3,10,000 करोड़ रुपए दिए गए, जिससे वे वित्तीय संकट से निकल सकें। इसका एक जबर्दस्त प्रभाव पड़ा। मुझे लगता है कि बैंकों ने 2014 से अब तक 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की है। बैंकिंग क्षेत्र का खराब ऋण अनुपात अब 2.7 परसेंट के न्यूनतम स्तर तक पहुँच गया है, जो 2011 से सबसे कम है।
वित्त वर्ष 2023-24 में बैंकों को 3 लाख करोड़ से अधिक का लाभ हुआ है। इसी तरह मैं गांव में देखता था कि लोग साहूकारों से ही लोन लेते थे और बड़े rate of interest पर लोन लेते थे। जब गांव में banking system पहुँचा, तो मैंने यह देखा कि प्रधान मंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 54 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं, जिनमें से 56 परसेंट खाते महिलाओं के हैं। कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2.5 परसेंट की ऋण वृद्धि हुई है।

(**सभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहत 30 लाख करोड़ से अधिक का लोन वितरित किया गया है, जिसमें 68 परसेंट महिलाएँ हैं, जिनको यह मुद्रा लोन दिया गया है। प्रधान मंत्री स्वनिधि योजना के तहत 67 लाख से अधिक street vendors को ऋण प्रदान किया गया है, जिसमें 45 परसेंट महिलाएँ हैं, जिनको यह लोन मिला है। इसी तरह, मैं देख रहा था कि प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 47 करोड़ लाभार्थियों को दुर्घटना बीमा दिया गया है। प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 21 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर प्राप्त हुआ है।

महोदय, मैंने एक चीज देखी, जोकि phenomenal है, वह मैं आज की डेट में देख रहा हूँ। खासकर मैं यह अपने स्टेट में देखता हूँ, जहाँ cashless payment का, Cards का प्रचलन कम था, वह शायद urban centres में रहा होगा, पटना में रहा होगा, लेकिन मैं अब गांव में देखता हूँ कि किसानों द्वारा सब्जी बेचने पर, अनाज बेचने पर उनके account में ही पैसा transfer हो जाता

है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में digital लेन-देन का कुल volume 2,071 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़ कर 18,737 करोड़ रुपये हो गया है, तो इसमें 44 परसेंट की वृद्धि हुई है। UPI और RuPay, दोनों तेजी से वैश्विक स्तर पर फैल रहे हैं, जिससे भारतीयों के लिए विदेश में रहने और यात्रा करते समय सरल cross border भुगतान संभव हो पाता है। वर्तमान में 7 देशों में UPI live है, जिनमें यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरीशस हैं। Asia Worldwide Report, 2024 के अनुसार, 2023 में भारत में वास्तविक वैश्विक लेनदेन 49 परसेंट रहा है। महोदय, आज भारतीय बैंकिंग क्षेत्र केवल मजबूत ही नहीं हुआ है, बल्कि यह सामाजिक बदलाव का एक प्रतीक भी बन गया है। आज बैंकिंग सिर्फ एक वित्तीय प्रक्रिया ही नहीं है। लोग गांव में जो लोन लेते थे, उनको अब इन सब चीजों में direct access प्राप्त हुआ है और बैंक ऋण वृद्धि 60 परसेंट के उच्चतम स्तर पर पहुँच गयी है। बैंकों ने 5 लाख करोड़ से अधिक के ऋण वितरित किए हैं। मैं देख रहा था कि हमारे यहां एक बहुत बड़ी फोर्स है, जो जीविका दीदियों की है, जोकि self-help group के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। उसमें एक करोड़ से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं। आदरणीया वित्त मंत्री जी बिहार गई थीं। वे वहाँ दरभंगा-मधुबनी के एरिया में गई थीं। वहां पर उनका एक बड़ा कैंप लगा था, जहां खुद इन्होंने loan disbursement किया था। मुझे लगता है कि उस कार्यक्रम में जो महिलाएं आई थीं, उसमें 50,000 से ज्यादा का participation था। जिस स्केल का वह कार्यक्रम हुआ और जिस हिसाब से loan disbursement हो रहा है, इससे मुझे लगता है कि पहली बार बैंकों में transparency आई है। यह मुझे पहली बार दिखाई पड़ रहा है कि लोगों को accessibility मिली है और उनको लोन मिल जाता है तथा कम रेट पर लोन मिलता है। तो यह बैंकिंग सिस्टम गरीब के घर तक पहुँचा है, इसलिए मैं इस बिल के पक्ष में समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Hon. Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman, to reply to the discussion.

THE MINISTER OF FINANCE; AND THE MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, let me first thank you for coming over here, to become a part of this discussion, lead it from the Chair and unmindful of your requirement of rest and so on. I am indeed grateful for your presence.

MR. CHAIRMAN: Health and economy, sometimes, suffer similar challenges. We have to rise to the occasion.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I am indeed grateful that 24 Members of this House have participated in this debate. I would like to start from saying that in 2023-24 Budget, I had mentioned and I quote, "To improve bank governance and enhance investors' protection, certain amendments to the Banking Regulation Act, the Banking Companies Act and the Reserve Bank of India Act are proposed."

That was in the 2024 Budget. And, we are actually having taken a bit of time between the two House and also before presenting it to the Lok Sabha. We had worked on this Banking Amendment Bill, which is unique, at the same time, significant in some few ways. This is an Amendment Bill which is on eight different themes. I spoke about protection of bank account holders' interests and also simplification and so on. This particular Banking Laws (Amendment) Bill, Sir, will have an impact on five different Acts. It is unique in that sense and it is unique in eight different themes of Amendments; meaning, Amendments for one particular theme and Amendment for another particular theme, and so on. Eight different themes are being covered to attain the purpose which was stated in the Budget speech. Nineteen Sections in these five Acts will be touched. And, therefore, I want to, first of all say there are five Acts - the Reserve Bank of India Act, 1934, Banking Regulation Act, 1949, State Bank of India Act, 1955, the Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertaking Act of 1970, and the Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertaking Act, 1978. These are the five Acts on which the proposed Amendments will have an impact and they spread on eight different reasons as to why we are doing these. Before I get to specifics of what these Amendments are, I want to just place it on record, and also to recall the Members from their memory that from 2014, when our banks were under severe and excessive stress built up over several years, particularly, on the loan portfolios, they had reached a situation of crisis and our economy anyway had reached the fragile five position. So, in order to address the major banking crisis related matters, reforms were undertaken. We implemented the Enhanced Access and Service Excellence -- EASE. EASE was brought in the banks. We enacted the Insolvency and Bankruptcy Code in 2016. We also put in place a very robust banking governance framework. We set up the National Asset Reconstruction Company, the NARCL, and then we also undertook amalgamation of public sector banks. And, these are few of those significant steps taken to restore banks to good health. Sir, the outcomes are really there for all of us to see. The gross NPAs of Scheduled Commercial Banks were at a multi-year low of 2.5 per cent in September, 2024. So, those measures began from 2014. And today, September 24, that is, some months ago, the multi-year low level of gross NPAs of 2.5 per cent has already been reached. System level Capital to Risk-Weighted Assets Ratio, which is known as CRAR, of 16.7 per cent was also achieved in September, 2024. And, it is well above the regulatory minimum level, meaning if we had reached a certain level, that would have been sufficient. We improved on it and have bettered it. So, the steps taken under the leadership of the hon. Prime Minister in getting the banks to some kind of good health are showing results across various indicators which measure the

health of the banks. Public sector banks have also recorded the highest ever net profit of Rs.1.41 lakh crores in the previous financial year.

And, if that is the level at which they achieved net profitability in the previous year, I am confident that this coming year also, India's banks will attain even greater heights. Sir, even though the NPAs have reduced drastically, the Government has remained absolutely committed to taking stringent recovery action against wilful defaulters. The debate saw very many Members speaking about wilful defaulters going away from the country and that fugitive offenders and economic offenders have also left the country. What are we doing about it? I would give a brief remark now, but I will get into specifics when I address the specific Members who spoke about it. I have stated in this House several times that the write-offs do not mean a waive off by banks. I repeat that line, but, then, I will elaborate on what it means actually. Write-offs do not result in waiver of liabilities of borrowers, and, therefore, it does not benefit the borrower. So, it is not as if the written off is actually waived off resulting in benefiting those huge defaulters. Close to the end of the debate, we saw a Member, Shri Ravi Chandra Vaddiraju, who spoke in Telugu; and, I am grateful for the one line that he said. He said that under his Government, till recently which was ruling in Telangana, they have taken a lot of steps towards giving relief to the farmers like '*rinn maafi*' as it is known there. Actually, '*Rinn maafi*' under their Government had been very effective and they have taken care of farmers who were under severe indebtedness. I am glad he observed that. I am not commenting on or I have not anything to do with the '*rinn maafi*' of the TRS regime, as we would call it the BRS regime, but the one line that he mentioned was, "as different from the Congress's time when waiver was announced, '*rinn maafi*' was announced, but, actually, half the farmers did not even get it." It was an observation; it was in Telugu, right? Did you say that, Sir?

SHRI RAVI CHANDRA VADDIRAJU (Telangana): Yes, Madam.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: So, that is the point which all of us have been repeatedly saying. Announce '*rinn maafi*' or loan waiver, but you really do not do it; half the farmers are left without '*rinn maafi*' and the banks would put it on the record saying you have been covered under '*rinn maafi*' because the Congress Government had given that promise. And later, because under a one-time settlement your loans have been written off, the farmer is not even eligible for one more new loan. So, instead of serving the farmers, the Congress's notorious '*rinn maafi*' in 2008, by which we were told through the media that they won the election and came back in 2009,

that notorious *'rinn maafi'* had left many farmer neither here nor there. They were not sure whether they got the '*rinn maafi'* and if indeed the '*maafi'* was given, are they eligible to go ahead? No! You have a layer of small farmers looking up to the banks to give them some kind of a relief. So I want to highlight, like the way they speak about food security, like the way they speak about the MNREGA in the rural areas, none of the schemes brought by them was effectively implemented. And when the Prime Minister Modi*ji* implements them without corruption, without malpractice, and without any kind of wrongdoing, they would say, 'Oh! That is our scheme.' Yes, it was your scheme, but you kept it on paper or you mismanaged it. I have heard an hon. Member saying, 'as different from the way the Congress had given '*rinn maafi'*, our '*rinn maafi'* is better.' I would want to highlight the fact that deceiving the farmers is for nobody's good. If you really want to help the farmers, here is the Prime Minister Modi*ji* putting 2000 rupees every four months or annually 6000 rupees into their account through transparent DBT. Actually, it helps the small farmers. Show it in action, but do not put it as though it is a right which we have given to the farmers and, at the end of the day, farmers do not feel that the right has been given actually to them. So, I was very glad to hear that Member. I have gone much ahead; I would have spoken when I am responding to him. But that is the way the Congress's policies have all been big-time talk, but there is no action on the ground.And if there is action, it is ridden with corruption. Non-existing individuals get the waiver, get the benefit; others who deserve don't get it. So that is something which I want to mention. Thankfully there is another Party Member who is saying it, not me. So, Sir, the public sector banks have recorded the highest-ever net profit of Rs. 1.41 lakh crores in the last year. I am sure they will do it this year as well. So, I want to highlight the fact. Most often, they say 'fugitives'; they have run away with public money; small people are being harassed. No, small people should not be harassed. We are periodically, through the Reserve Bank of India, telling banks, telling our NBFCs, that you have no business to go and harass anybody. Yes, duly follow it up, but you can't threaten people or get into their house at ungodly hours and threaten them and so on. But with all what is said, that the rich borrowers are let to go-off, they run away from the country, etc., I want to give you this number, which we placed in this House during Question Hour also several times. The Enforcement Directorate has successfully restored properties valued at approximately Rs. 22,280 crores back to victims or legitimate claimants, where the ED has enforced its action and taken money away from the accused, or, those who are charged with these offences, with the Court's permission, and restored properties to the legitimate claimants. Again, for those of us who seem to think, 'Oh, ED is let loose; they are going on a political

vendetta', no, people's money is being given back; people's properties are being given back. This work is also being done by ED, and I want the hon. Members to recognise that. When they say, 'money is being taken away, big people are running away, only small people are being made to suffer', I want to tell that Rs. 22,280 crores, legitimately, through the process, getting the stamp from the court, is being sent to the due claimants. So, that work is got to be recognized.

Sir, further, we will also be focusing on a lot of structural reforms, but our efforts are not restricted only to that. We have deepened financial inclusion, took banking to the last citizen and ensured that citizen-centric banking is importantly served as an interface. Quite a few Members and the last speaker, Sanjay Jhaji, also spoke. Fifty-five crore Jan Dhan accounts have been opened. Over 55 per cent of them are women and 66 per cent have been in rural or semi-urban centered bank branches.

Sir, 'Global Partnership for Financial Inclusion' in its Financial Inclusion Action Plan Report which was published in 2023, says and, I quote, "By leveraging DPIs, Digital Public Infrastructure, India has achieved over 80 per cent bank account penetration, a journey that would have otherwise taken 47 years through traditional means." So this is a report which has been published somewhere else. They recognize the financial inclusion using DPI, and that actually is something which they have measured. Otherwise, if you followed the traditional methods of inclusion, it would have taken a lot of time. I heard the hon. Member, Shri Shaktisinh Gohil, talking about how the intention of nationalisation of banks was to reach the poorest of the poor to give them the financial inclusion. Well taken, Sir! But look at our grievance. As I said, in every one of the Acts, they claim, 'it is ours.' Rightly, they are 'theirs.' They introduced it. But in 47 years, what would have been otherwise achieved has been achieved through DPI in these 10 years; and that is why since nationalisation, although it was intended to take bank to the poorest to the poor, the results were not much to talk about. So that has to be recognized.

So, numerous steps have been taken for financial inclusion and it does not stop with merely banking the unbanked and instead enables meaningful engagement with financial services. Sir, this has been achieved primarily because there are two pillars of 'funding the unfunded' and 'securing the unsecured.' When I say, 'Funding the unfunded', 68 lakh street-vendors have been supported by PM SVANidhi.

There are more than 94 lakh PM SVANidhi loan accounts. There are 68 lakh street vendors who are supported by the scheme, but it also shows when people have graduated from the lower end of the loan, repaid it and graduated to be eligible for the upper end. Therefore, they have benefited even from that. So, 68 lakh street vendors

have benefited, but 94 lakh SVANidhi loan accounts have been recorded, in all the three tranches -- 10,000 in the first tranche, 20,000 in the second tranche and 50,000 in the third tranche.

The second point, Sir, is on funding the unfunded. Fifty crore loan accounts were sanctioned under the *PM Mudra Yojana*. Again, these are unsecured loans, but guaranteed by the Government. Talking about securing the unsecured, slightly over 47 crore enrolments have been done for accident insurance cover under the *PM Suraksha Bima Yojana*. Over 21.67 crore enrolments have been done for the life insurance cover under *PM Jeevan Jyoti Bima Yojana* and over seven crore subscribers for the *Atal Pension Yojana*. So, both funding the unfunded and securing the unsecured have taken place throughout these ten years.

Sir, talking about this Bill, I said there are five different Acts which will get impacted. I just want to tell you about those eight different themes which I said were being undertaken. Many Members have spoken about it in detail. So, I would not highlight too much of it. The current system is that every bank reports every Friday. That system has several limitations. So, the accuracy and effectiveness of reporting data is affected. Therefore, that is now being changed through one of the amendments so that it can be the last day of the fortnight, month or quarter, instead of being somewhere in between and asking to report on a Friday. Thus, that particular amendment will affect five different Sections of two different Acts. So, that is one of the things.

Sir, the second theme is on the interpretation of substantial interest. So, we are redefining substantial interest. Currently, it is either five lakh rupees or 10 per cent of the paid up capital. We retain the 10 per cent paid up capital. We are not changing that. Now, the definition of substantial interest was last touched in 1968. So, since 1968, it remains at five lakh rupees. Now we are enhancing it to two crores, but retaining the 10 per cent paid up capital for defining what substantial interest is. That is the second Section and hence the second theme.

Sir, the third theme is about the tenure of Directors excluding the Chairman and the whole time Directors. This is particularly relevant for the cooperative banks. Why do we at all need to do this? In the commercial banks otherwise, it is eight years and we are not doing anything about that. That is being retained. But the current system allows for cooperative banks to have their Directors only for maximum eight years. We want to align that with what is constitutionally provided for those cooperatives, which has not been, till now, thought through. The Constitution provides for cooperative banks' Directors to have a maximum term of 10 years. By limiting it to eight years, they have actually been denied what the Constitution

provides them. So, we want to now change that and align it with what the Constitution expects us to do. So, that will be 10 years, first five-year term and another five-year term. So, 10 years will be available for them.

Sir, the next one is about cooperative banks. The RBI's existing rule does not allow people in the cooperative banks to hold more than one position anywhere as Directors. Technically, the RBI can appoint Directors to more than one bank at any particular time. So, one person can be appointed in one, two or three banks, if the RBI does it, exceptionally.

But in cooperative banks, the same rule, which applies to regular banks, also applied that you can be in one place at a time only, whereas the system, through which people get elected in the cooperative movement, is that they first get elected at the lower rung, then they come to the middle rung and then they come to the State level. So, it is inevitable that they will have more than one position. So, we have to, from the light of the cooperative movement spirit, recognise that they can be in more than one place. So, that Amendment is being brought in. The fifth of the theme, out of the said eight themes, is about nominees on which many of the hon. Members have spoken. I think, it is important to recognize, in this day and age, that banks have a terrible problem if the nomination is not made or if it is wrongly made or if too many names being given for cash and FDs and so on. So, we have said, simultaneous nomination will be permitted for cash and for FDs, whereas for lockers and articles in safe custody, it can only be successive nomination. The option is given. These are already being used in insurance policies and so on. It is easier to handle claims; otherwise, it is very difficult for people to prove that they are the actual nominees and, therefore, this Amendment is being brought in. It has a bearing on nearly four Sections of different Acts. The other one is again applicability of interpreting 'Managing Director' and 'Deposit Insurance Corporation'. This is one of the omissions while drafting the previous Act, that is, Banking Amendment Act of 2020. In order to make up for what was oversight problem, they are now being brought in, namely, definition of 'Deposit Insurance Corporation' and definition of 'Managing Director'. Nothing new is being changed, but what was omitted inadvertently is being brought in. And, the transfer of unclaimed dividend is being brought in here. Currently, it is important for us to recognise that public sector banks have provisions for transferring unclaimed dividends to the Investor Education and Protection Fund. However, there are no provisions for transferring unclaimed shares, bond redemption and interest amounts to the IEPF. So, the proposed Amendment seeks to include these additional categories, ensuring that the unclaimed shares, bond redemption, interest amounts are also transferred to the IEPF. That is the

seventh. The eighth is on the auditor remuneration, which is fairly straightforward. So, I am not explaining that.

Now, I will come to individual hon. Members who have raised some issues. Hon. Member, Shri Shaktisinh Gohil, is not here. He has sent me a note saying, 'sorry; I won't be around'.

MR. CHAIRMAN: The hon. Member has sought my leave. He had to leave for some urgency.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I understand that. He has also sent me a written note saying he won't be around. But I want to address some of the concerns that he has raised. The issue of wilful defaulters is one thing which hon. Member, Mr. Gohil, has raised. He said, 'What action has the Government taken in such cases?' I just want to highlight a few things. As on 29-01-2025, if you look back at the last five years, as I said, the Directorate of Enforcement has taken up around 912 cases related to bank frauds, including those pertaining to wilful defaulters. In these cases, Rs. 44,204 crores of proceeds of crime has been attached, frozen or seized. In eight cases, assets amounting to Rs. 22,276 crores have been restituted to banks or to their legitimate claimants or victims of money laundering. 144 accused persons have been arrested; 239 prosecution complaints, including 66 supplementary PCs, have been filed before Special Courts; 23 accused persons have been declared proclaimed offenders and 9 have been convicted under the PMLA, that is, Prevention of Money Laundering Act.

So, this is about the Prevention of Money Laundering Act. Now, under the Fugitive Economic Offenders Act, about which several Members spoke, several actions have been taken against the economic offenders who have fled abroad. As of 31st December, 2024, nine individuals have been declared as 'fugitive economic offenders' and assets worth Rs.749.83 crores have been confiscated. So, action is going on relentlessly. We have not let it lie low.

The hon. Member, Shri Saket Gokhale, spoke about several issues. He is here. I have explained write-offs and waive-offs. I was surprised to hear it back again from Shri Saket Gokhale. Borrowers of written off loans remain liable to repay their dues. They are not let off. The banks continue to pursue recovery action in written off accounts using various mechanisms. They file suits in civil courts or the Debt Recovery Tribunals. Taking action under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act (SARFAESI), filing cases in the National Company Law Tribunal (NCLT) under the Insolvency and Bankruptcy

Codes, negotiated settlements or compromises with borrowers and selling non-performing assets to asset reconstruction companies are several such steps. So, the write-off mechanism is an established practice globally and does not absolve the borrowers of their liabilities. It enables banks to utilise their resources more effectively, even as they continue the recovery process.

As a result of these reforms implemented by the Government, performance of the public sector banks has significantly improved, and I repeat, the gross NPAs of the public sector banks have declined. Gross NPA ratio of the public sector banks now stands at 2.85 per cent in December 2024, from the peak gross NPA ratio of 14.58 per cent in March 2018. March 2018 was when you saw all those loans of prior to 2014 coming to be recognised as NPAs and action being started from then. That was the peak, and that peak was 14.58 per cent. But, today, that is, as on December 2024, the gross NPAs are 2.85 per cent. Pursuant action is showing results.

Capital adequacy ratio has improved to 14.84 per cent in December 2024 -- I am talking of provisional data -- from 11.66 per cent in March 2018. That is the high water mark for an ignominious NPA, but that is the high level it had reached. The PSBs recorded the highest ever aggregate net profit of Rs.1.41 lakh crore in 2023-24 and Rs.1.30 lakh crore up to December 2024. That is only for three quarters.

There is also this question about gold loans given by the NBFCs. I want to use the RBI data and say that gross NPAs in gold loans of the scheduled commercial banks and major NBFCs rose by around 18 per cent between March and June 2024. That is the data that the RBI has given. But it is important to note that the NPA ratio in gold loans still remains low. What is it? It is 0.22 per cent for gold loans alone. The gross NPA of all the public sector banks, which includes all kinds of NPAs, is 2.85 per cent, and if you were to look at the gold loans, it is only 0.22 per cent. The same thing is for the NBFCs, where 3.5 per cent is the gross NPAs, all of them for all types of portfolios, but on the gold loan part of it, the NPAs in NBFCs is 2.58 per cent only, compared to the 3.5 per cent overall for all portfolios. So, both the Reserve Bank of India and the Government have taken timely and targeted steps to address the issue and banks and NBFCs have been directed to strengthen appraisal practices, ensure proper gold valuation, comply with the LTV norms and take action in case of non-repayment, including gold auctions with due notices.

So, Public Sector Banks were also to conduct a comprehensive audit of gold loan portfolios to ensure full regulatory compliance. No major lapse has been reported. That is about the gold loans.

Penalty charges for non-maintenance of minimum balance was also an issue which hon. Member, Mr. Gokhale raised. Sir, this has been said several times in this House that no minimum balance is required for Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana accounts and, as such, no such penalty is charged on the 55 crore PM Jan Dhan Yojana accounts for not keeping minimum balance. This issue was also probably raised by hon. Member Raghav Chadha.

Sir, hon. Member, Shri K.R.N. Rajesh Kumar, spoke on a few issues. He said that the proposed nomination system is confusing. I want to say the current provisions of the Banking Regulation Act permits the nomination of only one person for the repayment of depositors' money, articles kept in safe custody and safety lockers and so on. This particular limitation has led to a lot of confusion and challenges, particularly, in cases where both the nominee and the account-holder or the locker-holder pass away, leaving the assets without any valid nomination. As a result, banks are sitting not knowing how to handle the situation. Such situations have created significant difficulties for legal heirs as well. So, when they are claiming their dues, even they face a lot of difficulty. In order to address these issues and enhance the service of the banks, this proposed amendment has been brought in. Depositors will still have an option for either successive or simultaneous nomination to be given, whereas for articles of safe custody and safety lockers, only successive nomination will be given, so that there is no confusion. Successive nominations ensure that if the first nominee is not available, the second nomination in line will become operative, maintaining continuity and reducing complication for the legal heirs.

Sir, he also raised the issue of the PSL shortfall. It is a clear indication that when there is a shortfall in PSL, it means that banks are effectively distributing the Priority Sector Lending, which is their duty. If they have not done it, then the amount which goes to the NABARD will be more, whereas if they have fulfilled the conditions and the PSL distribution is happening, then, obviously, the amount will be reduced which comes to the NABARD or let us say, SIDBI. So, it actually proves that the banks are achieving the target of 40 per cent PSL, which is the target given to them, and, therefore, if the money is reducing, it is because they are already using it well.

Sir, I am sure that the hon. Member, Raghav Chadha, sent you a note seeking your indulgence. He has given me a note expressing sorry for not being present during the reply.

SHRI RAGHAV CHADHA: I am here.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Oh, sorry. I did not notice.

MR. CHAIRMAN: And he did not send notice to me and I don't take cognizance if someone directly goes to the Executive.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Oh! You should have sent it to the hon. Chairman first.

MR. CHAIRMAN: So, hon. Member has created a difficult situation of sending a communication and yet being present.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Yes, Sir. But because he did not send it to you, वे डर के मारे आ गए। Sir, he raised the question of public grievances and grievance redress.

MR. CHAIRMAN: Hon. Finance Minister, one second. Hon. Members, it is now going to be 6.00 p.m. If the House so agrees, we may sit beyond 6.00 p.m. today till the disposal of the Banking Laws (Amendment) Bill, 2024.

Do I have the leave of the House to extend the sitting beyond 6.00 p.m. as indicated?

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: Hon. Finance Minister.

6.00 P.M.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, on the issue of grievance redressal, I want to say that there is a multi-layered grievance redressal resolution mechanism. Grievances related to banks and financial institutions can be lodged with the Centralised Public Grievance Redressal and Monitoring System, the CPGRAMS portal. As per the guidelines issued, the stipulated time limit for redressal of grievances on CPGRAMS is 21 days. An appeal mechanism is also available for unsatisfied petitioners with a disposal timeline of 30 days. To further strengthen this institutional framework, the Reserve Bank of India launched, in 2021, the Integrated Ombudsman Scheme, combining earlier ombudsman schemes for banks, NBFCs, digital transactions into a single streamlined system. Also, hon. Members, Shri

Raghav Chadha and Shri Niranjan Bishi had raised the issue of availability of banking infrastructure, particularly in the rural areas. I was amused, Sir, if you allow me a light-hearted exchange. If hon. Member, Shri Raghav Chadha, does not take offence, I would like to say that he observed the number of fans in the banks, number of fans which are working, the bank and its condition, how many whitewashed, how many not painted. I am really so, so satisfied. There are Members of Parliament who are otherwise very busy with many things, international, have found time to go to the rural banks and to look at them, to say there is no fan here, there is no door here, there is no chair here. Raghav Chadha ji, please do more of this. It will help people within the country because with your exposure, particularly to the western world, you can do a lot more here. Please do. So, I was very amused, Sir.

MR. CHAIRMAN: Hon. Finance Minister, you have been very mild. You have been absolutely mild. I have seen changes in Shri Raghav Chadha recently, in several aspects. I don't want to share that with the Finance Minister. That should be okay. Hon. Finance Minister.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, banking network in India has actually grown significantly, with 42,511 branches of scheduled commercial banks added till September 24, taking the total number of branches to 1,65,501 as of September 2024. Of these, 85,116 branches belong to the public sector banks. The distribution of these branches, as of September 2024, is as follows. 30,539 branches are in metro areas. 55,372 branches are in rural areas. 45,314 branches are in semi-urban areas. And 29,276 branches are in urban areas proper. Sir, 99.88 per cent of the 6,01,328 inhabited mapped villages are covered by financial infrastructure, ensuring a banking touch point. That is, a bank branch itself, brick and mortar, business correspondent or an India post payment bank centre are all within the five kilometre radius of these villages. So, 6,01,328 inhabited villages are mapped and of these, 99.88 per cent of them have at least a bank touch point, be it a banking correspondent or a branch. Sir, on cyber security, again, quite a few Members asked questions. Raghav Chaddhaji asked, Niranjan Bishiji asked. I want to say, I am sure this information is available, that the Indian Cyber Crime Coordination Centre, I4C, under the Ministry of Home Affairs, serves as a national nodal point for coordinated efforts to tackle cyber crimes, including financial frauds. Cyber Fraud Mitigation Centre operates in collaboration with major banks, payment intermediaries, telecom service providers and the law enforcement agencies to address and prevent financial cyber frauds effectively.

The National Cybercrime Helpline 1930 operational 24x7 across all States and Union Territories has been established to ensure immediate reporting and redressal of financial cybercrimes. The Digital Intelligence Platform (DIP) developed by the Department of Telecommunications ensures real-time coordination among stakeholders, including telecom service providers, financial intermediaries and law enforcement agencies. I am told there is a Chakshu facility on Sanchar Saathi Portal which empowers citizens to report fraudulent communication such as spam calls and phishing attempts, enhancing public vigilance and fraud prevention efforts.

Sir, next is the point raised by the hon. Member, Shri Haris Beeran. I have just one more after this. I will not take much of your time. The hon. Member, Shri Haris Beeran, asked why five separate Acts are being amended in a single legislation. I tried saying that even in my opening statement. But the Banking Laws (Amendment) Bill which has been brought in now includes amendments to multiple banking legislations to address interlinked and consequential issues effectively. Instead of going one by one to all these Acts, we are doing it in one go because the intent and the objectives across the board are common. So, shifting of submission timelines for statutory reports in both the RBI Act and the BR Act is being addressed through this single Bill. Transfer of unclaimed dividends, shares and redemptions is also another one which touches on three Acts. Addressing all of these in one Bill ensures consistency, avoids duplication and also achieves a cohesive regulatory framework for the entire banking sector. That is the reason why we have taken up this route.

Sir, the last one which I would like to take up is from the hon. Member, Dr. V. Sivadasan. He spoke about quite a few issues, particularly about bank employees. I would like to say that the Inter Bank Association (IBA) signed the 12th Bipartite or the 9th Joint Note on 8.3.2024. This is the point which I would like to repeat any number of times. And I will say it here. Since 1992, when five-year bipartite agreements started, this time, agreement has been signed within 14 months. Earlier, the average delay would be 30 months. We completed it in less than half that time. In respect of increase in salary and allowances for serving employees of banks, there will be an overall increase of 17 per cent in salary and allowances of the annual placed expenses for 2021-22 which will be Rs.12,449 crore for all public sector banks. Out of this, 17 per cent and 3 per cent will be loaded onto the basic pay and the remaining will be distributed in the form of Other Allowances. New pay scales will be calculated after merging the DA with the basic pay as on 31.10.2022 and adding thereon a loading factor of 3 per cent. That is about serving employees. For pensioners, monthly *ex gratia* payment has been considered in addition to pension for the pensioners and

family pensioners as a one-time measure and will be applicable to current settlement period itself.

Now I come to third major thing. There are several other issues. The 12th BPS and residual issues of the 11th BPS, which are old legacy issues, all of them have been handled. The pre-1986 *ex gratia* payment to retirees and their families has been increased. The *ex gratia* payment for retirees was Rs.4,946 and the *ex gratia* payment for the families was Rs.2,478. They were getting only that. These have now been increased to Rs.10,000 per month in both the cases.

So, where you were getting only Rs. 2,478, you are getting Rs. 10,000; where you were getting Rs. 4,946, you are getting Rs. 10,000 per month now. That is for pre-1986 retirees. This will benefit 105 retirees, who are still living from that time and who are elderly super senior citizens, and 1,382 spouses of those people who had served the banks. Total additional cost is Rs. 4.73 crore per annum. It is implemented since February, 2023. Second point is, 100 per cent DA neutralization to pre-2002 retirees and *ex gratia*. Total additional cost is Rs. 631 crore per annum. Total beneficiaries will be 1,81,805 persons; to them, DA neutralization is being offered. It is implemented since October, 2023. Then, there is option to resignees, which was earlier not taken up for people, who were otherwise eligible to join pension scheme. Total additional cost on this ground is Rs. 135 crore per annum. This will benefit approximately 3,198 persons. That is also achieved. So, IBA has done this work keeping in mind the bank employees, their families, pensioners and retirees. The last point about Dr. Sivadasan's comment is, creation of and increasing the Chief General Manager positions in Nationalized Banks. I am talking about positions; I am also talking about jobs; I am also talking about vacancies which are getting filled up. We have taken a step which will enable banks to have better control and supervision, improved asset management and operational efficiency. With this revision, the number of CGM posts in all the 11 Nationalized Banks has been increased from 80 to 144. It means, people are moving up the pyramid; we are filling up those positions which are getting vacated; so, more people are coming in. Accordingly, the number of GM posts has also been revised from 440 to 576; the number of DGM posts are increased from 1,320 to 1,728; and, the number of AGM posts are increased from 3,960 to 5,184. So, I want to underline the point that a total of 1,832 posts have been created in the positions. Therefore, as a result of these steps, not only people are being allowed to go up in the ladder, new positions are also being created. It is said that jobs are not being created! Hon. Member, Dr. Sivadasan, it is being created and people are being moved upwards as well. Promotional opportunities are also increasing in banks. So, thank you very much for giving me this opportunity.

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, Dr. Sivadasan, has a point. Hon. Finance Minister, only the point of Dr. Sivadasan. ...(*Interruptions*)... Otherwise, it will be endless.

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Sir, my point is that thousands of persons are working in our banks as contract workers. So, reservation is not there. Also, because of the vacancies, they are working there as contract workers. Does the Government have any plan to fill up these posts? There may be creation of top posts like the posts of General Manager and others. But, thousands of posts are vacant. ...*(Interruptions)*...
MR. CHAIRMAN: Okay. One minute! What is your point of order?

SHRI TIRUCHI SIVA: It is under Rule 261. It says that if the Chairman is of opinion that a word or words has or have been used in debate which is or are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified, he may, in his discretion, order that such word or words be expunged from the proceedings of the Council. I did not want to interrupt her during the course of her speech. It was in good flow. During her reply, she said, "Congress Party's 2008 notorious loan waiver". 'Notorious' is unparliamentary word. Kindly expunge it.

MR. CHAIRMAN: I will look into the matter whether it is unparliamentary or not. ...*(Interruptions)*... Let me again look at it. Hon. Finance Minister, one particular Member, Shri Shaktisinh Gohil, had raised one issue that communications emanating from the hon. Member of Parliament did not evoke even a response from the concerned institution. Prestige of a Member of Parliament is fundamental to this House. If a Member of Parliament does not get prompt adequate response, the dignity of the House is also compromised. I recollect my days in 1990 when I was a junior Minister and the problem then was also the same. Some exemplary initiative will have to be taken by the Government to sensitize one and all that if there is no response to a communication of a hon. Member of Parliament, visitation will be of exemplary consequences. And I am sure, several directives, that are already issued in this, remain yet to be complied, if I go by what the hon. Member, Shri Shaktisinh Gohil, has said. I am sure, as a senior Minister, you will take steps and accordingly sensitize the administration.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sure, Sir. I would do that. If you will permit me, just one more thing which hon. Member, Dr. Sivadasan, said about jobs: "It is alright, you are creating GM's posts and other things." No, it is not just that. We

have created 3.94 lakh of jobs since 2014. 3.94 lakh of jobs only in public sector banks! They are of different cadres and different levels. State Bank of India alone has created 94,000 jobs, 41,000 jobs by Bank of Baroda, 36,000 jobs by Bank of India, 7,000 jobs by Bank of Maharashtra, 54,000 jobs by Canara Bank -- I am rounding off the numbers — 15,000 jobs by Central Bank of India, 21,000 jobs by Indian Bank, 7,000 jobs by Indian Overseas Bank, 55,000 jobs by Punjab National Bank, 8,000 jobs by Punjab and Sindh Bank, 13,000 jobs by UCO Bank and Union Bank of India has created 38,000 jobs. I have rounded up the figures but it is 3.94 lakh jobs since 2014.

MR. CHAIRMAN: So, hon. Finance Minister, you are the beneficiary. When I reflected on the prestige of Members being sustained and, therefore, you need to take pro-active steps now in that direction.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Obviously, Sir.

MR. CHAIRMAN: Zero tolerance with your Ministry and sensitize others also.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sure, Sir.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill further to amend the Reserve Bank of India Act, 1934, the Banking Regulation Act, 1949, the State Bank of India Act, 1955, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Banking Companies (Acquisition of Transfer of Undertakings) Act, 1980, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 3, there are three Amendments: Amendment (No. 3) by Shri A.A. Rahim, Amendment (No. 6) by Dr. John Brittas and Amendment (No. 11) by Dr. V. Sivadasan. Shri A. A. Rahim, are you moving the Amendment?

SHRI A.A. RAHIM (Kerala): Sir, I move:

3. That at page 2, line 29, *for* the words "two crore rupees", the words "fifty lakh rupees", be *substituted.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. John Brittas, are you moving the Amendment?

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I move:

6. That at page 2, lines 29 to 31, the words "or such other amount as may be notified in the Official Gazette by the Central Government", be ***deleted.***

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. V. Sivadasan, are you moving the Amendment?

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Sir, I move:

11. That at page 2, lines 29 to 31, *for* the words "two crore rupees or such other amount as may be notified in the Official Gazette by the Central Government", the words "one crore rupees", be *substituted.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendments moved.I shall first put Amendment (No. 3) moved by Shri A.A. Rahim to vote.

The question was put and the motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No.6) moved by Dr. John Brittas to vote.

The question was put and the motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No.11) moved by Dr. V. Sivadasan to vote.

The question was put and the motion was negatived.

Clause 3 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is one Amendment (No. 7) for insertion of a New Clause 3A by Dr. John Brittas. Are you moving the Amendment?

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I move:

7. That at page 2, *after* line 31, the following new clause be *inserted*, namely,-

"3**A**. In the Banking Regulation Act of 1949, in section 5, in clause *(ne)*, after the words "minor child", wherever they occur, the words "or father or mother", shall be inserted".

The question was put and the motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 4, there are four Amendments; Amendment (No. 4) by Shri A.A. Rahim, Amendment (No. 8) by Dr. John Brittas, Amendment (No.12) by Dr. V. Sivadasan and Amendment (No.17) by Shri M. Shanmugam. Shri A.A. Rahim, are you moving the Amendment?

SHRI A.A. RAHIM (Kerala): Sir, I move:

4. That at page 2, lines 32 to 34, be *deleted*.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. John Brittas, are you moving the Amendment?

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I move:

8. That at page 2, lines 32 to 34, be *deleted*.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. V. Sivadasan, are you moving the Amendment?

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Sir, I move:

12. That at page 2, lines 32 to 34, be *deleted*.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri M. Shanmugam; not present. I shall first put the Amendment moved by Shri A.A. Rahim to vote.

The question was put and the motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Amendment moved by Dr. John Brittas to vote.

The question was put and the motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Amendment moved by Dr. V. Sivadasan to vote.

The question was put and the motion was negatived.

Clause 4 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 5, there are three Amendments; Amendment (No.5) by Shri A.A. Rahim, Amendment (No.13) by Dr. V. Sivadasan and Amendment (No.18) by Shri Sandosh Kumar P. Shri A.A. Rahim, are you moving the Amendment?

SHRI A.A. RAHIM (Kerala): Sir, I move:

5. That at page 2, lines 35 to 38, be *deleted*.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. V. Sivadasan, are you moving the Amendment?

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Sir, I move:

13. That at page 2, lines 35 to 38, be *deleted*.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Sandosh Kumar P, are you moving the Amendment?

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Sir, I move:

18. That at page 2, lines 35 to 38, be *deleted*.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall first put the Amendment moved by Shri A.A. Rahim to vote.

The question was put and the motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Amendment moved by Dr. V. Sivadasan to vote.

The question was put and the motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Amendment moved by Dr. Sandosh Kumar P to vote.

The question was put and the motion was negatived.

Clause 5 was added to the Bill.

Clauses 6 to 13 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 14, there is one Amendment (No.9) by Dr. John Brittas. Are you moving the Amendment?

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I move:

9. That at page 5, lines 13, for the words and bracket, "clause (*nb*)", the words and bracket, "clauses (*h*) and (*nb*)", be *substituted*.

The question was put and the motion was negatived.

Clause 14 was added to the Bill.

Clause 15 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 16, there is one Amendment (No.14) by Dr. V. Sivadasan. Are you moving the Amendment?

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Sir, I move:

14. That at page 6, line 15, *for* the words "the State Bank", the words "the Reserve Bank", be *substituted*.

The question was put and the motion was negatived.

Clause 16 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 17, there are two Amendments. Amendment (No.10) by Dr. John Brittas and Amendment (No.15) by Dr. V. Sivadasan. Dr. John Brittas, are you moving the Amendment?

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I move:

10. That at page 6, lines 26 to 28, be *deleted*.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. V. Sivadasan, are you moving the Amendment?

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Sir, I move:

15. That at page 6, lines 26 to 28, be *deleted*.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendments moved. I shall first put the Amendment moved by Dr. John Brittas to vote.

The question was put and the motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Amendment moved by Dr. V. Sivadasan to vote.

The question was put and the motion was negatived.

Clause 17 was added to the Bill.

Clause 18 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 19, there is one Amendment (No.16) by Dr. V. Sivadasan. Are you moving the Amendment?

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Sir, I move:

16. That at page 7, lines 18 to 20, be *deleted*.

The question was put and the motion was negatived.

Clause 19 was added to the Bill.
Clause 20 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 1, there is one Amendment (No.2) by Shrimati Nirmala Sitharaman. Are you moving the Amendment?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I move:

2. That at page 1, line 5, *for* the figure, "2024", the figure, "2025" be *substituted.*

The question was put and the motion was adopted.
Clause 1, as amended, was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In the Enacting Formula, there is one Amendment (No.1) by Shrimati Nirmala Sitharaman. Are you moving the Amendment?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I move:

1. That at page 1, line 1, *for* the words, "Seventy-fifth", the words, "Seventy-sixth" be *substituted.*

The question was put and the motion as adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.
The Title was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shrimati Nirmala Sitharaman to move that the Bill, as amended, be passed.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I move:

"That the Bill, as amended, be passed."

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet at 11.00 a.m. on Thursday, the 27th March, 2025.

The House then adjourned at twenty-nine minutes past six of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 27th March, 2025.